फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 01:52 उपरांत द्वितीया विक्रम संवत 2082

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

अमृत विचार

बरेली

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण

लखनऊ ▪ बरेली ▪ कानपुर ▪ मुरादाबाद ▪ अयोध्या ▪ हल्द्वानी

सोमवार, 2 फरवरी 2026, वर्ष 7, अंक 69, पृष्ठ 16 ▪ मूल्य 6 रुपये

आम बजट 2026-27

अहम बातें

एमएसएमई : ग्रोथ फंड बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एलान

एफएंडओ पर एसटीटी 0.02 से 0.05 फीसदी की गई

17 कैंसर की दवाएं व 7 दुर्लभ बीमारी की दवाएं होंगी सस्ती

नए संस्थान, हॉस्टल और यूनिवर्सिटी टाउनशिप

नौकरियां, कौशल और बेहतर अस्पताल को मिलेगा बढ़ावा

किसानों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें टेक सपोर्ट देगी सरकार

बैंकिंग और निवेश में सुधार पर फोकस

इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

7,84,678	2,77,830	1,39,289	1,06,530	2,55,233
रक्षा	रेलवे	शिक्षा	स्वास्थ्य	गृह मंत्रालय

सभी राशि करोड़ रुपये में

टैक्स वही, सोच नई

53.5 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्री ने किया पेश

बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किसानों और युवाओं पर फोकस

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने के साथ मेगा टेक्सटाइल पार्क किए जाएंगे विकसित

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15% बढ़ाया 2047 तक ग्लोबल लीडर बनने का लक्ष्य

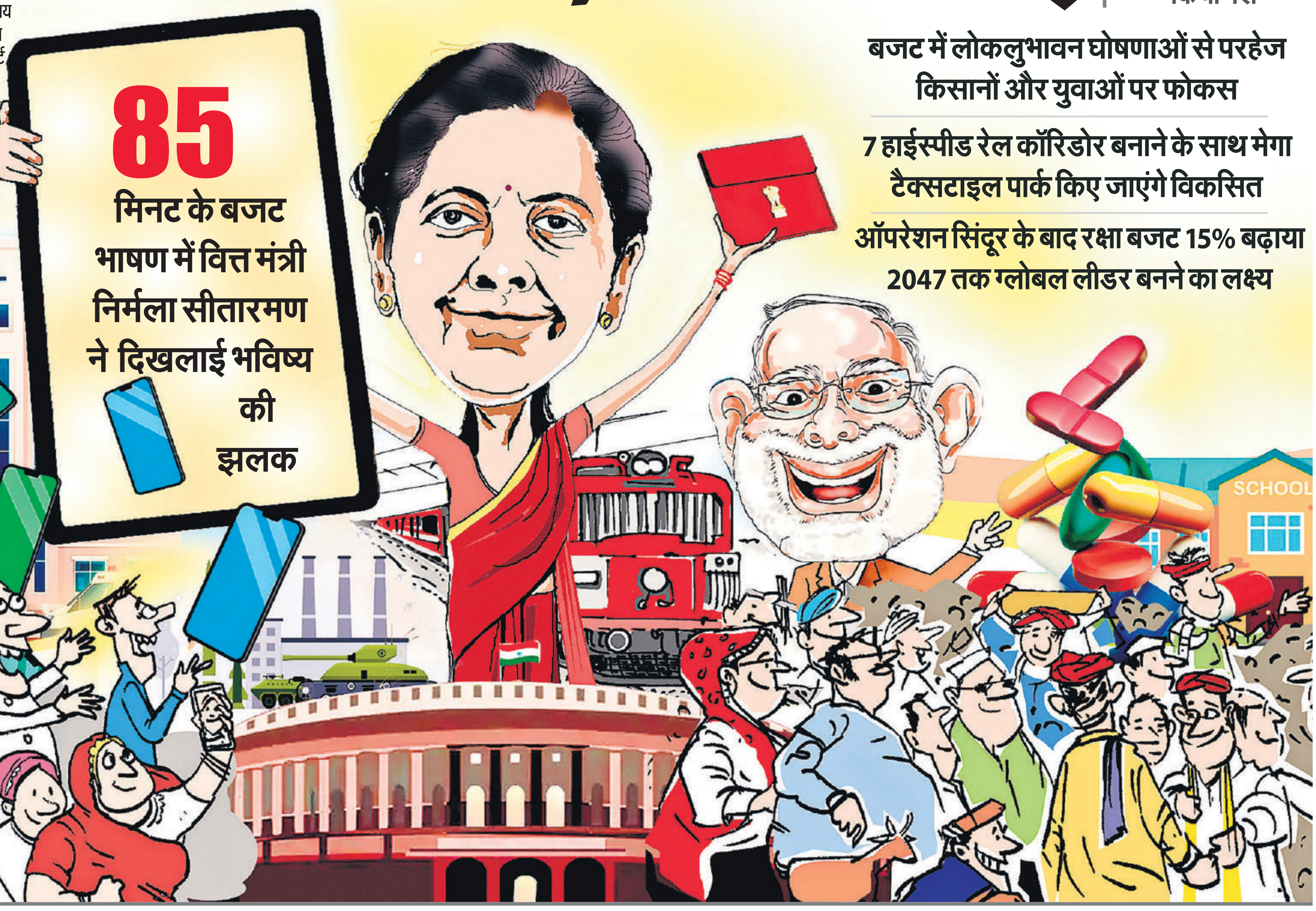

यह हुआ महंगा

- इनकम टैक्स में गलत जानकारी देना : टैक्स की रकम के 100% के बराबर पेनल्टी
- चल संपत्ति का खुलासा न करना : अब इस पर पेनल्टी लगेगी
- स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर्स ट्रेडिंग : सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया
- छाते और उनके पार्ट्स पर 10 प्रतिशत या 25 रुपये प्रति किलो (जो भी ज्यादा हो) ड्यूटी लगेगी
- शराब, मिनरल्स और स्क्रैप की बिक्री पर टीसीएस अब 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2% की
- क्रैनबेरी पर ड्यूटी 5 प्रतिशत और ब्लूबेरी पर 10 प्रतिशत कर दी गई है
- पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड पर ड्यूटी अब शून्य से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दी गई है।
- चबाने वाला तंबाकू, जर्दा और गुटखा पर एनसीसीडी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 कर दिया

सस्ती हुई चीजें

- माइक्रोवेव ओवन के खास पार्ट्स पर अब बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं
- चमड़े के निर्यात में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास इनपुट्स को ड्यूटी-फ्री आयात की सुविधा
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी माफ
- सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर कस्टम ड्यूटी हटी
- न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आयात किए जाने वाले सामान पर 2035 तक कस्टम ड्यूटी माफ
- एविएशन सेक्टर के पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी माफ
- विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस की दर 5–20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर की गई
- विदेश में पढ़ाई के खर्च पर एलआरएस के तहत अब कम टीडीएस लगेगा।
- एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ
- फ्रोजन टर्की मांस और खाने योग्य ऑफल पर टैरिफ 30 से घटाकर 5 प्रतिशत
- आर्टेमिया सिस्ट और कैंसर की कुछ दवाओं पर टैरिफ 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित पांच प्रमुख राज्यों में चुनाव करीब होने के बाद भी उन्होंने लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज रखा। साथ ही सुधार एक्सप्रेस को जारी रखते हुए वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट और कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने संसद में कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। छोटे उद्यमों एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। अब तक के सर्वाधिक 12.22 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ इस बजट को बढ़ते वैश्विक जोखिमों के बीच वृद्धि को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा के रूप में देखा जा रहा है। सीतारमण ने छूट को युक्तिसंगत बनाकर सीमा शुल्क व्यवस्था को सरल बनाया है। इसके तहत 17 कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। बैगेज नियमों में ढील के साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

छोटे उद्योगों के साथ कृषि, पर्यटन क्षेत्रों पर जोर

नई दिल्ली। निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए वैश्विक अनिश्चितता के बीच बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर को बनाए रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया जो पिछले वित्त वर्ष में 11.2 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि सरकार सात क्षेत्रों औषधि, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ-खनिज चुंबक, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र और खेल सामग्री में विनिर्माण को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देगी। साथ ही, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास पर भी जोर दिया जाएगा। बजट में पशुधन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए भी कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई। वहीं भारत को जैव-औषधि विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। कपड़ा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्गों के विकास के साथ-साथ 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास का भी प्रस्ताव किया गया। लघु उद्यमों को बढ़ावा देने और भविष्य के 'चैंपियन' तैयार करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई वृद्धि कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करने की बात कही गयी है। बजट में घोषित उपाय पिछले वर्ष आयकर में छूट और जीएसटी कटौती के पूरक हैं। इन उपायों ने बुनियादी ढांचे पर खर्च, श्रम कानून में सुधार और रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती के साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत के शुल्क का सामना करने में मदद की है।

वित्त मंत्री ने बताए 3 कर्तव्य

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सरकार का विकास रोडमैप सामने रखा। उन्होंने तीन मूल कर्तव्यों गिनाए।

- **आर्थिक ग्रोथ :** सरकार का पहला कर्तव्य है भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज रखना। वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकार का लक्ष्य है कि वृद्धि दर को लगातार ऊंचा रखा जाए।
- **जनता की उम्मीद :** दूसरा कर्तव्य है जनता की उम्मीदों और उनके भरोसे पर खरा उतरना। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, युवाओं के अवसर, महिला सशक्तिकरण और रोजगार ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार बजट के जरिए सीधे राहत देने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।
- **सबका साथ, सबका विकास :** सरकार का तीसरा कर्तव्य है विकास को सबके लिए समान और सुलभ बनाना। सीतारमण ने कहा कि किसी भी नीति या योजना का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे।

एसटीटी बढ़ोतरी से बाजार धराशायी, सेंसेक्स 1,547 अंक टूटा

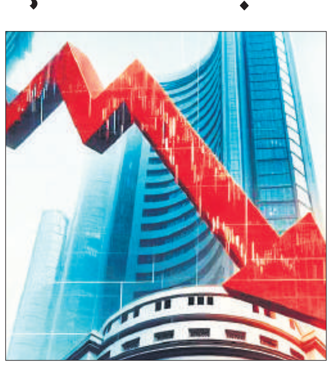

मुंबई। वायदा सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने की केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद रविवार को घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,547 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी 495 अंक टूटकर बंद हुआ। मार्केट में भारी बिकवाली के दबाव में निवेशकों के 9.40 लाख करोड़ रुपये डूब गए। विश्लेषकों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में सौदों पर एसटीटी को बढ़ाने का ऐलान बाजार को पसंद नहीं आया और यह बहुत तेजी से नीचे चला गया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती बढ़त गंवाते हुए दोपहर के कारोबार में 2,370.36 अंक यानी 2.88 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 80,000 अंक के अहम स्तर से भी नीचे फिसलकर 79,899.42 अंक पर खिसक गया था।

● सात साल में सबसे बड़ी गिरावट, वित्त मंत्री बोलीं- सट्टेबाजी को रोकना है मकसद, निवेशकों के 9.40 लाख करोड़ डूबे

हालांकि, बाद में सेंसेक्स थोड़े सुधार के साथ 1,546.84 अंक यानी 1.88 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,722.94 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 495.20 अंक यानी 1.96 प्रतिशत गिरकर 24,825.45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 748.9 अंक यानी 2.95 प्रतिशत लुढ़ककर 24,571.75 अंक के निचले स्तर तक चला गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) धीरज रेल्ली ने कहा, एसटीटी में प्रस्तावित बढ़ोतरी अल्पावधि में पूंजी बाजार से जुड़ी इकाइयों के लिए दबाव बना सकती है, हालांकि दीर्घावधि में इसके सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं।

140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं वाला बजट

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है तथा विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है। मोदी ने कहा कि बजट में अवसरों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बजट में देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। सीतारमण ने लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा की नींव है। इस वर्ष का बजट भारत की सुधार एक्सप्रेस को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। भारत केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं है और यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है।

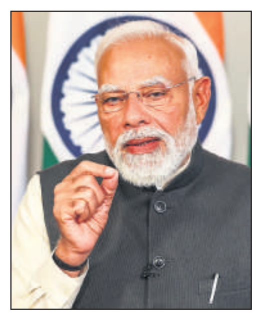

विकसित भारत के निर्माण का प्रेरणादायी संकल्प-पत्र

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह विकसित भारत के निर्माण का एक प्रेरणादायी संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा यह बजट युवाओं को अवसर, किसानों को सुरक्षा, उद्यमियों को प्रोत्साहन, मध्यम वर्ग को राहत और श्रमिकों को सम्मान प्रदान करेगा। योगी ने कहा यह बजट नवाचार, विनिर्माण और रोजगार को नई गति देने के साथ ही कृषि, ग्रामीण विकास, अवसंरचना, पर्यटन, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को सशक्त बनाते हुए 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को साकार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एमएसएमई, स्टार्टअप और स्वदेशी उत्पादन को समर्थन देकर 'आत्मनिर्भर भारत' की नींव को और सुदृढ़ किया गया है।

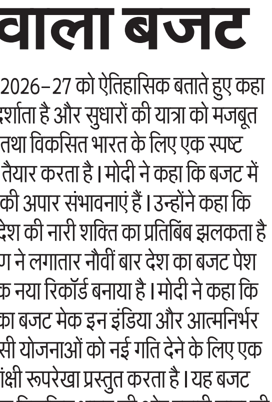

वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.3 प्रतिशत रहेगा जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 4.4 प्रतिशत से कम है। कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में राज्यों को कर हस्तांतरण राशि के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये प्रदान करेगी जबकि शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा (सरकारी व्यय और आय के बीच का अंतर) सकल घरेलू उत्पाद (जीडपी) का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

आयकर में नहीं मिली राहत स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले जैसा

अमृत विचार, बजट डेस्क

केंद्रीय बजट में आमजन की टैक्स से जुड़ी उम्मीदों के मुताबिक, कोई ऐलान नहीं हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। लोगों को आशा थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया था। इसके मुताबिक 12 लाख रुपये सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना था। यही सीमा अब 2026-27 में भी लागू रहेगी। इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी पूर्व की भांति 75 हजार ही रहेगा। ऐसे में मिडिल क्लास के हाथ खाली रह गए।

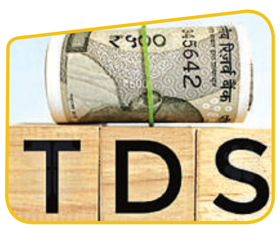

टैक्स में कुछ इन छूट का भी ऐलान

- वित्त मंत्री की बजट घोषणा के अनुसार अब किसी मोटर एक्सीडेंट क्लेम के तहत तय ब्याज को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। इस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। लेबर सर्विस को टीडीएस के तहत लाने का प्रस्ताव किया गया है और इन सेवाओं पर 1 से 2 फीसदी की टीडीएस कटौती हो सकती है।

छोटे करदाताओं को राहत

वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है. अब आईटीआर फाइल करने पर कम या जीरो टैक्स कटौती सर्टिफिकेट ले सकेंगे। इसके अलावा, अलग-अलग कंपनियों के शेयर रखने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए डिपोजिट्री, निवेशक के फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच स्वीकार करने और इसे सीधे उन कंपनियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।

विदेश में घूमना, इलाज और पढ़ाई अब पहले से सस्ती

- सरकार ने विदेश घूमने वालों के लिए बड़ी राहत दी है। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले टीसीएस जो पहले 5-20 फीसदी लगता था, को घटाकर सिर्फ 2 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह विदेश में मेडिकल और पढ़ाई पर होने वाले खर्च को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने टीसीएस के तहत खर्च पर ब्याज दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया है, यानी आप विदेश में अपना पैसा खर्च करते हैं तो कम ब्याज देना होगा। हालांकि, यह सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल खर्च के लिए ही मान्य होगा। इससे विदेश में पढ़ाई और इलाज अब सस्ता हो जाएगा।

आईटीआर के लिए नई डेडलाइन

अब आईटीआर-1 और 2 को भरने के लिए डेडलाइन 31 जुलाई है। नॉन-ऑडिटेड बिजनेस को आईटीआर भरने की डेडाइन 31 अगस्त तय की गई है। वहीं एनआरआई के लिए टैन की जरूरत अब समाप्त कर दी गई है। अब अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने पर निवासी खरीदार के पैन पर चालान के जरिए टीडीएस जमा किया जा सकता है।

एक अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि आयकर अधिनियम 2025 को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा। यह छह दशक पुराने आयकर कानून का स्थान लेगा। आयकर अधिनियम-2025 के नियम तथा 'टैक्स रिटर्न' फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे, ताकि करदाताओं को इसकी आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

63,500- करोड़ रुपये बजट में किसान सम्मान निधि के लिए जारी किए गए हैं। पिछली बार भी इस योजना के लिए इतनी ही धनराशि का आवंटन किया गया था। इस तरह 6000 रुपये सालाना की किसान सम्मान निधि योजना जारी रहेगी।

वित्त मंत्री ने बजट में किया स्मार्ट फार्मिंग एआई टूल 'भारत विस्तार' का एलान

खेती में एआई क्रांति से किसान होंगे मालामाल

अमृत विचार, बजट डेस्क

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र के लिए 1,62,671 करोड़ का प्रस्ताव और किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें कृषि क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा एआई टूल 'भारत-विस्तार' (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज) को माना जा रहा है। यह एक बहुभाषीय एआई टूल होगा जो एग्रीस्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संसाधनों को एआई प्रणाली से जोड़ेगा। इसका मकसद किसानों को उनकी अपनी भाषा में खास सलाह देना, खेती के जोखिमों को कम करना और पैदावार बढ़ाकर बेहतर फैसला लेने में मदद करना है। इससे किसान आसानी से अपनी आय में इजाफा कर सकेंगे। एग्रीस्टैक भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसे भारत सरकार ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए एक संपूर्ण डेटाबेस बनाना है जिसमें उनकी पहचान, भूमि रिकॉर्ड, आय, ऋण, फसल की जानकारी और बीमा इतिहास शामिल है। यह खेतों से प्राप्त डेटा और सरकारी एपीआई से मिली जानकारी का उपयोग करता है। एग्रीस्टैक के अंतर्गत विभिन्न डिजिटल उपकरणों और सेवाओं को शामिल किया जाता है। 'भारत विस्तार' का ऐलान सबका साथ विकास कर्तव्य का हिस्सा है। इसके अंतर्गत फसल चयन, मिट्टी स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान, बीज-खाद और कीटनाशक की सलाह के अलावा सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन तथा ट्रैकिंग जैसी सारी जानकारी एक ही इंटरफेस पर किसान को उसकी अपनी भाषा में मिलेगी। इस तरह यह प्लेटफार्म फसल की उत्पादकता बढ़ाएगा, किसानों के बेहतर निर्णय में मदद करेगा तथा कस्टमाइज्ड एडवाइजरी से जोखिम कम करेगा।

यूनिफाइड सिस्टम और एआई चैटबॉट

भारत विस्तार एआई टूल किसानों के लिए एक बहुभाषी एआई आधारित सिस्टम है, जो मौसम, फसल स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन और बाजार कीमतों की सटीक जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान करेगा। इसके तहत किसानों को एआई चैट बॉट, यूनिफाइड सिस्टम और टेस्टिंग की जानकारी दी जाएगी। कृषि साथी एआई चैटबॉट के जरिए किसान वॉयस चैटिंग कर सकेंगे और अपनी खेती संबंधित सवाल और समस्याओं के बारे में पूछ सकेंगे।इसमें वे वीडियो के जरिए भी समाधान हासिल कर सकेंगे।

कोकोनट प्रोत्साहन योजना से एक करोड़ किसानों को लाभ

भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है। एक करोड़ किसानों सहित लगभग तीन करोड़ लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए नारियल पर निर्भर हैं। नारियल संवर्धन योजना के माध्यम से नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पुराने और कम पैदावार देने वाले पेड़ों को नए पौधों और किस्मों से बदलने का काम किया जाएगा।

20 हजार से अधिक पशु चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ेगी

पशुपालन ग्रामीण कृषि आय का करीब 16 प्रतिशत योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत किसानों की आमदनी भी शामिल है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री ने 20,000 से अधिक पशु-चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऋण-सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी योजना पेश की है। यह योजना पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, निजी कॉलेज, डायग्नोस्टिक लैब और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देगी।

पशुपालन क्षेत्र को मदद मिलने से बढ़ेगी किसान की आमदनी

1,62,671 रुपये कृषि क्षेत्र के लिए कुल आवंटन

7% अधिक है यह राशि पिछले साल के बजट आवंटन से

पशुपालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। दुग्ध, पोल्ट्री और पशु व्यवसायों का आधुनिकीकरण होगा तथा वैल्यू चेन में किसान संगठनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार पशुधन उद्यमों का संवर्धन और आधुनिकीकरण करके डेयरी और मुर्गीपालन के लिए संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सृजन को संवर्धित करके और पशुधन कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन देगी। बजट में रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना तैयार करने की बात भी कही गयी। इससे रेशम किसानों, भेड़ पालक किसानों और जूट की खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास

- मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। इससे अंतर्देशीय मत्स्य पालन मजबूत होगा, तटीय क्षेत्रों में वैल्यू चेन विकसित होगी और स्टार्टअप, महिला समूहों तथा फिश फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों के जरिए बाजार से जुड़ाव बढ़ेगा।

कृषि से रोजगार

काजू और कोको 2030 तक बनेगा प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड

- भारत को कच्चे काजू और कोको की पैदावार व प्रसंस्करण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा निर्यात बेहतर करने के उपायों पर जोर देते हुए बजट में भारतीय काजू और भारतीय कोको को वर्ष 2030 तक प्रीमियम वैश्विक ब्रांड में मशहूर करने के लिए एक खास कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की

- बजट में केसीसी के तहत सब्सिडी वाले अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे करोड़ों किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को आसानी से सस्ता ऋण मिलने का रास्ता साफ होने से खेती-किसानी में निवेश बढ़ेगा।

सस्ती खाद को 1.71 करोड़ बनेंगे सब्जी उत्पादन क्लस्टर

- किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए 1.71 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रमुख खपत केंद्रों के पास सब्जियों के बड़े उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे ताकि आपूर्ति श्रृंखला बेहतर हो सके।

उच्च मूल्य वाली फसलों पर जोर

- सरकार ने पारंपरिक फसलों के बजाय उच्च मूल्य वाली फसलों पर जोर दिया है। इसमें नारियल प्रोत्साहन योजना, तटीय क्षेत्रों में काजू, कोको और चंदन की खेती को बढ़ावा। पहाड़ी क्षेत्रों में अखरोट, बादाम और पाइन नट्स के बागानों का आधुनिकीकरण। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों की खेती को प्रोत्साहन शामिल है।

किसानों का कल्याण केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान कल्याण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय बजट 2026–27 में किसान को केंद्र में रखकर ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। कोकोनट प्रोत्साहन योजना से उत्पादन बढ़ेगा और 1 करोड़ किसानों सहित लगभग 3 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकारों के साथ मिलकर इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम के गौरव को पुनर्स्थापित किया जाएगा। कृषि संसाधनों तक किसानों की आसान पहुँच के लिए 'भारत विस्तार' नाम से एक बहुभाषी एआई आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी।

उद्योग जगत

इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के निर्माण को 40 हजार करोड़ तो कंटेनर के वैश्विक इकोसिस्टम के लिए 10 हजार करोड़ रुपये

मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई बनेंगे विकसित भारत की राह में गेम चेंजर

नई दिल्ली, बजट डेस्क

केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत में मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाकर 'विकसित भारत' के लक्ष्य को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। सरकार ने 7 रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को गति देने का प्रस्ताव किया है। इसमें बायोफार्मा में अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 'बायोफार्मा शक्ति' योजना शुरू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण की योजना का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत उपकरणों और आईपी डिजाइन पर विशेष जोर दिया गया है। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और तकनीक के जरिए पुनर्जीवित किया जाएगा।ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर (रेयर अर्थ कॉरिडोर) और 3 समर्पित केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) से घरेलू बाजार में बिक्री के लिए रियायती शुल्क की सुविधा। कंटेनर विनिर्माण का अगले 5 वर्षों में वैश्विक इकोसिस्टम बनाने के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। टेक्सटाइल क्षेत्र में प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर के लिए नेशनल फाइबर मिशन और में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है।

'कॉरपोरेट मित्रों' का दस्ता एमएसएमई की करेगा मदद: सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता के लिए मझोले (श्रेणी-दो) और छोटे (श्रेणी-तीन) शहरों में 'कॉरपोरेट मित्रों' का एक दस्ता तैयार करेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' स्थायी समिति का गठन करेगी। 'कॉरपोरेट मित्रों' का यह दस्ता एमएसएमई को किफायती लागत पर अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। सरकार इस दस्ते को तैयार करने के लिए आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई जैसे संस्थानों को मॉड्यूल पाठ्यक्रम और व्यावहारिक टूल डिजाइन करने में सहयोग देगा।

एमएसएमई को 'चैंपियन' बनाने के लिए 10,000 करोड़ का कोष

200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे आधुनिक

10 हजार करोड़ की 'बायोफार्मा शक्ति' योजना

नयी दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को 'चैंपियन' बनाने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपना रही है जिसमें 10,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष भी शामिल है। एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री ने इक्विटी समर्थन, नगदी समर्थन और पेशेवर समर्थन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इक्विटी समर्थन के तहत 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास कोष के माध्यम से चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- उन्होंने कहा कि एमएसएमई को तरलता समर्थन के लिए ट्रेड्स मंच की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा सभी एमएसएमई खरीदारी का लेनदेन ट्रेड्स मंच पर करना, सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी प्रदान करना और जीईएम को कारोबार के साथ जोड़कर वित्तपोषण को तेज और सस्ता बनाना शामिल है। इसके साथ ही सीतारमण ने 2021 में गठित 'आत्मनिर्भर भारत कोष' में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि डालने की घोषणा की ताकि सूक्ष्म उद्यमों को जोखिम पूंजी उपलब्ध रहे।

"भविष्य के लिए तैयार भारत" का बजट

- **नयी दिल्ली।** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय बजट को "भविष्य के लिए तैयार भारत" का बजट बताया है। उनके मुताबिक इस बजट का मकसद निर्यात और घरेलू विनिर्माण को मजबूती देना है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं, महिलाएं, शिक्षा, कौशल विकास, मछुआरे, पशुपालन और नई तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। गोयल ने कहा कि अब तक करीब 350 सुधार किए जा चुके हैं और लगातार नई पहलों के जरिए सुधार की रफ्तार तेज हो रही है। बजट में डेटा सेंटर्स को अभूतपूर्व लाभ देने और 2047 तक टैक्स छूट का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे भारत को एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक हब बनाने की दिशा में सरकार की मंशा साफ झलकती है।

उद्योग जगत ने बताया दूरदर्शी और भरोसा बढ़ाने वाला बजट

- **नयी दिल्ली।** केंद्रीय बजट को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने दूरदर्शी और भरोसा बढ़ाने वाला बताया है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह बजट भारत की विकास यात्रा को स्थिर और मजबूत दिशा देता है। बजट में सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र, खेल सामग्री, महत्वपूर्ण खनिज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

बजट कर अवकाश

भारत के डेटा सेंटर का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर अवकाश का प्रस्ताव

नयी दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक 'कर अवकाश' का प्रस्ताव रखा, जो देश में स्थित डेटा सेंटर का उपयोग करके दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। यह कर अवकाश संबंधित संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन दिया जाएगा। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा, ''मैं किसी भी ऐसी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर अवकाश देने का प्रस्ताव करती हूं, जो भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्वस्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है।'' इस कर अवकाश का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को एक भारतीय पुनर्विक्रेता इकाई के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देनी होंगी।

एक लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने और आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणाएं इस बार आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खास हैं। इसी के साथ भारत को चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में राज्यों को सहायता देने के लिए योजना शुरू करने की घोषणा भी देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को काफी भायी है।

स्वस्थ भारत

• स्वास्थ्य मंत्रालय को 1,06,530 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

10% पिछली बार से ज्यादा

निजी क्षेत्र की साझेदारी में बनेंगे पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 2026-27 के बजट में 1,06,530.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2025-26 के बजट के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने भारत को एक प्रमुख चिकित्सा पर्यटन गंतव्य के तौर पर बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनाने में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ये हब एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परिसर के तौर पर काम करेंगे, जिनमें चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय दूर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए, बजट आवंटन को 45 करोड़ रुपये से कुछ बढ़ाकर 51 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 350 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। स्वायत्त इकाइयों के लिए बजट आवंटन 2024-25 में 21,901.98 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 22,343.97 करोड़ रुपये हो गया है।

नई दिल्ली स्थित एम्स के लिए आवंटन 5,238.70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,500.92 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि आईसीएमआर के लिए 4,821.21 करोड़ रुपये चिह्नित किए गए हैं, जो लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि है।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन 37,100.07 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 39,390 करोड़ रुपये किया

530.42 करोड़ रुपये में से 1,01,709.21 करोड़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा 4,821.21 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए

आयुष्मान भारत का बजट 5.6% बढ़ा

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटन 8,995 करोड़ से बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

अगले पांच साल में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

नई दिल्ली। बजट में अगले पांच वर्षों में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम से देश के दवा उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 'बायोफार्मास्युटिकल्स' या 'बायोलॉजिक्स' ऐसे जटिल औषधीय उत्पाद होते हैं, जिन्हें रासायनिक संश्लेषण के बजाय जीवों, कोशिकाओं या ऊतकों से तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री ने विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा समेत छह प्रमुख क्षेत्रों के लिए ठोस पहल करने का प्रस्ताव रखा।

दस क्षेत्रों में जोड़े जाएंगे एक लाख स्वास्थ्य पेशेवर

नई दिल्ली। अगले पांच सालों में ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और एप्लाइड साइकोलॉजी समेत अलग-अलग क्षेत्रों में करीब एक लाख सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों (एएचपी) को जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि एएचपी के लिए मौजूदा संस्थानों को उन्नत किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्र में नए एएचपी संस्थान बनाए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के युवाओं के लिए कौशल वाले रोजगारों के नए रास्ते बनेंगे। इसमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, एप्लाइड साइकोलॉजी और व्यवहार संबंधी सेहत समेत 10 चुने हुए क्षेत्र शामिल होंगे।

कैंसर के साथ सात अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं की कीमतें होंगी कम

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में कैंसर के साथ सात और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए रियायतों की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर की 17 दवाओं पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी यानी इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा सात और दुर्लभ बीमारियों के उपचार में काम आने वाली दवाओं के आयात शुल्क में भारी छूट दी गई है। मूलभूत सीमा शुल्क वह टैक्स है जो भारत सरकार विदेशों से आयात किए जाने वाले सामान पर लगाती है और यह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत लिया जाता है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर कैंसर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के काम में आने वाली दवाओं की कीमत पर पड़ेगा।

- बुजुर्गों और सहायक देखभाल सेवाओं के लिए एक मजबूत देखभाल प्रणाली बनाई जाएगी।

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

नई दिल्ली। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और दवाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद आयुर्वेद को दुनिया भर में पहचान और मान्यता मिली। अच्छी गुणवत्ता के आयुर्वेद उत्पाद जड़ी-बूटियों की पैदावार करने वाले किसानों और इनका प्रसंस्करण करने वाले युवाओं की मदद करते हैं।

वित्त मंत्री ने बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, प्रमाणन तंत्र के लिए आयुष फार्मेसी और दवा जांच प्रयोगशालाओं को उच्च मानकों पर पहुंचाने और अधिक कुशल लोग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा, प्राचीन भारतीय योग, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही सम्मान है, को तब बड़े पैमाने पर वैश्विक पहचान मिली जब प्रधानमंत्री इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद, आयुर्वेद को भी वैसी ही वैश्विक पहचान मिली। वित्त मंत्री ने जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र को उन्नत करने का भी प्रस्ताव रखा ताकि पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।

निमहांस 2.0 के साथ रांची मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरेगा

रांची। अपने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जानी जाने वाली झारखंड की राजधानी रांची को इसका पहला निमहांस मिलने जा रहा है, जो उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रांची में दूसरे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस 2.0) की स्थापना की घोषणा की।

पहला निमहांस बेंगलुरु में स्थित है। शहर के दो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक केंद्र द्वारा संचालित रांची तांत्रिका और मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान 100 से अधिक वर्षों से मनोरोग देखभाल, अनुसंधान और पुनर्वास के प्रमुख केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीआईपी अधिकारियों ने कहा कि वे संस्थान को निमहांस की तर्ज पर उन्नत करने की मांग कर रहे थे। इस संस्थान की स्थापना अंग्रेजों ने 17 मई 1918 को रांची यूरोपियन लुनेटिक असाइलम के नाम से की थी। सीतारमण ने कहा, उत्तर भारत में कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं हैं। इसलिए, हम निमहांस 2.0 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नत करेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र के लिए आम बजट 2026-27 में 1.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए 55,727 करोड़ रुपये शामिल

शिक्षित भारत

8.27% से ज्यादा वृद्धि

प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टिक केंद्रों के पास देश में बनेंगी 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप

नई दिल्ली, एजेंसी

युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का उद्देश्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने में राज्यों को सहयोग देगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, 'इन प्रस्तावित शैक्षणिक क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे।

केंद्र सरकार ने बजट में शिक्षा को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखते हुए इस वर्ष 8.27 प्रतिशत से अधिक धनराशि का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में कुल 128650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। बजट में उच्च शिक्षा और खासतौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (एसटीईएम) को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

हर जिले में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल 700 से ज्यादा जिले हैं पूरे देश में

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास (गर्ल्स हॉस्टल) स्थापित करने की घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं। सीतारमण ने पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं के लिए ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना का भी प्रस्ताव रखा। मंत्री ने आयुष औषधालयों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन तथा गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रमुख औद्योगिक ''लॉजिस्टिक'' केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।

शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता पर उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन

नई दिल्ली। देश को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सरकार ''शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता'' पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री ने रविवार को बजट पेश करते हुए कहा, मैं ''शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता'' पर एक उच्चस्तरीय स्थाई समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूं, जो विकसित भारत के प्रमुख प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, ताकि वर्ष 2047 तक वैश्विक सेवाओं में हमारी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत हो सके। यह समिति विकास, रोज़गार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करेगी। साथ ही, एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के रोजगार और कौशल आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर आवश्यक उपायों का सुझाव देगी।

15,000 स्कूलों, 500 कॉलेजों में स्थापित की जाएंगी 'एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब'

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल 'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज' के तत्वावधान में 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है।

सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक उभरता हुआ उद्योग है, जिसके लिए 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा, मैं 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। केंद्रीय बजट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 4,551.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

एवीजीसी क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये

इसमें से एक बड़ी राशि भारत के सार्वजनिक प्रसारक 'प्रसार भारती' के साथ-साथ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभा विकास और सामुदायिक रेडियो के विस्तार को समर्थन देने के लिए निर्धारित की गई है। एवीजीसी क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके माध्यम से सरकार देश के युवाओं को कंटेंट क्रिएशन में अग्रणी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बजट, शिक्षा के प्रति सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है : प्रधान

नई दिल्ली, एजेंसी

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रविवार को पेश केंद्रीय बजट में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में शिक्षा के बजट को बढ़ाया गया है जो सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।

प्रधान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बजट में नवजात शिशु से लेकर युवा तक का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी, स्कूल शिक्षा, स्किलिंग, नर्चरिंग इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप और शोध इस बजट के बड़े संकेत है। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने के लिए बजट में कई कल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में शिक्षा में बजट बढ़ाया गया है। पिछली बार की तुलना में इस बार बजट 8.27 प्रतिशत अधिक है जो सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।

इस बजट में भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने की कल्पना

प्रधान ने कहा कि भारत की लड़कियां विज्ञान, तकनीक और गणित की शिक्षा में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। सरकार ने इसमें और गति देने के लिए हर जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाए जाएंगे जिसमें शोध, नवाचार और ज्ञान का एक इकोसिस्टम बनेगा। अर्थ नीति को बढ़ाने के लिए उसे ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है। देश से बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों को पहले पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था उसे दो प्रतिशत किया गया जिससे छात्रों को देश के बाहर शोध करने के लिए जाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि बजट में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीआरटी) के बजट में चौदह प्रतिशत की बढोत्तरी की गई है।

2.77 लाख करोड़ में रेलवे करेगा विकास

नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन तथा कोच की खरीद के साथ-साथ होंगे कई अन्य कार्य

नई दिल्ली, एजेंसी

- 2025-26 में 2,52 लाख करोड़ थे आवंटित वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 10.25% ज्यादा
- रेलवे की कमाई 3,85,733.33 करोड़ और खर्च 3,82,186.01 करोड़ होने का अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजी व्यय के लिए रेल मंत्रालय को 2,77,830 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। बजट आवंटन में नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन तथा कोच की खरीद के साथ अन्य कार्य शामिल हैं। मंत्रालय को वित्त वर्ष 2025-26 में 2,52,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। आने वाले वित्त वर्ष के लिए यह आवंटन 10.25 प्रतिशत ज्यादा है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इसके अलावा, मंत्रालय को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 15,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

बजट दस्तावेज के मुताबिक, रेलवे की कुल कमाई 3,85,733.33 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि खर्च 3,82,186.01 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिससे वित्त वर्ष के आखिर में 3,547.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि क्योंकि रेलवे की कमाई इतनी कम है कि वह परिसंपत्ति बनाने और नए कामों का समर्थन नहीं कर सकती, इसलिए उसे सरकार से धन मिलता है। इसलिए, मंत्रालय को नई लाइन बिछाने, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने और सिंगल-लाइन वाले मार्गों पर डबल लाइन बनाने जैसे कार्यों के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बजट दस्तावेज में विभिन्न निर्माण कार्यों और संपत्ति निर्माण परियोजनाओं के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। इनमें नई लाइन के लिए 36,721.55 करोड़ रुपये, गेज परिवर्तन के लिए 4,600 करोड़ रुपये, लाइन दोहरीकरण के लिए 37,750 करोड़ रुपये, रोलिंग स्टॉक (लोकोमोटिव, वैगन आदि) के लिए 52,108.73 करोड़ रुपये, और सिग्नलिंग तथा दूरसंचार के लिए 7,500 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस दस्तावेज में 2024–25 में रेलवे की वास्तविक कमाई और खर्च का ब्यौरा भी दिया गया है। साल के दौरान, रेलवे ने 3,35,757.09 करोड़ रुपये कमाए और 3,32,440.64 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे 3,316.45 करोड़ रुपये की आय हुई। उस साल के लिए बजट में 2,51,946.56 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

एक अधिकारी ने कहा कि जहां तक वित्त वर्ष 2025–26 की बात है, कमाई और खर्च के असल आंकड़े वित्त वर्ष खत्म होने के बाद ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकतर कमाई और खर्च मामूली बदलावों के साथ उम्मीद के मुताबिक ही हैं। रेलवे के कुल खर्च में से सबसे बड़ा हिस्सा उसके कर्मचारियों को पेंशन देने में जाता है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, 2024-25 में पेंशन पर खर्च 58,844.07 करोड़ रुपये था, जिसके 2026-27 में बढ़कर 74,500 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

सात हाई-स्पीड, एक फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्तव रखा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026–27 के केंद्रीय बजट में अलग–अलग शहरों के बीच सात हाई–स्पीड कॉरिडोर और पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत के बीच एक नए विशेष फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि पर्यावरण अनुकूल यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर सात हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक, ये प्रस्तावित गलियारे मुंबई और पुणे, पुणे और हैदराबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, चेन्नई और बेंगलुरु, दिल्ली और वाराणसी तथा वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच विकसित किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि मालवहन के लिए पर्यावरण अनुकूल सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, वह पूर्वी क्षेत्र में डंकुनी को पश्चिमी हिस्से के सूरत से जोड़ने वाला एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रख रही हैं। अभी, अहमदाबाद और मुंबई के बीच एक हाई–स्पीड कॉरिडोर पर काम जारी है। इसी तरह, कई राज्यों और जिलों में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर – ईस्टर्न और वेस्टर्न का काम जारी है।

राजकोषीय घाटे की भरपाई को 17.2 लाख करोड़ का कर्ज लेगी सरकार

सरकार अगले वित्त वर्ष में 4.3% के अनुमानित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए कुल 17.2 लाख करोड़ रुपये उधार ले सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025–26 में 14.80 लाख करोड़ रुपये के सकल कर्ज का अनुमान लगाया था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचत और अन्य स्रोतों से किये जाने की उम्मीद है। सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। कर्ज की राशि अधिक होने के प्रश्न पर, आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि शुद्ध बाजार उधारी 11.73 लाख करोड़ रुपये के आसपास है, जो कुछ वर्षों के आंकड़ों के करीब है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी संख्या इसलिए है क्योंकि हमें इस साल 5.5 लाख करोड़ रुपये चुकाने हैं। इसलिए, उस लिहाज से हमें यह कोई बड़ी संख्या नहीं लगती। ठाकुर ने कहा कि प्रतिभूति पुनर्खरीद और अदला–बदली का मुख्य उद्देश्य सरकार पर ऋण चुकाने का बोझ कम करना, एक साथ कई ऋण के जमा होने के प्रभाव को कम करना और लागत को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि हमने इस साल उच्च ब्याज वाली प्रतिभूतियों की महत्वपूर्ण अदला–बदली की है। अगले साल इस 5.5 लाख करोड़ रुपये को चुकाना होगा। जैसे–जैसे ये प्रतिभूतियां आती रहेंगी, हम निर्णय लेते रहेंगे। बजट के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीतारमण ने कहा कि केंद्र राज्यों से उनके राजकोषीय प्रबंधन के बारे में बात कर रहा है और उनके ऋणों पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र अनुच्छेद 293 (3) के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य है कि राज्यों के कर्ज पर भी नजर रखी जाए। हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उनके वित्तीय प्रबंधन अधिनियम से ऊपर जाने पर हम उस पर गौर कर सकते हैं।

बजट में राजकोषीय मजबूती, पूंजीगत व्यय बढ़ने से वृद्धि को मिलेगा प्रोत्साहन

नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने बजट 2026–27 में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रशंसा की। कांत ने एक्स पर कहा कि सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को प्रभावशाली ढंग से घटाकर जीडीपी का 4.3 प्रतिशत किया है, जो 2020–21 के 9.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से एक बड़ी कमी है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन के वादे को सफलतापूर्वक निभाने के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई! इस उपलब्धि ने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था में भरोसे को मजबूत किया है, बल्कि निजी क्षेत्र को कर्ज लेने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण भी तैयार किया है। कांत ने कहा कि इस राजकोषीय मजबूती को पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ जोड़ा गया है, जिससे प्रभावी पूंजीगत व्यय अब जीडीपी का 4.4 प्रतिशत हो गया है।

लड़ाकू दक्षता बढ़ाने के लिए सेना को मिले 7.85 लाख करोड़

- रक्षा बजट में 15 प्रतिशत का इजाफा, पूंजीगत व्यय में करीब 22 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7,84,678 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो पिछले वर्ष के आवंटन 6.81 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। सरकार का ध्यान खासकर चीन और पाकिस्तान से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने पर है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के परिप्रेक्ष्य में पूंजीगत खरीद के बजट समेत रक्षा आवंटन में की गई यह वृद्धि हमारी सेना को और अधिक मजबूत बनाने के संकल्प को प्रबल बनाएगी। कुल आवंटन में से 2,19,306 करोड़ रुपये सशस्त्र बलों के पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदना शामिल है। यह पूंजीगत व्यय 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में 21.84 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय के तहत, 63,733 करोड़ रुपये विमान और एयरो इंजन के लिए और 25,023 करोड़ रुपये नौसेना बेड़े के लिए आवंटित किए गए हैं। कुल पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान 1.80 लाख करोड़ रुपये से 39,000 करोड़ रुपये अधिक है। 2025-26 का संशोधित पूंजीगत व्यय 1,86,454 करोड़ रुपये अनुमानित था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 1.39 लाख करोड़ रुपये (पूंजीगत खरीद बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा) वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान घरेलू उद्योगों के माध्यम से खरीद के लिए निर्धारित किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, अगले वित्त वर्ष के लिए रक्षा आवंटन अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दो प्रतिशत है और यह 2025-26 के बजट अनुमान (बीई) की तुलना में 15.19 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।

1.85 लाख करोड़ में सेनाओं के आधुनिकीकरण का प्रावधान

1.71 लाख करोड़ रुपये पेंशन के लिए व्यय करने का प्रावधान

17,250 करोड़ अनुसंधान व विकास पर होगा खर्च

12,100 करोड़ भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना के लिए

खरीदे जाएंगे 114 राफेल

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश किए गए बजट में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की रक्षा तैयारियों को आगे बढ़ाने और सेनाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। बजट में वायु सेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मद्देनजर पूंजीगत बजट में अच्छी खासी बढोतरी की गयी है जो 2.19 लाख करोड़ रुपये है। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक है। पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ दिए गए है जबकि पिछली बार 1.60 लाख करोड़ रुपये था। अनुसंधान और विकास के लिए भी 17250 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो पिछली बार 14923 करोड़ रुपये था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आए बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मज़बूत बनाने के सरकार के संकल्प को और सुदृढ़ किया है।

डीआरडीओ के लिए बजट कभी बाधा नहीं रहा : संयुक्त निदेशक

कोलकाता। डीआरडीओ के संयुक्त निदेशक बिनॉय दास ने कहा कि अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों और हथियार प्रणालियों के डिजाइन और विकास में लगे प्रमुख सरकारी अनुसंधान संगठन के लिए बजट कभी भी बाधा नहीं रहा है। दास ने कहा कि रक्षा अनुसंधान और उत्पादन क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हमेशा से भरपूर सहयोग मिलता रहा है। सरकार ने हमेशा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को बिना शर्त सहयोग दिया है और बजट हमारे लिए कभी बाधा नहीं रहा है। दास के मुताबिक, डीआरडीओ से अगली पीढ़ी की ऐसी तकनीक पर काम करने के लिए कहा गया है, जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। उन्होंने साइंस सिटी सभागार में कहा कि हमें ऐसे उपकरणों पर काम करना होगा, जिनका हमारे सशस्त्र बल सपना देख रहे हैं। हम ऐसे उपकरणों के आयात का इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि आज की बदलती भू–राजनीतिक परिस्थितियों और युद्ध के परिदृश्यों में समीकरण बदल गए हैं। दास को विज्ञान और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान के लिए जेआईएस महा सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि यह बजट हमें उन प्रणालियों को साकार करने और सशक्त बनाने में मदद करेगा, जिन्हें हम विकसित करते हैं। यह निर्यात के माध्यम से आर्थिक महाशक्ति बनने में सहायक होगा। पहले भारत को रक्षा प्रौद्योगिकियों के आयात से वंचित रखा गया था और आज हम आयात से इन्कार कर रहे हैं। भारत ने गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करके सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त की हैं और पूर्णत: आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में काम हो रहा है।

5000 करोड़ में सात सीईआर होंगे स्थापित

सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु, सूरत और वाराणसी सहित सात शहरी आर्थिक क्षेत्र (सीईआर) स्थापित किए हैं। इनके लिए पांच साल में प्रति क्षेत्र 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। सीतारमण ने शहरों को भारत के विकास, नवोन्मेष और अवसरों का इंजन बताते हुए कहा कि यह नई पहल मझोली और छोटे शहरों (टियर दो और तीन) के साथ–साथ मंदिर नगरों पर केंद्रित होगी, जिन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। सरकार ने बजट में दो नई योजनाओं– शहरी आर्थिक क्षेत्रों और क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों के लिए 2,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव रखा है। यह आवंटन सात शहरी आर्थिक क्षेत्रों बेंगलुरु, भुवनेश्वर–पुरी–कटक त्रिपक्षीय क्षेत्र, कोयंबटूर–ईरोड–तिरुप्पुर, पुणे, सूरत, वाराणसी और विशाखापत्तनम के लिए प्रस्तावित किया गया है।

विधि मंत्रालय को ईपीआईसी के लिए मिले 250 करोड़

मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बीच बजट में विधि मंत्रालय को मतदाता पहचान पत्रों के लिए 250 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि लोकसभा चुनाव से संबंधित खर्चों के लिए 500 करोड़ अलग से दिए गए हैं। मतदाता फोटो पहचान पत्रों (ईपीआईसी) पर होने वाला खर्च केंद्र और राज्यों के बीच बराबर बांटा जाता है। प्रत्येक राज्य मतदाताओं की संख्या के अनुपात में राशि का भुगतान करता है। भारत में मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 99 करोड़ है। निर्वाचन आयोग, चुनाव कानूनों, संबंधित नियमों और निर्वाचन आयोग की नियुक्तियों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने वाले विधि मंत्रालय को 2024 में हुए लोकसभा चुनावों के लिए 500 करोड़ उपलब्ध कराए गए हैं।

ई-अदालत परियोजना को मिला 1,200 करोड़

सभी अधीनस्थ अदालतों के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से विधि मंत्रालय की ई–अदालत परियोजना के तृतीय चरण के लिए केंद्रीय बजट में 1,200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस परियोजना को अनुमान के 1,500 करोड़ के मुकाबले 1,200 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सितंबर 2023 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,210 करोड़ के वित्तीय व्यय के साथ केंद्रीय योजना के रूप में परियोजना के तीसरे चरण को मंजूरी दी थी, जिसे चार साल में लागू किया जाना है। राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के तहत भारतीय न्यायपालिका को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में सक्षम बनाने के लिए 2007 से ई–अदालत परियोजना क्रियान्वयन में है। परियोजना का दूसरा चरण 2023 में खत्म हुआ।

2.5 लाख करोड़ में खुफिया तंत्र और मजबूत करेगा केंद्रीय गृह मंत्रालय

कुल धनराशि का 68% हिस्सा यानी 1.73 लाख करोड़ पुलिस मद के लिए किए गए निर्धारित

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026–27 में गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि निर्धारित की गई है, जो 2025–26 के बजट अनुमान 2.33 लाख करोड़ की तुलना में 9.44 प्रतिशत अधिक है। बजट में गृह मंत्रालय के लिए कुल धनराशि का 68 प्रतिशत हिस्सा यानी 1.73 लाख करोड़ रुपये पुलिस मद के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें खुफिया ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ, सीमा विकास कार्यक्रम, तथा दिल्ली और जम्मू–कश्मीर के पुलिस बलों के लिए निधि शामिल है। केंद्रीय बजट 2025–26 में गृह मंत्रालय के लिए 2.33 लाख करोड़ रुपये (बजट अनुमान) आवंटित किए गए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026–27 में जम्मू–कश्मीर के लिए 43,290.29 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए 1,348.0 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। आंतरिक खुफिया एजेंसी आईबी को 2026–27 में 6,782.43 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आईबी के आवंटन में पिछले बजट की तुलना में 63 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछले बजट में आईबी के लिए 4,159.1 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। बजट दस्तावेज में कहा गया है, यह प्रावधान खुफिया ब्यूरो के प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए है, जो आंतरिक खतरों, आतंकवादी गतिविधियों और संभावित सुरक्षा जोखिमों की जानकारी एकत्रित करके और उनकी पड़ताल करके राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। बजट में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 6,680.94 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ के लिए 5,720.17 करोड़ रुपये, दादरा और नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के लिए 2,832.70 करोड़ रुपये, लद्दाख के लिए 4,869.31 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप के लिए 1,682.35 करोड़ रुपये और पुडुचेरी के लिए 3,517.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बजट में जनगणना से संबंधित कार्यों के लिए भी 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसका पहला चरण एक अप्रैल से शुरू होगा।

एफएंडओ में एसटीटी वृद्धि से रोकेंगे सट्टेबाजी

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने का मकसद उच्च जोखिम वाली सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन भोले-भाले निवेशकों को हतोत्साहित करने के लिए किया गया, जो डेरिवेटिव बाजार में बड़ी मात्रा में पैसा गंवा रहे थे। बजट में वायदा अनुबंधों पर एसटीटी को 0.02 से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा, विकल्प सौदों पर एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है। अब तक एसटीटी विकल्प प्रीमियम पर 0.1% और विकल्प कारोबार पर 0.125% था।

बजट के बाद सीतारमण ने कहा कि सरकार वायदा-विकल्प कारोबार के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि भारी नुकसान का सामना कर रहे छोटे निवेशक सट्टेबाजी वाले एफएंडओ बाजार से दूर रहें। सीतारमण ने कहा कि यह मामूली वृद्धि पूरी तरह से सट्टेबाजी को लक्षित है। इसलिए, एफएंडओ पर एसटीटी में यह वृद्धि ऐसे निवेश को रोकने के लिए है। सेबी के अध्ययनों के अनुसार, एफएंडओ खंड में 90% से अधिक खुदरा निवेशकों को नुकसान होता है। बाजार नियामक ने इस खंड में कारोबार कम करने के लिए पहले भी कम कदम उठाए हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अत्यधिक सट्टेबाजी की गतिविधियों को हतोत्साहित करने और अधिक संतुलित बाजार संरचना को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। हालांकि, कुछ लोगों ने चेतावनी दी है कि यह निकट अवधि में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की भागीदारी को प्रभावित कर सकता है।

12.22 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय जीडीपी का 4.4%

सीतारमण ने कहा कि 2026–27 के लिए घोषित 12.22 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.4% है और अब तक का सर्वाधिक है। वित्त वर्ष 2026–27 का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2025–26 में घोषित 11.11 लाख करोड़ के बजटीय पूंजीगत व्यय से 10% अधिक है। उन्होंने कहा कि हमने घोषणा की है कि 12.22 लाख करोड़ का सार्वजनिक व्यय किया जाएगा। इस बार यह जीडीपी का 4.4% है। यह कम से कम पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है और यदि आप पिछली अवधि के आंकड़ों को भी देखें तो यह संभवत: सबसे अधिक है। वित्त वर्ष 2021–22 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का 2.5% और 2024–25 में 4.0% था। वित्त वर्ष 2015–16 में सरकार का पूंजीगत व्यय 2.35 लाख करोड़ रुपये था। सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2026–27 के लिए 4.3% के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य यथार्थवादी है।

सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने को एसटीटी बढ़ाया : राजस्व सचिव

राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि एफएंडओ खंड में एसटीटी बढ़ाने का मकसद सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना और प्रणालीगत जोखिम को संभालना है। एफएंडओ में सट्टेबाजी से छोटे और खुदरा निवेशकों को नुकसान हो रहा था। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों को हतोत्साहित करना है, और यही वजह है कि दर में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि यह मुख्य रूप से वायदा–विकल्प बाजारों में प्रणालीगत जोखिम को संभालने के लिए है। श्रीवास्तव ने कहा कि इस वृद्धि के बाद भी एसटीटी की दरें होने वाले लेनदेन की मात्रा की तुलना में मामूली रहेंगी।

मौजूदा कीमतों पर 10% वृद्धि का अनुमान यथार्थपूर्ण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2026–27 के लिए जीडीपी में मौजूदा कीमतों पर 10% की वृद्धि का अनुमान यथार्थपूर्ण है। बजट दस्तावेज के अनुसार, भारत की जीडीपी वृद्धि को वास्तविक संदर्भ में 393 लाख करोड़ आंका गया है। वित्त मंत्री ने कहा, भारत में मुद्रास्फीति कम है और कुछ समय तक इसी स्तर पर बनी रहेगी। मुद्रास्फीति अकेला मूल्य संशोधन कारक नहीं है, लेकिन काफी हद तक आप इसी पर निर्भर करते हैं। इसलिए मौजूदा कीमतों पर जीडीपी का अनुमान यथार्थपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह 10% वृद्धि का अनुमान जीडीपी के मौजूदा आधार वर्ष और उपयोग की गई गणना पद्धति पर ही तय किया गया है। सरकार फरवरी में कई वृहद–आर्थिक संकेतकों, जैसे जीडीपी और खुदरा मुद्रास्फीति की गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने जा रही है।

एसटीटी वृद्धि से पूंजी बाजार पर बढ़ेगा दबाव, विशेषज्ञों ने जताई चिंता

नई दिल्ली/मुंबई। केंद्रीय बजट 2026–27 में वायदा और विकल्प (एफएंडओ) खंड में प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने पर विशेषज्ञों ने कहा कि यह कदम अल्पकालिक रूप से बाजार के लिए दबाव पैदा कर सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक धीरज रेल्ली ने कहा कि एफएंडओ में एसटीटी वृद्धि अल्पकालिक रूप से पूंजी बाजार संस्थाओं के लिए दबाव डाल सकती है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से यह सकारात्मक हो सकती है। एसटीटी वृद्धि को बजट भाषण के बाद शेयर बाजार में आई तेज गिरावट का कारण बताया गया। कोटक सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीपल शाह ने कहा कि एसटीटी में यह तीव्र वृद्धि व्यापारियों, जोखिम प्रबंधकों के लिए लागत बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। इसका उद्देश्य आमदनी अधिकतम करने से अधिक लेन–देन की मात्रा को नियंत्रित करना प्रतीत होता है, क्योंकि संभावित आय लाभ को वायदा विकल्पों की कम मात्रा से संतुलित किया जा सकता है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म सैमको सिक्योरिटीज ने कहा कि उच्च लेन–देन लागत से लेन–देन की मात्रा घटने, अल्पकालिक गति कमजोर होने और सक्रिय बाजार प्रतिभागियों के लिए लाभप्रदता कम हो सकती है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी अनुसंधान प्रमुख श्रीकांत चौहान ने कहा कि इक्विटी एफएंडओ पर एसटीटी में वृद्धि से अल्पकालिक बाजार में असुविधा उत्पन्न हो सकती है। पुनर्खरीद (बायबैक) को पूंजीगत लाभ के रूप में मानने से एक सार्थक क्षतिपूर्ति मिलती है और दीर्घकालिक निवेशक विश्वास मजबूत होता है। एनएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी आशीषकुमार चौहान ने कहा कि बजट सट्टेबाजी पर रोक के लिए वायदा और विकल्प पर उच्च एसटीटी जैसे सुनियोजित उपायों से वित्तीय बाजारों को सुदृढ़ बनाता है। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के सीईओ फेरोज अजीज ने कहा कि एसटीटी में वृद्धि से डेरिवेटिव व्यापारियों के लेन–देन की लागत में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी जिससे उनकी रणनीतियों पर प्रभाव पड़ेगा। यह बाजार में डेरिवेटिव लेन–देन की मात्रा कम कर सकता है और निकट भविष्य में अस्थिरता ला सकता है।

यूपी के विकास को मिलेगी रफ्तार, मिलेंगे 4 लाख करोड़ रुपये

● इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाई-स्पीड रेल, पर्यटन व सिटी इकोनॉमिक रीजन से टियर-2 व टियर-3 शहरों को मिलेगी मजबूती ● टेक्सटाइल व एआई आधारित कृषि पर फोकस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

बजट -2026

● भाजपा जहां बजट को ऐतिहासिक बता रही, वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है

अमृत विचार: आम बजट से प्रदेश को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सौगात मिलने की उम्मीद है, जिससे विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर फोकस से सरकार उत्साहित है। हाई-स्पीड रेल, जल परिवहन और सिटी इकोनॉमिक रीजन से तस्वीर बदलने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को जमकर सराहा है। भाजपा जहां इसे ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। आम आदमी और नौकरीपेशा वर्ग को प्रत्यक्ष राहत कम नजर आई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय करों से उत्तर प्रदेश के हिस्से में 2.69 लाख करोड़ रुपये आएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में राज्य को कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये मिलने हैं। पूंजीगत निवेश (विकास कार्यों) के लिए राज्यों को ब्याजमुक्त ऋण योजना से 22 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में करीब 18 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान है। इसी प्रकार केंद्र सहायतित योजनाओं के मद में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग ने केंद्रीय योजनाओं से भी 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिलने का अनुमान लगाया है। इन मदों से वर्ष 2026-27 में राज्य को करीब 4.18 करोड़ रुपये मिलेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इन मदों से राज्य को 3.92 करोड़ रुपये मिलने हैं। अब केंद्र से मिलने वाले इस धनराशि के आधार पर राज्य सरकार अपना बजट तैयार करेगी।

बजट में किसान, महिला, युवा, कारीगर व छोटे उद्यमियों को केंद्र में रखते हुए समावेशी विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से पूर्वांचल, काशी क्षेत्र, बुंदेलखंड और टियर-2 व टियर-3 शहरों के लिए ये योजनाएं क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार, निवेश व आर्थिक गतिविधियों को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी-सिलीगुड़ी और दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया, जिससे यूपी को कुल 1500 किमी हाई-स्पीड रेल मिली। इसके अतिरिक्त, सभी 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का विशेष बजट, नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क और तीर्थ स्थलों के विकास की घोषणा की गई। ये परियोजनाएं राज्य में कनेक्टिविटी, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देंगी। केंद्र सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। इससे दूर-दराज़ इलाकों से उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक रहने की व्यवस्था मिलेगी।

बजट में यूपी को मिले प्रमुख तोहफे

- वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम
- बुंदेलखंड में होगा आईआईटी का निर्माण, पश्चिमी यूपी में खुलेगा एम्स
- सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना से टियर-2 व टियर-3 शहरों का कायाकल्प
- 12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स से सड़क, रेल व लॉजिस्टिक्स को मजबूती
- खेल, एमएसएमई, खादी, हथकरघा व टेक्सटाइल सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन की घोषणा
- एआई आधारित 'भारत-विस्तार' से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक
- 'शी-मार्ट' से ग्रामीण महिलाओं को नया बाजार और उद्यमिता का अवसर
- सोलर, बैटरी व ई-मोबिलिटी को बढ़ावा, पीएम सूर्य घर योजना को गति
- हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल और जिला अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार
- 10,000 करोड़ का कंटेनर निर्माण विशेष बजट
- नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क, तीर्थ स्थलों का समग्र विकास

इस धनराशि से तय होगा यूपी के आम बजट का आकार

- केंद्रीय करों से हिस्सा (2026–27): 2.69 लाख करोड़ (2025–26 में 2.55 लाख करोड़)
- पूंजीगत निवेश के लिए ब्याजमुक्त ऋण: 22,000 करोड़ (चालू वर्ष में 18,000 करोड़)
- केंद्र सहायतित योजनाएं: 1 लाख करोड़ से अधिक
- वित्त आयोग की सिफारिशों से: 10,000–12,000 करोड़
- केंद्रीय योजनाओं से अनुमानित राशि: 15,000 करोड़ से अधिक
- कुल अनुमानित केंद्रीय सहायता (2026–27): लगभग 4.18 लाख करोड़
- (2025–26 में लगभग 3.92 लाख करोड़)

आपात-स्थिति में सस्ता और प्रभावी इलाज

गरीबों व निम्न आयवर्ग के लोगों को आपात-स्थिति में सस्ता व प्रभावी इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में सभी जिला अस्पतालों की इमरजेंसी सुविधाएं बढ़ाने तथा ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे समय पर उपचार मिलने से जान बचाने की संभावनाएं बढ़ेंगी और जिला अस्पतालों की क्षमता में भी वृद्धि होगी। इन दोनों पहलों से यूपी में न केवल स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सहायक कर्मियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

कनेक्टिविटी से लेकर रोजगार तक बदलेगा यूपी का परिदृश्य

अमृत विचार, लखनऊ : केंद्रीय बजट 2026–27 उत्तर प्रदेश के लिए विकास का व्यापक खाका लेकर आया है। हाई-स्पीड रेल, जल परिवहन, सिटी इकोनॉमिक रीजन और 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्रदेश की कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही किसान, महिला, युवा, एमएसएमई, पर्यटन और टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष ध्यान देकर रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित करने की दिशा तय की गई है।

हाई-स्पीड रेल से बदलेगी कनेक्टिविटी की तस्वीर

केंद्रीय बजट में घोषित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से 2 महत्वपूर्ण कॉरिडोर सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जिनमें दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राजधानी दिल्ली से काशी, पूर्वांचल और आगे पूर्वी भारत तक की रेलयात्रा तेज, सुरक्षित, सुविधाजनक तरीके से संपन्न होगी। आधुनिक तकनीक से लैस रेल नेटवर्क प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। हाई-स्पीड रेल से लंबी दूरी की यात्रा का समय काफी कम होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश व पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। काशी, पूर्वांचल व सीमावर्ती जिलों में उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

वाराणसी को मिलेगा जल परिवहन में नया आयाम

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जल परिवहन को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय बजट में वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह पहल गंगा नदी पर विकसित हो रहे जलमार्ग आधारित परिवहन तंत्र को तकनीकी व व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाएगी। शिप रिपेयर इकोसिस्टम के स्थापित होने से मालवाहक जहाजों और जलपोतों के रखरखाव व मरम्मत की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी, जिससे समय और लागत दोनों में कमी आएगी। इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलने के साथ जल परिवहन, एक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में प्रभावी होगा।

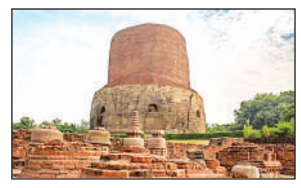

पर्यटन व धार्मिक स्थलों को नई पहचान, संरक्षण को विशेष महत्व

केंद्रीय बजट में पर्यटन व सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। इसी क्रम में भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ तथा हस्तिनापुर को देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे न केवल यूपी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर नई मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। इससे धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल, होम-स्टे, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और अन्य सहयोगी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

सिटी इकोनॉमिक रीजन से शहरों का होगा समग्र विकास

केंद्रीय बजट 2026–27 में टियर-2 और टियर-3 शहरों को विकास की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सिटी इकोनॉमिक रीजन (सीईआर) योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत बड़े महानगरों पर निर्भरता कम करते हुए पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले अन्य शहरों में बुनियादी ढांचे व आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी जैसे प्रमुख शहरों को इस योजना का सीधा लाभ मिल सकता है। आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए लगभग 5000 करोड़ तक का चरणबद्ध निवेश प्रस्तावित है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश की घोषणा मिलेगा सीधा लाभ

केंद्रीय बजट में देशभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) की घोषणा की गई है, जिसका सीधा व अप्रत्यक्ष लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। केंद्र सरकार के इस कैपेक्स का उद्देश्य आर्थिक विकास को रफ्तार देना, रोजगार सृजन करना और भारत को वैश्विक निवेश का आकर्षक केंद्र बनाना है। उत्तर प्रदेश में इस निवेश से सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक हब के विस्तार को नई गति मिलेगी। राज्य का पहले से मजबूत होता एक्सप्रेसवे नेटवर्क (पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा और लिंक एक्सप्रेसवे) औद्योगिक कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा।

सोलर, बैटरी और ई-मोबिलिटी क्षेत्र में रियायत बनेगी गेम चेंजर

अमृत विचार, लखनऊ : केंद्रीय बजट 2026 में सोलर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और ई–मोबिलिटी से जुड़े कस्टम ड्यूटी व आयात शुल्क में दी गई रियायतों को उत्तर प्रदेश के लिए गेम–चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। इन फैसलों को प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना और राज्य में तेजी से उभरते ई–मोबिलिटी इकोसिस्टम से जोड़कर आंका जा रहा है। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि बजट के ये प्रावधान रूफटॉप सोलर विस्तार, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रिड–स्तरीय ऊर्जा संतुलन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी– इन चारों क्षेत्रों को एक साझा दिशा में आगे बढ़ाएंगे। बजट 2026 में लिथियम–आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल– कोबाल्ट पाउडर, बैटरी स्क्रैप और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। सोलर सेक्टर के लिए बजट में एक अहम प्रावधान करते हुए सोलर ग्लास निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल सोडियम एंटीमॉनेट को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। उद्योग जगत का मानना है कि इन रियायतों से डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (डीसीआर) आधारित सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। इनपुट्स सस्ते होने से घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। इसका असर उत्तर प्रदेश में सोलर वैल्यू चेन के विस्तार के रूप में सामने आ सकता है। बजट प्रावधानों के बाद नोएडा, लखनऊ, कानपुर और पूर्वांचल के औद्योगिक क्षेत्रों में नई सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के साथ–साथ ईवी कंपोनेंट्स, बैटरी पैक असेंबली और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश बढ़ने की संभावना है।

एमएसएमई, खादी और वस्त्र क्षेत्र को मिलेगी गति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

● लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों के लिए नए अवसर

● एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम, ग्रोथ फंड और ग्रामीण उद्योगों पर फोकस

अमृत विचार: केंद्रीय बजट 2026–27 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग को सशक्त बनाने के लिए कई अहम और दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। वस्त्र क्षेत्र के लिए एक व्यापक, एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल और समर्थ 2.0 जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन और निर्यात को गति देना है। मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

इन प्रावधानों से प्रदेश के एमएसएमई, खादी, हथकरघा, रेशम और वस्त्रोद्योग से जुड़े लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। रोजगार बढ़ेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी। छोटे उद्यमों की कार्यशील पूंजी की समस्या कम करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम के दायरे का विस्तार किया जाएगा।

कॉरपोरेट मित्र और विरासत औद्योगिक क्लस्टर का प्रस्ताव

'कॉरपोरेट मित्र' व्यवस्था के जरिए एमएसएमई को व्यावसायिक मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और बाजार से जोड़ने की पहल की गई है। इसके साथ ही देशभर में 200 विरासत इंडस्ट्रियल क्लस्टरों के कायाकल्प का प्रस्ताव है, जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टर भी शामिल होंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूते के ऊपरी हिस्सों के शुल्क–मुक्त आयात का विस्तार और चमड़ा व वस्त्र परिधान निर्यात की समय–सीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं। इनसे वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान मिलेगी।

किसानों, महिलाओं व युवाओं पर विशेष ध्यान

केंद्रीय बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारत–विस्तार योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इससे राज्य के अन्नदाता किसानों को मौसम, मिट्टी, फसल चक्र और बाजार की मांग के अनुरूप सटीक कृषि सलाह उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे फसल जोखिम कम होगा और राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि संभव होगी। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा, जो परंपरागत खेती पर निर्भर हैं। बजट में ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शी–मार्ट्स की शुरुआत की गई है। कृषि–तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और उद्यमिता से जुड़े नए अवसर सृजित होंगे।

स्वास्थ्य व शिक्षा में सशक्त कदम

केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण व दूर–दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इससे उच्च शिक्षा, मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास सुविधा मिल सकेगी। बजट में प्रस्तावित स्टेम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथ्स) संस्थानों से प्रदेश में पहले से जारी स्किल डेवलपमेंट अभियान को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है बजट

अमृत विचार, लखनऊ : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जिन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प इसमें स्पष्ट रूप से झलकता है। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी दृष्टि, दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त घोषणापत्र है। राज्यपाल ने कहा कि करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, राजकोषीय अनुशासन, नियंत्रित घाटा और संतुलित कर्ज-जीडीपी अनुपात इस बात का प्रमाण है कि भारत की विकास यात्रा सुदृढ़ नींव पर आगे बढ़ रही है।

बजट पर विभिन्न दलों के नेताओं का कहना...

ऐतिहासिक बजट : केशव प्रसाद मौर्य

अमृत विचार : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। अपार अवसरों का राजमार्ग है। 2047 के विकसित भारत की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है।

बजट में यूपी का रखा ध्यान : पाठक

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आम बजट में उत्तर प्रदेश का पूरा ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित हर क्षेत्र को बजट में समाहित किया गया है

विकसित भारत को लेकर जनोन्मुखी बजट: पंकज

अमृत विचार : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला जनोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। हाई–स्पीड रेल, आयुष, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, कृषि और एमएसएमई पर जोर से रोजगार, निवेश और कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।

समझ से बाहर है बजट : अखिलेश

अमृत विचार : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बजट–2026 में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है और यह पूरी तरह समझ से बाहर है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो पीतल को लोहे पर चढ़ाकर गहने बनाने पड़ेंगे, यह बजट उसी सोच को दिखाता है। आरोप लगाया कि बजट कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है।

मायावती ने बजट पर उठाए सवाल

अमृत विचार : केंद्रीय बजट 2026–27 को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बजट में कई योजनाओं, परियोजनाओं और आश्वासनों का जिक्र है, लेकिन इनके वास्तविक असर का आकलन जमीन पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, इन पर सही नीयत से अमल होना जरूरी है। सलाह देते हुए कहा कि बजट गरीब और बहुजन हितैषी होना चाहिए, न कि केवल पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों का पक्ष लेने वाला।

बजट जवाब देने से भागने वाला : संजय

अमृत विचार : केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बजट सवालों से भागने वाला बजट है और सरकार को अब देश की जनता को जवाब देना ही होगा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ ली थी, तब उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि बजट में बेरोज़गारी पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।

आत्मनिर्भरता के संकल्प को ऊर्जा देगा बजट: अनिल

अमृत विचार : बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने कहा कि यह विकसित भारत का बजट है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह बजट विशेष कर अन्नदाताओं, नौजवानों, महिलाओं और शोषित वंचित उत्थान के लिए समर्पित है और किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण बुनियाद को मजबूत करने का काम करेगा।

विश्लेषण | बजट तात्कालिक वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए रचा गया वक्तव्य : प्रो. अजय द्विवेदी

बजट संख्या नहीं संकेत : देश की आर्थिक चेतना का निर्णायक क्षण

प्रो. अजय द्विवेदी
पूर्व डीन, प्रबंधन संकाय
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

अमृत विचार: भारत का आम बजट तब तक अधूरा रहता है, जब तक उसे केवल आय-व्यय के गणित की तरह पढ़ा जाता है। उसका वास्तविक अर्थ तब खुलता है, जब उसे समाज की मनःस्थिति, राष्ट्र की दिशा और सत्ता की मानसिकता के साथ जोड़कर देखा जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट एक ऐसे दस्तावेज़ के रूप में सामने आता है, जो शोर नहीं करता, संकेत देता है। यह बजट उत्सव का नहीं, निर्णय का बजट है। तात्कालिक वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरे उतरने के लिए रचा गया वक्तव्य।

हर बजट अपने साथ अपेक्षाओं की एक लंबी कतार लेकर आता है। मध्यम वर्ग कर राहत की प्रतीक्षा करता है। किसान स्थिर आय और सुरक्षा की उम्मीद करता है। युवा रोजगार के ठोस संकेत खोजते हैं। उद्योग नीति स्थिरता और निवेश अनुकूल वातावरण चाहता है। सामाजिक क्षेत्र अधिक संसाधनों की आकांक्षा रखता है। ऐसे में प्रश्न यह नहीं कि क्या यह बजट सबको खुश करता है, बल्कि यह है कि यह बजट किस दिशा में देश को ले जाना चाहता है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट भावनात्मक संतोष का साधन नहीं बनता। प्रत्यक्ष करों में बड़े और आकर्षक बदलावों का अभाव पहली दृष्टि में निराशा पैदा कर सकता है। पर इसके भीतर छिपा संदेश अधिक गहरा है। सरकार यह संकेत देती है कि अस्थिर अर्थव्यवस्था में दी गई त्वरित राहत अंततः उसी वर्ग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। महंगाई नियंत्रण, निवेश निरंतरता और वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता देना यह दर्शाता है कि मध्यम वर्ग को उपभोक्ता नहीं, बल्कि आर्थिक भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। यह दृष्टि लोकप्रिय नहीं, पर जिम्मेदार है। कृषि और ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह बजट करुणा से अधिक रणनीति की भाषा बोलता है। किसान को सहायता का पात्र नहीं, बल्कि आर्थिक संरचना का आधार मानने की सोच इस बजट को लोकलुभावन परंपरा से अलग करती है। ग्रामीण रोजगार, कृषि अवसंरचना और मूल्य संवर्धन पर निरंतर जोर यह स्पष्ट करता है कि सरकार जानती है कि गांव कमजोर हुआ तो शहर की प्रगति टिकाऊ नहीं रह सकती। यहां राहत बांटने से अधिक जड़ों को मजबूत करने का प्रयास दिखाई देता है। युवा वर्ग के लिए यह बजट सबसे अधिक बहस को जन्म देता है। सीधे रोजगार के बड़े वादे नहीं हैं, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं जिसे पोस्टर पर उकेरा जा सके। पर कौशल, तकनीक, स्टार्टअप और अवसंरचना के माध्यम से अवसर निर्माण की जो संरचना प्रस्तुत की गई है, वह यह संकेत देती है कि सरकार नौकरी देने की नहीं, रोजगार अर्थव्यवस्था बनाने की सोच पर आगे बढ़ रही है। यह दृष्टि धैर्य मांगती है, पर दीर्घकाल में आत्मनिर्भरता की ठोस जमीन तैयार करती है।

उद्योग और व्यापार जगत के लिए यह बजट राहत की सांस जैसा है। करों में अप्रत्याशित झटकों का अभाव, नीति की निरंतरता और अवसंरचना निवेश का स्पष्ट संकेत यह दर्शाता है कि सरकार उद्योग को संदेह की दृष्टि से नहीं, साझेदार के रूप में देखती है। यह बजट उद्योग से यह नहीं कहता कि सरकार सब कुछ करेगी, बल्कि यह भरोसा देता है कि रास्ता स्थिर और स्पष्ट रहेगा, चलना उद्योग को स्वयं होगा। सामाजिक क्षेत्र में यह बजट भावनात्मक घोषणाओं से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को नारों के रूप में नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही वह सूक्ष्म अंतर है जो इस बजट को गंभीर बनाता है। यह स्वीकार किया गया है कि मानव संसाधन पर किया गया निवेश तत्काल राजनीतिक लाभ नहीं देता, पर दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण का यही आधार होता है। इस पूरे बजट की रीढ़ उसका वित्तीय अनुशासन है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने का संकल्प यह स्पष्ट करता है कि सरकार विकास की कीमत पर लापरवाही नहीं करना चाहती। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में यह संयम भारत को एक जिम्मेदार और परिपक्व अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। अवसंरचना पर निरंतर निवेश के साथ यह अनुशासन यह दर्शाता है कि सरकार विकास को गति देना चाहती है, पर संतुलन खोकर नहीं।

बजट प्रतिक्रिया

वृद्धि, समावेशन का संयोजन वाला साहसिक बजट: सुनील मित्तल

नई दिल्ली, एजेंसी। भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील मित्तल ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने और डेटा सेंटर परिवेश को प्रोत्साहन देने से भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा। मित्तल ने इसे विकास और समावेश को संयोजित करने वाला एक साहसिक बजट बताया और कहा कि कौशल विकास पर जोर के साथ विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान में लगातार निवेश समय पर किया गया कदम है, जो घरेलू क्षमताओं को मजबूत करेगा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात की जगह घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा। मित्तल ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के उपाय, ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना और डेटा सेंटर परिवेश को प्रोत्साहन देना, भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास को और मजबूत करेगा।

यह बजट झुनझुना है दिखता है पर बजता नहीं : प्रमोद तिवारी

लखनऊ, एजेंसी। राज्यसभा में उप नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद प्रमोद तिवारी तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ''मोना'' ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह "झुनझुने" की तरह है, जो दिखता तो है लेकिन बजता नहीं। उन्होंने इसे किसान, बेरोजगार युवाओं और लघु एवं मध्यम उद्योगों के खिलाफ बताते हुए कहा कि बजट से देश की जनता निराश हुई है। उनका दावा है कि बजट के बाद बाजार में गिरावट इसका संकेत है। नेता ने कहा कि पिछले एक वर्ष से पूंजी निवेश ठहरा हुआ है और न तो विदेशी निवेश आ रहा है और न ही स्वदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों में 78,086 करोड़ रुपये और शुद्ध कर संग्रह में 1,62,748 करोड़ रुपये की कमी आर्थिक सुस्ती का संकेत है। उनके अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास, नगर विकास, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं में बजटीय कटौती की गई है, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए कोई ठोस नई योजना या अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है और यह बजट केवल नारों तक सीमित है।

खेल विकास से सधेगी युवा शक्ति

युवा और खेल मंत्रालय के लिए बजट में 1,133 करोड़ की वृद्धि, खेलो इंडिया मिशन की शुरूआत

नई दिल्ली, एंजेंसी

वर्ष 2025-26 3,346 करोड़
वर्ष 2026-27 4,479.88 करोड़

- 2036 तक भारत को टॉप 10 खेल देशों में और 2047 तक टॉप 5 में जगह दिलाने का विज़न
- स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये

यूनियन बजट 2026-27 में भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार पैदा करने पर फोकस किया गया है। इससे युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेलो इंडिया मिशन शुरू करने की घोषणा की, जिसका मकसद अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। डेवलपमेंट सेक्टर के तौर पर स्पोर्ट्स की बढ़ती अहमियत पर जोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, स्पोर्ट्स सेक्टर रोज़गार, स्किलिंग और नौकरी के कई मौके देता है।

खेलो इंडिया प्रोग्राम के जरिए स्पोर्ट्स टैलेंट को सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाने की शुरुआत करते हुए, मैं अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। यूनियन बजट में, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। खेलो इंडिया मिशन पूरे देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बड़ा तरीका अपनाएगा। इस मिशन का मकसद एथलीट के लिए सही रास्ते बनाना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत करना और सभी लेवल पर परफॉर्मेंस के नतीजों को बेहतर बनाना है। बजट में युवाओं पर केंद्रित नेचर पर जोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रस्ताव युवाओं को जोड़ने की कोशिशों से निकले आइडिया और उम्मीदों को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में, हमारे प्रधानमंत्री के साथ कई नए आइडिया शेयर किए गए, जिनसे कई प्रस्तावों को प्रेरणा मिली, जिससे यह एक अनोखा युवा शक्ति पर आधारित बजट बन गया। ग्लोबल स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भारत की क्षमता को पहचानते हुए, बजट में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक खास पहल का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहाः केंद्रीय बजट 2026-27, युवा मामले और खेल मंत्रालय को कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ताकि 2036 तक भारत को टॉप 10 खेल देशों में और 2047 तक टॉप 5 में जगह दिलाने का विज़न पूरा हो सके। मंत्रालय के लिए आवंटन 2025-26 में 3,346 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 4,479.88 करोड़ रुपये हो गया है। बढ़ा हुआ आवंटन केंद्र द्वारा चलाए जा रहे खेल और युवा विकास योजनाओं को लागू करने को मजबूत करेगा, जिसमें एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, युवा जुड़ाव की पहल, कोचिंग और सपोर्ट सिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस इंटीग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल हैं।

बैंकों के लिए उच्चस्तरीय समिति की हुई घोषणा

नई दिल्ली, एजेंसी

- बजट में इस प्रस्ताव से होगा बही खाता सुधार, बैंकों की गांवों की ओर पहुंच और तेजी से बढ़ेगी
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियमों की हो सकेगी व्यापक समीक्षा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ''विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की। यह समिति बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करेगी और इसे भारत की वृद्धि के अगले चरण के लिए तैयार करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत बही-खाते, लाभप्रदता के ऐतिहासिक उच्चस्तर, बेहतर संपत्ति गुणवत्ता और देश के 98 प्रतिशत से अधिक गांवों को शामिल करने वाली पहुंच से लैस है।

उन्होंने आगे कहा, हम इस मोड़ पर इस क्षेत्र की सुधार आधारित वृद्धि जारी रखने के लिए आवश्यक उपायों का मूल्यांकन करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण देते हुए कहा, मैं वित्तीय स्थिरता, समावेश और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित रखते हुए इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने और इसे भारत की वृद्धि के अगले चरण के साथ जोड़ने के लिए विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के नजरिये को ऋण वितरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के स्पष्ट लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी में पैमाना हासिल करने और दक्षता में सुधार करने के लिए उन्होंने कहा कि पहले कदम के रूप में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के पुनर्गठन का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, मैं भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन और उपयोगकर्ता के अनुकूल ढांचा तैयार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियमों की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रस्ताव से देश के बैंकिंग क्षेत्र को लाभ मिल सकेगा।

भारत बनेगा एआई में सबसे बड़ा हब

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बजट पेश होने के बाद रेल भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि भारत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हब के रूप में उभरने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने डिजिटल और तकनीकी विकास को बजट की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल बताया और कहा कि भारत का एआई-पारिस्थितिकी तंत्र आज पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित, निवेश-अनुकूल बन चुका है। श्री वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेमीकॉन 2.0 और सेमीकॉन 1.0 की सफलता के आधार पर आगे बढ़ रहा है, जो सेमीकंडक्टर के उपकरणों, सामग्री का घेरलू विनिर्माण और डिज़ाइन और प्रतिभा पारिस्थितकी तंत्र को मज़बूत करने पर फोकस करता है। उन्होंने मंत्रालय के तहत आईटी सेवाओं में बड़े सुधारों की भी घोषणा की। जिसमें टैक्स और लागू करने को आसान बनाना, और एआई डेटा सेंटर्स के लिए मज़बूत समर्थन शामिल है-जिसे 8.25 लाख करोड़ रुपये (90 बिलियन डॉलर) तक के निवेश और 2047 तक टैक्स हॉलिडे का सपोर्ट मिला है-जो भारत को वैश्विक एआई हब के तौर पर स्थापित करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि एआई और तकनीक को लेकर बजट में मिले प्रोत्साहन से देश में एआई -संबंधित बुनियादी ढांचे, डेटा-सेंटर, जीपीयू (ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट) क्षमता और शोध को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत किसी अन्य देश की नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी रणनीति के साथ एक वास्तविक और व्यावहारिक एआई विकास मॉडल तैयार कर रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि एआई सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का अगला बड़ा इंजन है, और भारत की रणनीति इसे विश्व स्तर पर एक प्रमुख एआई हब के रूप में स्थापित करने की है। उन्होंने कहा कि सरकार एआई का उपयोग, स्किलिंग, रिसर्च और निवेश को समान रूप से बढ़ावा दे रही है ताकि देश के युवा, स्टार्टअप्स तथा उद्योग सभी इस तकनीक का लाभ उठा सकें।

पीएफ ट्रस्ट में नियोक्ता योगदान को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को भविष्य निधि या पीएफ ट्रस्ट के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया। इसके तहत नियोक्ता के योगदान पर समानता और प्रतिशत आधारित सीमाओं की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इस पहल का मकसद कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों में नियोक्ताओं के योगदान को सरल बनाकर कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है। इस समय कुछ ऐसे पीएफ ट्रस्ट हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति निधि संभालने वाली संस्था ईपीएफओ और आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त है। इन ट्रस्ट के नियोक्ता कुछ सीमाओं के तहत पीएफ खातों में अपने कर्मचारियों के योगदान की तुलना में कम या अधिक राशि का योगदान करते थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि परिवर्तनों का उद्देश्य कामकाज को आसान बनाना है।

रियल एस्टेट और शहरी विकास को प्रोत्साहन

नई दिल्ली, एजेंसी

- राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा

केंद्रीय बजट पर राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने रविवार को कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह बजट उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है।

श्री जैन ने बजट में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सभी क्षेत्रों व सेक्टरों तक अवसरों की समान पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है, जो "सबका साथ, सबका विकास" की भावना को मजबूती देता है। श्री जैन ने शहरी संतुलित विकास के लिए पूंजीगत व्यय को वित्त वर्ष 2026-27 में 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किए जाने के निर्णय को दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर विशेष फोकस से टियर-2 और टियर-3 शहरों में रियल एस्टेट गतिविधियों को नई गति मिलेगी और मेट्रो शहरों से परे संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर लोहिया वर्ल्डस्पेस के निदेशक पीयूष लोहिया ने कहा कि यह बजट आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्थिरता व दीर्घकालिक विकास का मजबूत आधार तैयार करता है। उन्होंने कहा कि सात हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर-मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेंगे और इनके आसपास नए रियल एस्टेट, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित होंगे। दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि यह बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भरोसेमंद, निवेश-अनुकूल और विकासोन्मुख वातावरण तैयार करता है, जो भारत के शहरी और आर्थिक भविष्य को नई दिशा देगा।

म्यूचुअल फंड आय से जुड़े ब्याज खर्चों पर कटौती खत्म करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी

सरकार ने रविवार को लाभांश और म्यूचुअल फंड आय से संबंधित ब्याज खर्चों पर मिलने वाली कटौती को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्रस्ताव से वह मौजूदा प्रावधान खत्म हो जाएगा, जिसके तहत लाभांश या म्यूचुअल फंड आय के 20 प्रतिशत तक के ब्याज खर्चों पर कटौती की अनुमति मिलती थी। आम बजट 2026-27 के अनुसार, यह प्रस्ताव है कि लाभांश आय या म्यूचुअल फंड की इकाइयों से होने वाली आय के संबंध में किए गए किसी भी ब्याज व्यय पर कोई कटौती नहीं दी जाएगी। साथ ही, एक तय सीमा तक ऐसी कटौती की अनुमति देने वाले मौजूदा प्रावधान को हटाने का भी प्रस्ताव है।

यह बदलाव आयकर अधिनियम, 2025 का हिस्सा है, जो एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। अब अगर निवेशक कर्ज लेकर निवेश करते हैं, तो उनके ऋण के ब्याज जैसे खर्चों को लाभांश या म्यूचुअल फंड आय से घटाया नहीं जाएगा। इससे ऐसी आय पर कर योग्य राशि प्रभावी रूप से बढ़ जाएगी।

आवास ऋण के ब्याज पर छूट में अब ब्याज भी शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के मामले में आवास ऋण के ब्याज पर मिलने वाली दो लाख रुपये तक की आयकर कटौती में अब संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण से पहले दिया गया ब्याज भी शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22(2) में संशोधन करेगी। इससे एक अप्रैल 2026 से लागू नए कर कानून के तहत गृह ऋण लेने वाले करदाताओं को राहत जारी रहेगी। बजट दस्तावेज के अनुसार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22 गृह संपत्ति से होने वाली आय के मामले में मिलने वाली कटौतियों से संबंधित है।

विदेश में रहने वालों को निवेश की अनुमति

नई दिल्ली, एजेंसी

पीआरओआई निवेश

- भारतीय कंपनियों में अब इक्विटी निवेश कर सकेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत व्यक्ति (पीआरओआई) अब पोर्टफोलियो निवेश योजना के जरिये सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी निवेश कर सकेंगे। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि पीआरओआई के लिए निवेश सीमा को भी अब पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट बॉन्ड सूचकांक पर कोष एवं डेरिवेटिव्स तक उपयुक्त पहुंच के लिए एक ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान देना जारी रखेगी।

उन्होंने कहा कि गुजरात के जामनगर में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र अद्यतन किया जाएगा। साथ ही देश की दूरबीन और खगोल विज्ञान अवसंरचना को भी उन्नत करने का प्रस्ताव है।

बजट के मुताबिक, पर्यटन एवं कौशल विकास क्षेत्र में सरकार 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड के कौशल उन्नयन के लिए पायलट योजना शुरू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में पर्वतारोहण में विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने की क्षमता मौजूद है। इसके अलावा केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन मार्ग भी विकसित करेगी।

सुधार | बजट में प्रशासनिक सुधारों को 65 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव ई-गवर्नेंस को बढ़ावा

कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर 299 करोड़ रुपये होंगे खर्च

नई दिल्ली, एजेंसी

देश और विदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 299 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।

रविवार को पेश बजट के अनुसार, इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों के लिए 65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस प्रावधान में सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण की योजना, प्रशासनिक सुधारों पर पायलट परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, सुशासन को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए एक व्यापक प्रणाली शामिल है।

आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल 299 करोड़ रुपये के परिव्यय में से, 120.8 करोड़ रुपये प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के लिए स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए, 52.2 करोड़ रुपये प्रशिक्षण योजनाओं के लिए और 126 करोड़ रुपये केंद्र के महत्वाकांक्षी ''मिशन कर्मयोगी'' या सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को निर्धारित की गई है। मिशन कर्मयोगी को सबसे बड़ी नौकरशाही सुधार पहल कहा जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अधिक रचनात्मक, सक्रिय, पेशेवर और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाना है। बजट दस्तावेज में कार्मिक मंत्रालय के लिए बजटीय प्रावधानों का विवरण देते हुए कहा गया कि 120.8 करोड़ रुपये के प्रावधान में दिल्ली स्थित आईएसटीएम, मसूरी स्थित एलबीएसएनएए और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग से संबंधित स्थापना व्यय शामिल हैं। ये संगठन सचिवालय के सभी स्तरों तथा श्रेणियों के कर्मचारियों को नवीनतम नियमों एवं विनियमों और योग्यताओं से पर्याप्त रूप से अवगत कराने के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम, पुनरावलोकन पाठ्यक्रम तथा मिड-करियर (कामकाज के दौरान) प्रशिक्षण सहित कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस आवंटन में घरेलू या विदेशी यात्रा पर होने वाला व्यय, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) और केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएस) के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क भी शामिल होगा।

बजट दस्तावेज में कहा गया कि 52.2 करोड़ रुपये के आवंटन में सभी के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान शामिल है। अगले वित्त वर्ष में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए 3.5 करोड़ रुपये का कोष अलग रखा गया है।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) को लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामलों के निवारण का दायित्व सौंपा गया है। इसको आगामी वित्त वर्ष के लिए स्थापना संबंधी व्यय को 166.42 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। बजट दस्तावेज में कहा गया कि इसमें सीएटी की विभिन्न पीठों के लिए भूमि की खरीद एवं भवनों के निर्माण का प्रावधान भी शामिल है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 52.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है।

बजट समावेशी, वृद्धि और रोजगार बढ़ाने वाला: महेंद्र देव

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन एस महेंद्र देव ने रविवार को कहा कि बजट 2026-27 समावेशी है और वृद्धि तथा रोजगार को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट कारोबारी सुगमता के साथ ही रहन-सहन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। देव ने लिंक्डइन पर पोस्ट किया, बजट 2026-27 विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अगला कदम है। यह वृद्धि, समावेश और रोजगार की दिशा में बढ़ने वाला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों, वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट, और कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की।

दुर्घटना दावे से मिला हर्जाना अब आयकर से मुक्त होगा

नई दिल्ली, एजेंसी

- कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ
- एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा। बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है।

दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हादसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली किसी भी आय पर व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को छूट दी जाएगी।

यह संशोधन एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 तथा उसके बाद के कर वर्षों के संबंध में लागू होगा। इसमें यह भी कहा गया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई मुआवजे की राशि पर मिलने वाले ब्याज के संबंध में स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी।

न्यूज ब्रीफ

बजट से देश वासियों को उम्मीद जगी है : अरुण कुमार

शाहजहांपुर, अमृत विचार : भाजपा सांसद अरुण सागर ने कहा कि इस बजट से देश वासियों को उम्मीद जगी है। बजट में रोजगार बढ़ाने, किसानो की मदद, शिक्षा और स्वास्थ को और बेहतर बनाने, महिलाओं को मजबूत करने सड़क और रेल जैसी बुनियादी सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। बजट आने के बाद सांसद ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रयासों से पेश किया गया बजट बहुत ही अच्छा और उम्मीद जगाने वाला है। यह बजट साफ दिखाता है कि विकास सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि गांव-गरीब-मध्यम वर्ग तक सच में पहुंचेगा। प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप यह बजट गरीब, युवा, किसान और नारी शक्ति पर केंद्रित है। इसमें विकास के चार प्रमुख इंजन, कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा यही संदेश दिया है कि विकास तभी सार्थक है, जब वह आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। इस बजट में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है, जो 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएगी।

बजट : कुछ की उम्मीदें हुईं पूरी, कुछ की रहीं अधूरी

केंद्र सरकार के बजट को कुछ लोगों ने सराहा, वहीं कुछ ने बताया निराशाजनक, किसानों ने कहा नहीं मिली बजट से राहत

कार्यालय संवाददाता, शाहजहांपुर

अमृत विचार : केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए केंद्रीय बजट को लेकर जिले की जनता में खासी उत्सुकता और उत्साह देखने को मिला। बजट में मध्यम वर्ग, किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जिस पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं।

व्यापारियों में बजट को लेकर संतोष की भावना दिखी। कहा कि आयकर में दी गई राहत से मध्यम वर्ग को सीधा लाभ होगा। इससे उनकी खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी और व्यापार में तेजी आएगी। इस फैसले से बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। गृहिणियों ने महिलाओं और बच्चों से जुड़ी योजनाओं की सराहना की। हालांकि, महंगाई को काबू करने के लिए और मजबूत कदम उठाने की जरूरत बताई गई। युवाओं ने रोजगार सृजन और स्किल डेवलपमेंट पर सरकार के जोर की तारीफ की। किसानों ने बताया कि हर बजट में किसानों के लिए घोषणाएं होती रहती हैं, लेकिन असली लाभ तब मिलेगा जब ये सुविधाएं सीधे खेतों तक पहुंचेंगी। वरिष्ठ नागरिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं और पेंशन से जुड़े प्रावधानों को राहत देने वाला बताया। फिर भी, बढ़ती महंगाई को लेकर उनकी चिंता बरकरार है।

ये विकसित भारत का बजट है : किशोर गुप्ता

राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संघटन के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष किशोर कुमार गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये विकसित भारत का बजट है, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की और बढ़ते कदम के लिए बजट, इनकम टैक्स में सजा का प्रावधान हटने से भय ख़त्म होगा।

कर्मचारियों के रिक्त पदों के भरने पर नहीं हुई चर्चा : नरेंद्र त्यागी

एनआरएमयू मुरादाबाद मंडल के सहायक मंडल मंत्री व सचिव जिला ओलम्पिक संघ नरेंद्र त्यागी ने कहा कि बजट में कर्मचारियों के रुके हुए 18 माह के डीए को देने, कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने पर चर्चा नहीं की गई। 8वां वेतन आयोग के लिये भी बजट में कुछ नहीं है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई खास प्रावधान नहीं : ओमशिव

रिटायर्ड स्टेशन अधीक्षक ओम शिव अवस्थी ने कहा कि सीनियर सिटीजन के लिए बजट में कोई खास प्रावधान नहीं है। 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड व एचडी में एक्स्ट्रा ब्याज टीडीएस की कटौती बंद करने तथा वेतन आयोग के संबंध में बजट में प्रावधान नहीं है।

संतुलित और व्यावहारिक बजट है : अक्षत

टैक्स कंप्लायंस एवं लिटिगेशन्स एक्सपर्ट अक्षत सक्सेना यह बजट तात्कालिक कर राहत से अधिक अनुपालन आधारित कर सुधारों, राजस्व सुदृढ़ीकरण और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस पर केंद्रित एक संतुलित और व्यावहारिक बजट है। उन्होंने कहा इससे आम आदमी को राहत मिलेगी। बजट आम आ

बजट का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को मिले : अनीत

सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव अनीत कुमार त्रिवेदी एडवोकेट ने कहा कि एक अधिवक्ता के रूप में यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि बजट प्रावधानों का क्रियान्वयन पारदर्शी और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हो, ताकि इसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। व्यापारियों को मिलेगा लाभ।

प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन : नवजोत

कांवेंट स्कूल के शिक्षक नवजोत सिंह ने कहा कि बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने सिद्ध किया है कि यह आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प है। बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। ये बजट हर इंसान के लिए सही है।

शिक्षा में गुणवत्ता और छूट की अनदेखी : डॉ रूपक

प्रोफेसर डॉ रूपक श्रीवास्तव ने कहा कि विदेश यात्रा खर्च पर टैक्स दर 2 प्रतिशत तक घटाई गई है इसका लाभ मिलेगा। नौकरी वाले युवाओं को लाभ देने को कर्मचारी भविष्य निधि से तीन किस्तों में एक महीने का वेतन देने की योजना से दो करोड़ युवाओं को लाभ मिलेगा।

आर्थिक सम्मान का माध्यम बनेगा : कामरान

प्रशिक्षक मोहम्मद कामरान ने कहा कि केंद्रीय बजट शिक्षा, कौशल, ग्रामीण विकास और अवसंरचना पर यह बजट शाहजहांपुर जैसे ज़िलों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की क्षमता रखता है। बजट रोज़गार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सम्मान का माध्यम बनेगा।

युवाओं को रोजगार, कौशल पर केंद्रित : वैभव

छात्र प्रतिनिधि ने कहा कि आज के बजट में युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह बजट युवा शक्ति-संचालित बजट" है, जो युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है।

युवाओं को सशक्त बनाने वाला बजट : आयुष

छात्र प्रतिनिधि आयुष श्रीवास्तव ने कहा कि यह बजट युवाओं के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। शिक्षा से रोजगार की नीति और डिजिटल स्किल्स पर फोकस यह सुनिश्चित करेगा कि युवाओं को पढ़ाई पूरी करते ही काम मिले।

ब्याज दरों में कटौती नहीं : सलाउद्दीन

व्यापारी नेता सलाउद्दीन अख़्तर ने कहा कि उद्योग एवं व्यापार वर्ग निरंतर देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार सृजन तथा सरकार के राजस्व में महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है। बैंको द्वारा व्यापारियों को दिये जाने वाले ऋण में ऊंची ब्याज दरें ली जाती हैं कटौती होनी चाहिए।

बजट कुछ खास नहीं : मुबीन

डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ के जनपद सचिव इं अहमद मुबीन ने कहा कि आज केंद्र सरकार का बजट आया है, परंतु उसमें पेंशन व्यवस्था और आठवें वेतन आयोग से संबंधित बजट की बात नहीं की गई। कर्मचारी, शिक्षकों की दृष्टि से यह बजट कुछ खास नहीं है।

बजट डिजिटल कौशल पर फोकस करता है : शिशिर

भौतिकी विभागाध्यक्ष डा शिशिर शुक्ला ने कहा कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट तकनीकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल कौशल पर विशेष फोकस करता है। देश के हजारों स्कूलों और कॉलेजों में एवीजीसी अर्थात एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स से जुड़ी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की घोषणा से स्पष्ट है कि देश के युवाओं को तकनीकी दक्षता से लैस करने के लिहाज से यह बजट नितांत महत्वपूर्ण है।

बजट में एमएसएमई को 10,000 करोड़ रुपये का एमएसएमई ग्रोथ फंड दिया गया है, जिससे देश और प्रदेश के छोटे व्यवसायों को विस्तार और प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लघु और सूक्ष्म उद्योगों को टियर-2 और टियर-3 शहरों में कॉर्पोरेट मित्र और प्रशिक्षण समर्थन मिलने से स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा।

– **रोहित गोयल**, सचिव, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

ऑटोमोबाइल और निर्माण उद्योग ने बजट की कुछ घोषणाओं का स्वागत किया जाना चाहिए। इससे इन क्षेत्रों में निवेश और औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा मिलने की संभावना है। लॉन्ग-टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्पादन उन्मुख नीतियों से कारोबारी माहौल मजबूत होगा। कुछ सेक्टरों को अभी विशिष्ट प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी।

– **शुभम खन्ना**, केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

बजट से प्लास्टिक उद्योग को कच्चे माल पर करों में राहत, सस्ती वित्तीय सहायता, और तकनीकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन की उम्मीद थी। प्लास्टिक कच्चे माल पर कर राहत जैसे प्रावधान घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन कस्टम्स सुधार और विनिर्माण को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं उद्योग के लिए अवसर पैदा कर सकती हैं।–

गुरजीत सिंह मोंगा, मंडलीय चेयरमैन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत यह बजट विकसित भारत का चहुंमुखी बजट है। कर्तव्य भवन में बना यह पहला बजट गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी शक्ति, जनजातीय वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए आर्थिक सशक्तिकरण व सामाजिक विकास के नए अवसर प्रदान करेगा। इससे हर वर्ग को लाभ होगा।

–**प्रशान्त कठेरिया**, भाजपा नेता ।

आत्मनिर्भर भारत फंड में अतिरिक्त राशि जोड़कर सूक्ष्म उद्यमों को पूंजी और जोखिम भत्ते का समर्थन बढ़ाया गया है। बजट में 200 पारंपरिक औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव है, जिससे स्थानीय कारोबारों को नई ताकत मिलेगी। इससे लोगों को लाभ मिलेगा।

– **जय गोविंद मोदी**, कोषाध्यक्ष, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन शाहजहांपुर

बजट में औद्योगिक विकास, मेड इन इंडिया को मजबूत करने और उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे देश में उत्पादन क्षमता और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ने की उम्मीद है, जो स्वागत योग्य कदम है। इस बजट से देश के प्रत्येक वर्ग को सहूलियत मिलेगी। बजट सभी को हित में बनाया गया है।

– **हेमंत रोहरा**, वाइस चेयरमैन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

यह बजट विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने वाला दूरदर्शी और ऐतिहासिक बजट है। यह गरीब कल्याण, किसानों-युवाओं के उत्थान और महिला सशक्तिकरण को समर्पित है। इस बजट का लाभ प्रत्येक तबके को मिलेगा। इस बजट में किसानों को भी राहत मिलेगी, तो व्यापारी वर्ग को भी लाभ देगा।

– **विनीत मिश्र**, मीडिया प्रभारी, केंद्रीय राज्य मंत्री

कपड़ा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता और आजीविका का प्रमुख साधन है। सरकार ने कपड़े पर 5 प्रतिशत टैक्स स्लैब रखा है, जबकि इसे पूरी तरह टैक्स मुक्त श्रेणी में रखा जाना चाहिए था, ताकि आम आदमी को सीधी राहत मिल सके। कपड़ा प्रत्येक वर्ग की जरूरत है। सरकार को कपड़े से टैक्स हटा लेना चाहिए।

– **सचिन बाथम**, महानगर अध्यक्ष, व्यापार मंडल

टीवी पर बजट देखते उद्यमी। ● अमृत विचार

बजट 2026 पर आईआईए की कार्यकारिणी में मंथन

शाहजहांपुर, अमृत विचार : इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन शाहजहांपुर की कार्यकारिणी की ओर से केंद्रीय बजट 2026 को लेकर चर्चा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों और सदस्यों ने बजट के विभिन्न प्रावधानों पर अपने विचार रखे और औद्योगिक विकास, एमएसएमई, विनिर्माण और निवेश से जुड़े पहलुओं पर प्रतिक्रिया दी।

भाजपा कार्यालय पर बजट का प्रसारण देखते पदाधिकारी व कार्यकर्ता। ● अमृत विचार

यह बजट एमएसएमई को स्थानीय स्तर से वैश्विक स्तर तक ले जाने के अवसर देने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेडिट और नियमों में और सरलता की अपेक्षा अब भी बनी हुई है।

– **विनम्र अग्रवाल**, चैप्टर चेयरमैन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

पुवायां में केंद्रीय बजट 2026 को लेकर दिखा उत्साह

पुवायां, अमृत विचार : नगर पालिका परिषद पुवायां के सभागार में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 को लेकर चर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। चर्चा के दौरान जिला अध्यक्ष कृष्ण चंद्र मिश्र ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें किसानों और छात्रों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। उन्होंने बताया कि बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कई बड़ी परियोजनाओं को शामिल किया गया है, जिनमें हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के साथ-साथ अयोध्या, काशी, मथुरा और आगरा जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर विकसित करने की योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 83,562 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.35 प्रतिशत अधिक है। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष क्षमा वर्मा, जिला कोषाध्यक्ष संजीव बंसल, किसान मोर्चा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सर्वेश पाल, नगर पालिका परिषद पुवायां के चेयरमैन संजय गुप्ता, जिला संयोजक सैनिक प्रकोष्ट विजय मोहन मिश्र, मंडल अध्यक्ष पुवायां नगर अर्पित गुप्ता, मंडल अध्यक्ष ग्रामीण राजेश राजपूत सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने देखा केंद्रीय बजट का प्रसारण

शाहजहांपुर, अमृत विचार : केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026 के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय शाहजहांपुर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में दिए जा रहे बजट भाषण का पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से लाइव प्रसारण सुना और देखा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बजट 2026 में गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा देगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगातार विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ा रही है और बजट 2026 उसी सोच को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने बजट को जन-आकांक्षाओं के अनुरूप बताते हुए इसे दूरदर्शी और समावेशी करार दिया। कार्यक्रम में संयोजक जितेंद्र वर्मा, सह संयोजक नितेश गुप्ता, त्रिवेंद्र सिंह, नीलमणि त्रिवेदी, व्यापार मंडल अध्यक्ष कुलदीप दुआ, रोहित अग्रवाल, विनोद कन्नौजिया, हेमा अग्रवाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओ ने कहा कि सरकार का बजट प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

आयोजन

शोभायात्रा में सभी वर्गों ने की शिरकत, जगह-जगह किया गया स्वागत, साधु-संतों ने किया हवन पूजन

संत रविदास जयंती पर धूमधाम से निकाली शोभायात्रा में शामिल झांकियों ने मोहा मन

कार्यालय संवाददाता, शाहजहांपुर

अमृत विचार : संत रविदास जयंती पर रविवार को शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी शोभायात्रा में सभी वर्गों के लोगों ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया। खिरनी बाग जीआईसी खेल मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मनमोह लिया।

गुरु रविदास सभा की ओर से संत शिरोमणि गुरु रविदास पूजा स्थल रामबाग सराइकाइयां में साधु-संतों ने हवन पूजन किया। उसके बाद बैंड-बाजा और मनमोहक झांकियों के साथ शोभायात्रा निकाली गई।

शोभायात्रा को रविदास सभा के अध्यक्ष दिनेश कुमार एडवोकेट, विपुल प्रसाद सिंह, राम प्रकाश, बाबू भगवत राम तथा राकेश कुमार ने संयुक्त रूप से झंडा दिखाकर रवाना किया। पूजा स्थल से निकली शोभायात्रा में आगे-आगे संत रविदास की भव्य सिंहासन झांकी रही, जिसके पीछे संत-महात्माओं की मनमोहक झांकियां, बैंड-बाजे एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। शोभायात्रा केरूगंज, चार खंभा, चौक, घंटाघर, बहादुरगंज, सदर बाजार, कचहरी, गुरुद्वारा से होकर जीआईसी खेल मैदान खिरनी बाग में पहुंची। रात्रि में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। कार्यक्रम में रामपाल चौधरी, रामप्रकाश, माया प्रकाश, श्याम बिहारी एडवोकेट, दो छेदा लाल, शैलेंद्र मोहन, पीडब्ल्यूडी से शिव शंकर लाल, निराला, राजेंद्र प्रसाद वर्मा, मातादीन वर्मा, अनिल कुमार, रमेश कुमार एडवोकेट, मुकेश कुमार, महेश किला, अनिल भास्कर, मुंशीलाल गौतम, राजू बग्गा, दीपक उर्फ दीपू, अनूप कुमार सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। इसके अलावा सपा कार्यालय पर जिलाध्यक्ष तनवीर खां के साथ पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा, पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा, जिला महासचिव रणंजय सिंह यादव आदि मौजूद रहे।

संत रविदास जयंती पर शोभायात्रा को झंडा दिखाकर रवाना करते समाज के लोग। ● अमृत विचार

शोभायात्रा में शामिल झांकी में शामिल कलाकार।

आयोजकों को पुलिस ने दी चेतावनी

सिंधौली, अमृत विचार : रविदास जयंती पर गांव में बने बुद्ध विहार पर सभा करने की योजना बना रहे आयोजकों को पुलिस ने सख्त हिदायत देकर नई परंपरा न डालने की चेतावनी दी। क्षेत्र के चड़ारी गांव निवासी कालिका प्रसाद ने दो वर्ष पहले अपने घर में गौतम बुद्ध तथा डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित करने के बाद उक्त स्थल को बुद्ध विहार का नाम दे दिया। इसके बाद वह वह परिवार सहित दिल्ली के शाहदरा में रहने लगे। चड़ारी गांव में निवास कर रहे कुछ लोग रविदास जयंती के मौके पर बुद्ध विहार स्थल पर कार्यक्रम करना चाहते थे। सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक रविंद्र सिंह ने उक्त लोगों से संपर्क कर बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई भी सभा न करने की हिदायत दी। प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र सिंह ने बताया कि प्रशासनिक अनुमति के बिना ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा।

संत रविदास शोभायात्रा का जगह जगह किया गया स्वागत किया

रविदास जयंती के जुलूस का स्वागत गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा निकट कचहरी में किया गया। इस दौरान संस्थाध्यक्ष बीबी कमलेश कौर माटा, महासचिव सरदार हरभजन सिंह दिया, धार्मिक सचिव सरदार जगजीत सिंह, सरदार राजू बग्गा, गुरमीत सिंह गांधी, गुरप्रीत सिंह, गुरमीत सिंह बग्गा, श्री गुरु रामदास गुरमत, संगीत विद्यालय के छात्र उपस्थिति रहे।

श्रद्धा के साथ मनाया संत रविदास जयंती प्रकाश पर्व

पुवायां, अमृत विचार : गीता सिटी स्थित शिक्षक वीरपाल के आवास पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती प्रकाश पर्व के रूप में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन एडवोकेट सुबोध कनौजिया के संयोजन में किया गया। एडवोकेट सुबोध कनौजिया ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास जी का सम्पूर्ण जीवन श्रद्धा, भक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक रहा है। इस मौके पर ब्रजेश कुमार, प्रवक्ता अवनीश कुमार, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी बाबूराम ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में संयोजक एडवोकेट सुबोध कनौजिया ने सभी उपस्थित श्रद्धालुओं एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सुनील कुमार, सुनील कुमार एआरपी, दीपक कनौजिया, सचिन पटेल, वेदराम राठौर, राजेन्द्र, एडवोकेट आदेश कुशवाहा, एडवोकेट अजीत कुमार आदि रहे।

बरेली न्यूरो एण्ड स्पाईन सुपर स्पेशलिटी सेंटर

डा. मोहित गुप्ता
M.Ch., Neurosurgery (AIIMS)
Senior Consultant Neurosurgeon
मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग विशेषज्ञ
Reg. No. UPMCI 65389
समय - प्रातः 10 से 12:30 बजे तक एवं सायं 6 से 8:30 बजे तक
अब डॉ. मोहित गुप्ता रविवार को भी मिलेंगे प्रातः 10 से दोपहर 1 बजे तक

सुविधायें
ब्रेन हैमरेज
स्लिप डिस्क
ब्रेन ट्यूमर
मिर्गी का दौरा
गर्दन दर्द (सर्वाइकल)
रीढ़ की चोट, टी.बी
सिर दर्द, माइग्रेन
कमर दर्द, कंधों में दर्द
पीठ दर्द, रीढ़ की गांठ
सिर की चोट (हेड इंजरी)
हाथ पैरों में झनझनाहट
फालिज (लकवा)
नसों का दर्द
सियाटिका (कमर से पैरों में दर्द)
दिमागी में पानी व खून जमना
दिमाग, रीढ़ एवं नस सम्बन्धित सभी बीमारियों का इलाज एवं ऑपरेशन
Bareilly Neuro and Spine Super Speciality Centre
Google Maps Location
सी-427, डिवाइन अस्पताल के सामने, के.के. अस्पताल रोड, राजेन्द्र नगर, बरेली
7417389433, 7017678157
9897287601, 8191879754

सांड़ के हमले से किसान की मौत

युवक को दौड़ाकर पटक दिया, जब तक मौत नहीं हो गई तब तक करता रहा हमला

- सांड के हमले में आठ लोगों की जा चुकी है जान कई हो चुके घायल

करन सिंह।

कार्यालय संवाददाता, शाहजहांपुर

मृतक करन के रोते बिलखते परिजन। • अमृत विचार

अमृत विचार : खेत पर फसल की रखवाली करने गए युवक ने खेत से सांड को भगाने का प्रयास किया तो उसने हमला कर दिया। युवक को सांड ने पटक पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को आनन-फानन में जलालाबाद सीएचसी पर ले गए। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों का रो रोकर बुराहाल है।

जलालाबाद थाना क्षेत्र के गांव हथिनापुर निवासी करन सिंह (28) रविवार की सुबह छह बजे खेत पर फसल में घुसे छुट्टा पशुओं को भगाने के लिए गए। उसके खेत में पशुओं का झुंड फसल चर रहा थे। करन ने पशुओं को भगाने का प्रयास किया। इसी बीच एक सांड ने करन पर हमला कर दिया। करन ने भागकर जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन सांड पीछे पड़ गया और टक्कर मारकर उसे जमीन पर गिरा लिया। इसके बाद करन को जमीन पर तब तक पटकता रहा।

गांव के लोग लाठी डंडा लेकर पहुंचे और सांड को किसी तरह भगाया। सांड के भाग जाने के बाद परिजन करन को जलालाबाद सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक करन सिंह की पत्नी विभा और दो बेटियों का रो-रोकर बुराहाल है। परिवार वालों ने जलालाबाद थाना पर सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह तोमर फोर्स के साथ गांव में गए और परिवार वालों से जानकारी की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इधर ग्रामीणों ने बताया कि गांव में छुट्टा पशुओं की संख्या बहुत है। पशु रात में फसल चर जाते है। सांड कई लोगों को घायल कर चुका है। कई बार प्रशासन पे अवारा पशुओं को पकड़वाए जाने की मांग कर चुके है।

छुट्टा पशु को बचाने के चक्कर में युवक घायल

कलान, अमृत विचार : नगर पंचायत के मोहल्ला गोपाल नगर निवासी प्रदीप शाक्य रविवार दोपहर को बाइक से गाढ़िया छवि मार्ग होते हुए अपनी बहन के यहां बदायूं के थाना उसहैत के गांव ग्राम खिरिया जा रहा था। सथरा गांव के आगे गौशाला के पास सड़क पर अचानक छुट्टा पशु आ गए। पशुओं को बचाने के प्रयास में बाइक का संतुलन बिगड़ गया और बाइक सहित वह गहरे खड्ड में गिर गया। हादसे में प्रदीप शाक्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

जलालाबाद में सांड़ के हमले में हुई मौतें

- 16 जून 22 को खेड़ा चौराहे पर के निकट 50 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति पर सांड ने हमलाकर के मार डाला था, शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी।
- 23 जनवरी 23 को कुंडरा गांव में खेत पर सांड को भगाने रीना देवी गयी थी, सांड ने हमला करके उसे मार डाला था।
- 12 फरवरी 23 को गांव हथिनापुर से शादी से लौट रहे थाना कांट के गांव कुर्रिया कला के योगेश की बाइक सांड से टकरा गयी थी, उनकी सीएचसी पर मौत हो गयी थी।
- 24 दिसंबर 23 को रैपुरा निवासी साधुराम खेत पर फसल की रखवाल करने गए थे। उन्होंने सांड को भगाया तो सांड ने हमला करके उसे मारडाला।
- 06 मार्च 24 को खाईखेड़ा चौराहे के निकट बाइक सांड से टकरा गयी थी, जिससे बाइक सवार सुमोध निवासी चंदौरा बहादुरपुर थाना जलालाबाद की मौत हो गयी थी।
- 21 अगस्त 24 को गांव गुलड़िया निवासी बिजय की बाइक ककराहा गांव के सामने सांड से टकरा गयी थी, जिससे उसकी मौत हो गयी थी।
- 17 अक्टूबर 25 को शिवरतन निवासी झरहरहरीपुर थाना जलालाबाद की बाइक सांड से टकरा जाने से मौत हो गयी थी।

मोबाइल हैक कर सात लाख की ठगी

शाहजहांपुर, अमृत विचारः पुलिस प्रशासन साइबर ठगी के लिए बराबर जागरुकता अभियान चला रहा है, उसके बाद भी ठगी का धंधा नहीं रुक रहा है। चीनी मिल कर्मचारी के मोबाइल हैक करके सात लाख 43 हजार 509 रुपये ठग लिए है। साइबर थाना में रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी है।

सदर बाजार थाना क्षेत्र के मोहल्ला बाडूजई द्वितीय निवासी पंकज कुमार ने साइबर थाना में दी गई तहरीर में बताया कि अजुबापुर चीनी मिल में काम करता हू। 12 जनवरी को उसके मोबाइल पर एम-परिवहन एप का लिंक आया। लिंक को क्लिक करने पर फोन हैक हो गया। कुछ देर बाद मोबाइल का नेटवर्क चला गया। उनको कुछ अहसास हुआ कि नेटवर्क में दिक्कत होगी। उन्होंने 24 घंटे तक नेटवर्क आने का इंतजार किया। उन्होंने उसी नंबर नया सिम कार्ड निकलवाया। वह सिम भी चालू नहीं हुआ। उन्होंने 15 जनवरी को एयरटेल कार्यालय में शिकायत की। उनको पता चला कि 12 जनवरी से 15 जनवरी तक सिम कार्ड कहीं और एक्टिव है। उसकी पत्नी के नाम खाता पंजाब सिंध बैंक में है। उनको पता चला कि उसके खाते और पत्नी के खाते से कुल मिलाकर 7 लाख 43 हजार 509 रुपये की ठगी हो गयी है।

वन विभाग का इंस्पेक्टर बनकर की अश्लील बात

संवाददाता, तिलहर

अमृत विचारः नगर निवासी महिला की तहरीर पर गांव गुरगवां निवासी अजय कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपी ने मोबाइल नंबर लेकर खुद को वन विभाग का इंस्पेक्टर बताकर अश्लील बातें कीं और जबरन शादी की धमकी दी। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। महिला के अनुसार 29 जनवरी को बच्चों को स्कूल से लाते समय आरोपी ने तमंचा दिखाकर जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। 30 जनवरी को बिरियागंज अंबेडकर पार्क के पास फिर से गलत हरकत करते हुए ले जाने का प्रयास किया, शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। कोतवाली प्रभारी जुगल किशोर पाल ने बताया कि आरोपी को अभिरक्षा में लेकर जांच शुरू कर दी गई है।

अफीम समेत तस्कर गिरफ्तार

शाहजहांपुर, अमृत विचार : बंडा पुलिस ने मादक पदाथ्र तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से 345 ग्राम अफीम, एक बाइक और 450 रुपये बरामद किए है। बंडा प्रभारी निरीक्षक प्रदीपक कुमार राय को शनिवार की शाम सूचना मिली कि मादक पदार्थ तस्कर चित्तरपुर नवदिया तिराहे पर खड़ा है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 345 ग्राम अफीम, एक बाइक और 450 रुपये बरामद किए है।

पीएचसी पर महिला ने किया हंगामा, दी तहरीर

कलान, अमृत विचार : प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रोगी को देखने पहुंची महिला ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में तैनात चौकीदार और सफाई कर्मी से अभ्रदता की। पीड़ित कर्मियों ने थाना पर तहरीर दी है। अस्पताल में तैनात सफाई कर्मी उमेश वाल्मीकि ने बताया कि अस्पताल में घायल रोगी को देखने के लिए महिला आई थी। उसने आते ही अभद्रता शुरू कर दी और जाति सूचक शब्द बोलते हुए गाली गलौज करने लगी। रजिस्टर फाड़ दिया, अस्पताल में रखी सिरिंज आदि सामान फेंक दिया। पीड़ितों ने बताया कि इससे पहले महिला प्रसव केंद्र पर भी कई बार हंगामा कर चुकी है। थाना में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

अवैध संबंधों में की गई कमलेश की हत्या

संवाददाता, शाहजहांपुर/अल्हागंज

- आरोपी के अनुसार कमलेश के उसकी पत्नी से थे संबंध
- मना करने के बाद भी नहीं मान रहा था

पुलिस हिरासत में आरोपी अनीस।

अमृत विचार : अल्हागंज थाना क्षेत्र के रावतपुर गांव निवासी कमलेश की हत्या उसी गांव निवासी अनीस ने की थी। अनीस को शक था कि कमलेश के उसकी पत्नी से अवैध संबंध हैं। रविवार को पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया। हत्यारोपी अनीस के पास से घटना में प्रयुक्त डंडा प्राप्त कर लिया है। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया।

अल्हागंज थाना क्षेत्र के गांव रावतपुर निवासी कमलेश (17) का खून से सना हुआ शव पंचायत भवन परिसर के बरामदे में मिला था। उसका सिर और चेहरा कूच कर हत्या की गई थी। गीता देवी का आरोप था कि शुक्रवार की शाम सात बजे गांव का ही उसका दोस्त अनीस घर से बुलाकर ले गया था। शनिवार सुबह को कमलेश का शव पंचायत भवन परिसर में मिला था। कमलेश के पिता जितेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके बेटे कमलेश की अज्ञात ने हत्या कर दी है। एसपी ने घटना के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया था। पुलिस की विवेचना में अनीस निवासी रावतपुर थाना अल्हागंज का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने अनीस को रावतपुर मोड़ से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ की। उसने कमलेश की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस आरोपी अनीस की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त डंडा तालाब के पास से बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान अनीस ने बताया कि कमलेश काफी दिनों से उसकी पत्नी से मिलता जुलता था। एक दिन आरोपी ने मोबाइल पर चेटिंग देखी तथा बातचीत करते हुए एवं प्रेम संबंध बनाते हुए देख लिया था। उसी दिन से कमलेश को निपटाने का मन बना लिया था। शुक्रवार को दोस्त कमलेश को विश्वास में लेकर घर से बुलाकर पंचायत भवन परिसर में ले गया। जहां बातचीत के दौरान डंडे से कमलेश के सिर और चेहरे पर डंडे से प्रहार करके हत्या कर दी थी। आरोपी ने डंडे को तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने अभियुक्त का चालान कर दिया। टीम में एसओ ओमप्रकाश, उप निरीक्षक राजेश कुमार, मुख्य आरक्षी अविनाश सिंह, विक्रम सैनी, सिपाही पवन कुमार थे।

MEDICAL Lifelines OF BAREILLY
अमृत विचार एक सम्पूर्ण अखबार
विज्ञापन हेतु सम्पर्क करें :- 8445507002

फोकस नेत्रालय
राजेन्द्र नगर, बरेली 731-098-7005
बरेली का सबसे बड़ा केवल आँखों के लिए समर्पित प्राइवेट अस्पताल ...
नवीनतम AI तकनीक एवं NABH मान्यता के साथ
- 40,000 से अधिक सफल सर्जरी सम्पन्न
- बिना इंजेक्शन एनेस्थीसिया (केवल आई ड्राप्स द्वारा)
- आयुष्मान/सीजीएचएस/ईसीएचएस/सीएपीएफ सभी स्वास्थ्य बीमा मान्य
- कैशलेस ईलाज

ADITYA आदित्य आई एण्ड लेजर सेन्टर
उपलब्ध सुविधायें :-
बिना सुई बिना टांका आधुनिक लेंस प्रत्यारोपण की सुविधा।
TPA कैशलेस सुविधा उपलब्ध
100000 से अधिक आंखों के आपरेशन का अनुभव
अल्ट्रासाउण्ड द्वारा पर्दे की जांच की सुविधा उपलब्ध
IOL Master 700 द्वारा लेंस का नम्बर
लेजर द्वारा आंख की झिल्ली हटाने की सुविधा उपलब्ध
बी स्कैन द्वारा पर्दे की जांच उपलब्ध
OCT द्वारा काला पानी एवं पर्दे की जांच व उपचार
8077344353
समय : प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक (सोमवार से शनिवार)
NABH PRE ACCREDITED
डॉ. आदित्य त्यागी
MBBS, DOMS, DNB, MNAMS
CARARACT REFRATIVE & GLAUCOMA SURGERON
आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए फ्री आपरेशन की सुविधा
ट्यूलिप ग्रांड के सामने, पीलीभीत बाईपास, बरेली

स्वास्थ्य जागरूकता अभियान
नि : शुल्क परामर्श
महीने के प्रत्येक रविवार को
समय : सुबह 10 से 5 बजे तक
कैम्प में समस्त ब्लड जाँचें, ई.सी.जी., एक्स-रे 50% के छूट पर किये जायेंगे।
रजिस्ट्रेशन शुल्क 20/-
प्रेमलोक हॉस्पिटल
नरियावल अड्डा, शाहजहाँपुर रोड, बरेली।
डॉ. दीपक माहेश्वरी
MBBS., MD, Consultant Physucuan & Critical Care Specialist
ब्लड प्रेशर, हृदय रोग श्वांस रोग, गम्भीर रोग विशेषज्ञ
9084307201, 9412244430
डॉ. नितिन अग्रवाल हृदय रोग विशेषज्ञ मो.9457833777

डॉ. हारिस अंसारी
एम.एस., एम.सी.एच. (यूरोलॉजी)
Consultant Urologist & Andrologist
गुर्दा, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली की पथरी व कैंसर सर्जन
- प्रोस्टेट (गदूद का आपरेशन) (TURP)
- गुर्दे की पथरी का आपरेशन (PCNL)
- गुर्दे की नली (यूरेटस) की पथरी का ऑपरेशन (URSC)
- पेशाब के समस्त प्रकार के रोगों का इलाज
कैशलेस, इंश्योरेंस, TPA व ESI आयुष्मान से अनुबन्धित अस्पताल
डॉ. एम. खान हॉस्पिटल
मल्टी स्पेशलिटी व क्रिटिकल केयर सेन्टर स्टेडियम रोड, निकट सेंट फ्रांसिस स्कूल, बरेली
हेल्पलाईन 9897838286, 9837549348

वरुण-अर्जुन मेडिकल कॉलेज की ओर से दो स्थानों पर लगाए गए स्वास्थ्य कैंप

कटरा में आयोजित नि :शुल्क शिविर में मरीजों की जांच करते चिकित्सक।

खिरिया सकतू में वरुण-अर्जुन मेडिकल कॉलेज की ओर से लगाया स्वास्थ्य कैंप।

कार्यालय संवाददाता, शाहजहांपुर

- रोगियों को नि:शुल्क दवा की गई वितरित, बांटे गए कूपन और दी चिकित्सीय सलाह
- मीरानपुर कटरा में 156 और खिरिया सकतू में 136 रोगियों का किया गया परीक्षण

अमृत विचारः वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज एवं रोहिलखंड अस्पताल बंथरा की ओर से संचालित ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस थाना नखासे के सामने मीरानपुर कटरा और खिरिया सकतू गांव में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। दोनों स्थानों पर लगे शिविर में 292 रोगियों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से पांच मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। वहीं खिरिया सकतू में हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया और जागरूक किया गया। सभी मरीजों का ऑपरेशन रोहिलखंड अस्पताल में निःशुल्क किया जाएगा।

शिविर के दौरान सभी मरीजों को निःशुल्क आई ड्रॉप और दवाइयां वितरित की गईं। चिकित्सकों की ओर से लोगों को नियमित नेत्र परीक्षण कराने के लिए जागरूक किया गया और नेत्र रोग विभाग में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी गई। बताया गया कि अस्पताल में काला मोतियाबिंद, कार्निया की बीमारी, आंख के पर्दे की जांच और इलाज, मोतियाबिंद ऑपरेशन चीरा विधि और फेको विधि से, भेंगापन, नासूर, नाखूना जैसी आंखों की बीमारियों के इलाज और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही कंप्यूटर के माध्यम से चश्मे के नंबर की जांच और प्रमाणीकरण की सुविधा सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं खिरिया सकतू में परिवार दत्तक कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान मरीजों को निःशुल्क दवाइयां वितरित की गईं और रक्त जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही हेपेटाइटिस-बी का टीकाकरण किया गया। ग्रामीणों को हेपेटाइटिस-बी रोग के लक्षण, कारण, बचाव और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व सामुदायिक चिकित्सा विभागाध्यक्ष डॉ. धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता की ओर से किया गया। उनके साथ विभाग के डॉ. आदित्य प्रकाश, डॉ. विनायक और डॉ. अतुल सक्सेना मौजूद रहे। अन्य विभागों से जनरल मेडिसिन के डॉ. अर्सलान और नेत्र रोग विभाग की डॉ. शुभांगी ने भी सहयोग प्रदान किया। शिविर को सफल बनाने में स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन और मेडिकल सोशल वर्कर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वास्थ्य सेवाएं मिलने पर ग्रामीणों ने प्रसन्नता जताई और भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाने की मांग की।

स्वास्थ्य कार्ड की दी जानकारी

चिकित्सकों ने यह भी जानकारी दी कि वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज एवं रोहिलखंड अस्पताल में परिवार स्वास्थ्य कार्ड की सुविधा मात्र 200 रुपये में उपलब्ध है, जो एक वर्ष के लिए मान्य होती है। शिविर में नेत्र रोग विभाग की डॉ. स्वप्निल, सामान्य रोग विभाग के डॉ. राजेश, महिला एवं प्रसूति रोग विभाग की डॉ. तपस्या, नेत्र टेक्नीशियन, पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सोशल वर्कर मोहित थापा मौजूद रहे

दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत, दो लोग घायल

खुटार, अमृत विचारः नगर के मोहल्ला सरोजनीनगर में रहने वाले मोहनलाल वर्मा अपनी बाइक से तिकुनिया जा रहे थे। तभी पंजाब टेंट हाउस के सामने तिकुनिया की ओर से तेज रफ्तार से आ रहे के पुवायां के गांव जेवा में रहने वाले लालजीत उर्फ आदेश अवस्थी की बाइक मोहन की बाइक से तेजी से टकरा गई। दोनों वाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टकराव के बाद वहां आसपास के लोग जमा हुए। लोगों ने दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुटार पहुंचाया वहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। जहां से हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें जिला अस्पताल शाहजहांपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। आदेश अवस्थी की हालत गंभीर बताई जा रही है।

न्यूज ब्रीफ

श्रीकृष्ण-सुदामा का मिलन प्रसंग सुन भाव भावुक हुए श्रद्धालु

ओरछी, अमृत विचार : फैजगंज बेहटा के गांव सिसरका के शिव मंदिर टावर के पास चल रही श्रीमद्भागवत कथा के सातवें दिन भक्ति और भाव का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा व्यास आचार्य महेंद्र पाठक ने भगवान श्रीकृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा के मिलन का प्रसंग सुनाया तो पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं। जीवंत अभिनय ने बांधा समां कथा के दौरान सुदामा चरित्र का मंचन आकर्षण का केंद्र रहा। उप आचार्य बलराम शर्मा ने सुदामा और नितिन व ओंकार सिंह ने द्वारपाल की भूमिका निभाकर कथा को जीवंत किया। आयोजन में मुख्य रूप से अमित सिंह, नीतू सिंह, उदयभान सिंह, राजवीर सिंह, वीरपाल सिंह, अतवीर सिंह, चंद्र प्रकाश उर्फ चीकू मिश्रा और सुमित सिंह मौजूद रहे। अंत में आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया।

आपत्तिजनक पोस्ट डाल रहा युवक, शिकायत

कादरचौक, अमृत विचार : कादरचौक क्षेत्र के गांव बेहटा डंबर निवासी युवक अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर आपत्तिजनक स्टोरी डाल रहा है। उसने बनिया, स्वर्ण और पंडित जाति के लोगों के लिए गाली-गलौज लिखी। जिससे गांव में तनाव की स्थित पैदा हो गई है। इसके अलावा वह मुख्यमंत्री के खिलाफ भी अभद्र व आपत्तिजनक पोस्ट कर चुका है। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अपने आचरण में सुधार की बजाय वह अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है। लोगों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

प्रतियोगिता में 200 छात्र छात्राओं ने लिया भाग

बिल्सी, अमृत विचार : नगर बिल्सी के मोहल्ला तीन स्थित सिटी हार्टमैन जूनियर हाईस्कूल में रविवार को शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा छह से लेकर कक्षा 12 तक के करीब 200 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संस्था की अध्यक्ष डॉ. सुचित्रा गुप्ता ने बताया कि सोसाइटी पिछले लगभग दो साल से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रही है। अमित कुमार, पूजा शर्मा, नेहा गुप्ता, राजेश वर्मा आदि स्टाफ का सहयोग रहा।

केंद्रीय बजट से विकास को मिलेगी गति, आत्मनिर्भर बनेगा भारत

सत्ता पक्ष ने सराहा, विपक्षी दलों ने पूंजीपतियों का बताया बजट, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव न होने से व्यापारियों को मिली निराशा

कार्यालय संवाददाता, बदायूं

अमृत विचार : मोदी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। जिस पर लोगों ने अपनी प्रक्रिया व्यक्त की। व्यापारियों और महिलाओं ने बजट को संतोषजनक बताया। टैक्स स्लेब में बदलाव न होने पर निराशा जताई। महिलाओं ने रसोईगैस की कीमतें कम न किए जाने पर दुख प्रकट किया। वहीं सत्ता पक्ष ने बजट को विकास की गति देने वाला बताया। तो विपक्षी दलों ने पूंजीपूतियों वाला बताया। कहा कि इसमें न रोजगार पर ध्यान रखा गया है। और न ही किसानों सहुलियतों को पूरा करेगा।

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में महिलाओं सशक्ति बनाने पर जोर दिया गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लघु उद्योग को बढ़ावा दिए जाने कई योजनाएं शुरू किए जाने पर बल दिया है। पूंजीगत सामान की क्षमता बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। हाईटेक टूल रूम स्थापित होंगे और कंटेनर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। वस्त्र क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू की गई है, जिससे रेशम, ऊन, जूट और आधुनिक फाइबर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मजबूती देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई है।

लोगों की क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और उच्च मूल्य वाली फसलों पर जोर दिया गया है। लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न ही रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को कम किया गया है। जिस पर व्यापारियों और महिलाओं ने निराशा व्यक्त की है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, उनमें कुछ अच्छी बातें जरूर हैं। उन्होंने कहा कि दवाइयों की बढ़ती कीमतों को लेकर जो बातें बजट में कही गई हैं, वह एक अच्छा कदम है। अगर वाकई इन घोषणाओं को ठीक से लागू किया जाता है तो आम लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं महिलाओं का कहना है कि सरकार की सभी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन इस बजट से कहीं भी महंगाई कम होती नजर नहीं आ रही है। अगर घरेलू खर्च में लगने वाले पैसे और कम हो जाते तो राहत होती। महिलाएं बजट से तो संतुष्ट दिखी, लेकिन महंगाई पर अब भी उनकी नाराजगी भी दिखी।

संसद में पेश केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत की दिशा में सुधारों की गति को तेज करने के लिए तीन कर्तव्यों वाला सुद्रण ब्लूप्रिंट है। यह कर्तव्य, उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर तथा अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में सुदृढ़ता का निर्माण कर आर्थिक विकास की गति को तेज कर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। साथ ही उनकी क्षमता का विकास कर भारत की समृद्धि की राह में उन्हें एक सशक्त साझेदार बनाने वाला बजट है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सिद्ध करने वाला बजट है। – **राजीव गुप्ता**, भाजपा जिला अध्यक्ष

देश आज महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की बदहाली से जूझ रहा है, लेकिन यह बजट आम जनता को राहत देने के बजाय कॉरपोरेट हितों को संरक्षण देने का दस्तावेज बनकर रह गया है। पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर सरकार ने जनता को पूरी तरह निराश किया है। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी न देना यह साबित करता है कि सरकार की प्राथमिकता किसान नहीं, बल्कि बड़े उद्योगपति हैं। युवाओं के लिए स्थायी रोजगार का कोई ठोस रोडमैप नहीं है, केवल प्रशिक्षण और योजनाओं के खोखले वादे किए गए हैं। – **आदित्य यादव**, सपा सांसद बदायूं

आज बजट में सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया, जो इतना बड़ा राज्य है जहां किसान, मजदूर और गरीब लोग रहते हैं। उनके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई, उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया, और उनका जिक्र तक नहीं हुआ। मुझे लगता है कि देश के गरीब, कमजोर और आम लोग निराश हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, शेयर बाजार धराशायी हो गया है और कमोडिटी बाजारों को भारी नुकसान हुआ है। इस बजट में आम जनमानस के लिए कोई राहत नही दी गयी है।

– **नीरज मौर्य**, सांसद आंवला

2026-207 केंद्रीय बजट जन कल्याणकारी एवं सर्वांगीण विकास का बजट है। यह बजट आज के सपनों को साकार करने के साथ साथ 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का रोडमैप है। यह युवा शक्ति, महिलाओं और किसानों को समर्पित बजट है। इस बजट से किसानों की आय बढ़ेगी। किसान क्रेडिट कार्ड में ऋष की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख करने का प्रावधान है। महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। दिव्यांगों के लिए शुरू होने वाली योजनाएं लाभकारी होगीं।

– **बीएल वर्मा**, राज्यसभा सांसद

बजट में शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने का प्रावधान किया गया है। जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। एलआरएस के तहत शिक्षा और मेडिकल खर्च पर टीसीएस 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने से लोगों को राहत मिलेगी। सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने से देश के विकसित राष्ट्र बनने के सपने को पंख लगेंगे और आम जनता को सीधा फायदा मिलेगा। एमएसएमई के लिए 10000 करोड रुपये देकर छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया है। सरकार को महंगाई नियंत्रित करने और टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए। – **केबी गुप्ता**, जिलाध्यक्ष उप्र उद्योग व्यापार मंडल

भारत को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को ध्यान में रखा गया। यह आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को व्यक्त कर रहा है। गंभीर बीमारियों (कैंसर, शुगर आदि) के लिए दवाईयां सस्ती की गई हैं इसका सकारात्मक प्रभाव आम आदमी पर होगा। नौकरी पेशा को तथा इनकम टैक्स दाताओं को कोई राहत न देना निराशाजनक है। – **माधव मिश्र**, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

यह बजट महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता से जुड़े पहलुओं को संवेदनशीलता के साथ सामने लाता है। महिला सशक्तिकरण को सामाजिक विकास से जोड़ने की दृष्टि साहित्यिक और मानवीय मूल्यों के अनुरूप है। समावेशी सोच और संतुलन इस बजट की उल्लेखनीय विशेषता है। बजट 2025 भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा।

– **डॉ. दीप्ति जोशी**, साहित्यकार

बजट 2026 आशा और निराशा का मिला जुला समन्वय है। आम आदमी के लिए इंकम टैक्स में कोई संशोधन नहीं किया गया, जिससे मिडल क्लास को निराशा हाथ लगी। इसी के साथ बजट 2025 भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगा। चिकित्सीय सुविधाएं, विदेशी यात्रा सस्ती, गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था आदि सराहनीय प्रावधान है।

– **प्रीति अरोरा**, गृहणी

मजबूत करने के साथ-साथ भारतीय उद्योग, स्टार्टअप्स, किसानों और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। इस बार का बजट भारत की आर्थिक वृद्धि, सुधार और वित्तीय अनुशासन को संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और घरेलू विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बजट में विकास और समावेशी नीतियों का संतुलन रखा है। – **शीराज आलम**, अधिवक्ता

केंद्रीय बजट 2026-2027 तात्कालिक लाभों से ऊपर उठकर दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण की सशक्त नींव रखता है। सतत विकास, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, व्यापक रोज़गार सृजन तथा भविष्यदृष्टि से परिपूर्ण निवेश के माध्यम से यह बजट आने वाले दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर, मजबूत और प्रगतिशील बनाने का संकल्प दर्शाता है। – **पार्थ कुमार**, युवा उद्योगपति/आर्थिक विश्लेषक

केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया बजट किसानों को धोखा देने वाला है। यूरिया खाद का कट्टा 40 किलो कर दिया। महंगाई बड़ी परंतु किसान सम्मन निधि में कोई वृद्धि नहीं हुई। गरीब गांव की जनता के लिए कुछ भी हाथ में नहीं आया। यह बजट विदेशी कंपनी और उद्योगपति पूंजी पतियों वाला बजट है। सरकार को एमएसपी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। – **राजेश कुमार सक्सेना**, भाकियू मंडल प्रवक्ता

बजट में स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों को लेकर की गई घोषणाओं से बहुत उम्मीदें हैं। इसका असर जमीन पर दिखना चाहिए। जमीन पर असर होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और युवाओं को रोजगार मिलेगा। – **अमित गुप्ता**

विद्यार्थियों के लिए बजट राहत देने वाला है। फीस, कोचिंग और रहने के बढ़ते खर्च को देखते हुए छात्रों के लिए और राहत की जरूरत है। शिक्षा के साथ-साथ रोजगार की गारंटी मिले। साथ ही उनके लिए एक स्पष्ट रोडमैप शामिल होता तो और अधिक रहता। – **पुष्पराज सिंह**

बजट में रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास की बात कही गई है। स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया जैसे क्षेत्रों को लेकर भी घोषणाएं हुई हैं। इन योजनाओं का असर तभी दिखेगा, जब इन्हें जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू किया जाए। – **सुमित शाक्य**

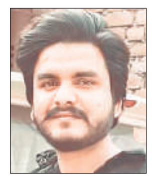

केंद्र सरकार का बजट संतुलित बजट है। इसमें युवाओं, बेरोजगारों और महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। नए कॉलेज खुलेंगे। इनमें युवाओं को सीखने का मौका मिलेगा। स्टार्टअप से नए रोजगार के अवसर खुलेंगे।

– **हामिद रसूल**

बजट में महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास की धुरी के रूप में देखा गया है। स्वरोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे।

– **शिल्पी रस्तोगी**, साहित्यकार

केंद्रीय बजट 2026-27 शिक्षा और युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने वाला है। छात्रों की सीखने की संभावनाओं और अवसरों को बढ़ावा देने वाले प्रावधान समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार होंगे। – **डॉ. श्रद्धा गुप्ता**, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय

बजट को लेकर पदाधिकारियों ने रखे विचार

संवाददाता, कादरचौक

अमृत विचार : ब्लॉक परिसर में रविवार को केंद्रीय बजट 2026-27 का सीधा प्रसारण देखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। बजट में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी नवाचार और मध्यम वर्ग को राहत देने पर विशेष जोर दिया गया है। अन्य घोषणाएं भी की गई हैं।

सरकार ने बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। साथ ही देश के शहरों को जोड़ने के लिए 7 हाई-स्पीड कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सरकार के बजट की प्रशंसा की। ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र राजपूत, विजय गुप्ता, राजेश गुप्ता, अश्विन कुमार गुप्ता, सर्वेश कश्यप, राकेश माहेश्वरी, योगेश मौर्य, राहुल शाक्य सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने बजट भाषण सुना।

2026 का केंद्रीय बजट देश के विकास और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है, जिसमें 12.2 लाख करोड़ का भारी निवेश घोषित किया गया है। यह बजट टियर-2/3 शहरों, युवाओं और किसानों के लिए एक विकासवादी कदम है, जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को गति देने का प्रयास करता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे, तकनीक और शिक्षा पर बड़ा जोर दिया गया है।

– **राजेश यादव**, भाजपा जिला प्रभारी मुरादाबाद नगर

इस बजट में हमेशा की तरह सरकार ने सभी को साधने की कोशिश की है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बजट में बड़े सुधार, बड़ी घोषणाओं की गई हैं। जमीन पर उतरने के बाद ही हकीकत सामने आएगी। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साधने में सक्षम दिख रहा है साथ ही ये ट्रम्प के टेरिफ को भी बेअसर करेगा।

– **मुकेश वशिष्ठ**, जिला महामंत्री, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन

इनकम-टैक्स स्लैब में कोई बड़ी कटौती नहीं की गई है। हालांकि टैक्स प्रोसेस को आसान बनाना, रिफंड जल्दी मिलने और ऑटोमैटिक संज्ञान सुधार जैसी व्यवस्था व्यापारियों को अप्रत्यक्ष लाभ दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी टैक्स उल्लंघन को अब आपराधिक दण्ड से हटाकर अर्थदण्ड के रूप में बदल दिया गया है।

– **सुमित गोयल**, एडवोकेट

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने रविवार को नौवा बजट पेश किया है। अब तक इनके द्वारा जो भी बजट पेश किए गए हैं। उन सभी में किसानों को कुछ नहीं मिला। नौवे बजट में भी किसानों की तकलीफों का ध्यान नहीं रखा गया। सरकार किसानों से जुड़ने के स्थान पर एआई से जोड़ने की बात कह रही है।

– **ऋषभ चौधरी**, भारतीय किसान यूनियन

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट से मध्यम वर्गीय कर्मचारी वर्ग को निराशा हुई हैं। आयकर की सीमा में कोई भी छूट नहीं दी गई है। जिससे उसकी दिक्कतें और बढ़ेगी।
– **राजकुमार शर्मा**, जिला मंत्री प्रधानाचार्य

भाजपाईयों ने केंद्रीय बजट का देखा सीधा प्रसारण

केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण देखते भाजपा नेता और कार्यकर्ता।

संवाददाता, उसावां

अमृत विचार : केंद्र सरकार ने रविवार को आम बजट पेश किया। इसका सीधा प्रसारण भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नगर अध्यक्ष के आवास पर देखा।

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2026-27 के लिए राज्यों को बजट आवंटित हुए विकसित भारत बजट भाषण के अंतर्गत प्रस्तुतीकरण का लाइव प्रसारण नगर पंचायत उसावां चेयरमैन के आवास पर देखा गय। इसके उपरांत भाजपा नेता शैलेश पाठक ने कहा कि आज भारत का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। भारत तेजी से आगे बढ़कर पूरे विश्व के लिए चुनौती बन गया है। डबल इंजन की सरकार जनहित में लोक कल्याणकारी निर्णय ले रही है। इस अवसर पर अध्यक्ष नगर पालिका पति अनिल सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के हितों का संरक्षण करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री हेश राठौर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर राहुल लोधी, सन्तोष गुप्ता, पंकज कुमार मिश्रा, पवन गुप्ता, धनमेश कश्यप आदि उपस्थित रहे।

सब तो ठीक, मगर महंगाई से नहीं मिली राहत

बदायूं, अमृत विचार : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट पेश किया। इस बजट में युवा, महिलाओं, किसानों और विकास से जुड़े कई ऐलान किए गए हैं। इस बजट में महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और और आत्मनिर्भरता पर पूरा फोकस किया गया है। बजट पेश होने के बाद महिलाओं ने इसे अच्छा बताया है। वहीं मंहगाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि महंगाई भी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। उसमें कोई रियायत नहीं मिली है।

अमृत विचार एक सम्पूर्ण अखबार
क्लासीफाइड
विज्ञापन हेतु सम्पर्क करें
9756905552, 8445507002

[illegible]

आवश्यकता है
अनुभवी व्यक्तियों की
- आयुष्मान मित्र
- पी.आर.ओ. (पब्लिक रिलेशन ऑफिसर)
- कंप्यूटर ऑपरेटर
- सिक्यूरिटी गार्ड
- कुक (रसोइया)/कुक हेल्पर

वेतन योग्यतानुसार
सम्पर्क करें
एच.आर. ऑफिस एडमिन ब्लाक
वरूण अर्जुन मेडिकल कॉलेज एवं रोहिलखण्ड अस्पताल
एन.एच.-30 बन्थरा, शाहजहाँपुर
समय : प्रातः 10 बजे से सायं 04 बजे तक
मो. 7521001986

सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पासपोर्ट सं. T5211436 में मेरा नाम भूलवश MOHAMMAD SOHAIL दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम MOHAMMAD SOHAIL KHAN है। आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी मेरा नाम MOHAMMAD SOHAIL KHAN ही दर्ज है। मो. सोहेल खान पुत्र श्री मोईन मियां निवासी मो. मुनीर खां तह. व जिला पीलीभीत।

वैधानिक सूचना :- समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन जैसे टावर सम्बन्धी, नौकरी सम्बन्धी, ऋण सम्बन्धी या अन्य किसी भी प्रकार के विज्ञापन में पाठकों को सावधान किया जाता है। विज्ञापनदाता द्वारा किये गये दावे या उल्लेख, समर्थन की पुष्टि समाचार पत्र नहीं करता है।

सपने को साकार होने से रोकने वाली एकमात्र चीज है– असफलता का भय।

–पाउलो कोएल्हो, ब्राजीलियन लेखक

संप्रभुता पर सख्त

देश के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा यह स्पष्ट कहना कि तथाकथित 'चिकन नेक' भारत की भूमि है और इस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक गंभीर रणनीतिक संकेत है। बयान बताता है कि केंद्र सरकार 22 किलोमीटर चौड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर अत्यंत सतर्क और इसकी रक्षा के लिS आक्रामक रुख रखती है। 'चिकन नेक' पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से जोड़ने वाली एकमात्र स्थलीय कड़ी है। इसके पश्चिम में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश और उत्तर में भूटान तथा चीन का प्रभाव क्षेत्र है। यदि इस संकरी पट्टी की सुरक्षा में कोई व्यवधान आता है, तो आठ पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक और सामरिक निरंतरता पर प्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। इस दृष्टि से इसे रणनीतिक संप्रभुता का मामला माना जाना चाहिए।

गृहमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि दिल्ली में कुछ तत्वों ने इस कॉरिडोर को 'काट देने' जैसे नारे लगाए थे। उनके बयान पर केंद्र की कड़ी प्रतिक्रिया यह संदेश देती है कि राष्ट्रीय एकता और भौगोलिक अखंडता पर कोई भी सार्वजनिक उकसावा अब सहन नहीं किया जाएगा और राजनीतिक विमर्श की आड़ में सामरिक संवेदनशीलता को हल्के में लेने वालों के साथ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा भी इसी व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा है। जहां भूमि संबंधी विवाद हैं, वहां केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, हलांकि केवल भूमि का मुद्दा ही बाधा नहीं है; तकनीकी सर्वेक्षण, सीमा निर्धारण के अंतर्राष्ट्रीय समझौते और स्थानीय विरोध भी प्रक्रिया को धीमा करते हैं। असल में सीमा प्रबंधन में भूमि अधिग्रहण, स्थानीय प्रशासन का सहयोग, पर्यावरणीय स्वीकृतियां तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रोटोकॉल जैसे जटिल पहलू शामिल होते हैं। कई स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में देरी एक व्यावहारिक बाधा रही है, पर यह पूरी कहानी नहीं है। नदियां, आबादी का घनत्व, तस्करी की चुनौतियां और सीमा पर रहने वाले नागरिकों के आजीविका संबंधी प्रश्न भी बाड़बंदी को जटिल बनाते हैं। इसलिए दूसरी सीमाओं, विशेषकर कुछ हिस्सों में भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमा पर भी पूर्ण बाड़बंदी अभी बाकी है।

भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आती तो भी बाड़ तो लगेगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी एक दल के शासन पर निर्भर नहीं हो सकती। संवैधानिक ढांचे के भीतर केंद्र सरकार के पास सीमा सुरक्षा के पर्याप्त अधिकार हैं। किंतु प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार का सहयोग अनिवार्य होता है। बेहतर समाधान यह होगा कि इसे चुनावी मुद्दा बनाने के बजाय सर्वदलीय सहमति और केंद्र–राज्य समन्वय के जरिए आगे बढ़ाया जाए। गृहमंत्री का बयान केवल चुनावी आरोप-प्रत्यारोप नहीं माना जाना चाहिए। यह उस बदलते सुरक्षा वातावरण की स्वीकृति है, जिसमें हाइब्रिड युद्ध, सूचना युद्ध और आंतरिक अस्थिरता के प्रयास समान रूप से गंभीर खतरे हैं। 'चिकन नेक' केवल एक भूगोल नहीं, भारत की पूर्वोत्तर नीति, 'एक्ट ईस्ट' रणनीति और सामरिक आत्मविश्वास का प्रतीक है, इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक शोर से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के ठोस, संस्थागत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना समय की मांग है।

प्रसंगवश

एक संन्यासी ने हजारों आंखों में भर दी रोशनी

पंजाब के एक छोटे से गांव से निकले एक साधारण युवक ने संन्यास का मार्ग चुना और राजस्थान में पहुंच कर भक्ति के साथ जन सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने अपने तप, त्याग व करुणा से हजारों लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया। वह युवक संत स्वामी ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है। गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने उन्हें पदमश्री प्रदान देने की घोषणा की है। उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि उस विचारधारा पर मुहर है, जिसमें सेवा को साधना और मानवता को धर्म माना जाता है।

पंजाब के मोगा जिले की निहाल सिंह वाला तहसील में एक छोटा सा गांव है- रौंता। इस गांव से एक दिन एक युवक निकला, लेकिन उसने दुनिया से कुछ पाने का नहीं बल्कि दुनिया को कुछ लौटाने का रास्ता चुना। यह युवक आगे चलकर स्वामी ब्रह्मदेव के नाम से विख्यात हुआ। स्वामी ब्रह्मदेव ने संन्यास लिया, लेकिन समाज से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने पीड़ित मानवता की पीड़ा को देखा। उन्होंने 1963 में जब अमृतसर में श्री दुर्ग्याना मंदिर में अंध विद्यालय को देखा तो ऐसा ही कोई काम करने का संकल्प किया।

अमरपाल सिंह वर्मा
वरिष्ठ पत्रकार

अपनी शिक्षा पूर्ण कर वह 1978 में राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक मंदिर में आए। यहीं से शुरू हुई श्री जगदंबा अंध विद्यालय की कहानी। शुरुआत बहुत साधारण थी। कोई बड़ी इमारत नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं। थे तो बस कुछ अच्छे लोग और स्वामी जी का अटूट भरोसा। जन सहयोग से रोपा गया एक छोटा सा पौधा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही पौधा एक दिन वटवृक्ष बन जाएगा।

वर्ष 1980 में उन्होंने जगदंबा अंध विद्यालय की आधारशिला रखी। जगदंबा अंध विद्यालय की शुरुआत केवल एक बच्चे और एक शिक्षक के साथ हुई थी, लेकिन आज वह वटवृक्ष बन चुका है। बीते साढ़े चार दशकों में उन्होंने सात हजार से ज्यादा दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षित किया है। मूक-बधिर बच्चों के लिए चार दशक से स्कूल भी चल रहा है। स्वामी ब्रह्मदेव ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें जीना भी सिखाया। नेत्रहीन और मूक-बधिर बच्चों के हाथ में हुनर दिया, साथ में आत्म विश्वास भी दिया। आज उस विद्यालय से पढ़े अनेक बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं।

स्वामी जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो जन्म से अंधे नहीं हैं, बस आर्थिक संकट के कारण इलाज नहीं करा पाए। यहीं से शुरू हुआ मोतियाबिंद ऑपरेशन का काम। वर्ष 1993 में स्थापित श्री जगदंबा आई हॉस्पीटल में अब तक साढ़े चार लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर उनकी आंखों की रोशनी बचाई जा चुकी है। साढ़े चार लाख का यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं है। यह साढ़े चार लाख घरों में लौटी उम्मीद है। स्वामी ब्रह्मदेव ने समाज को एक और गहरी बात सिखाई है, वह है मरणोपरांत नेत्रदान। उन्होंने लोगों को समझाया कि मौत के बाद भी किसी की जिंदगी रोशन की जा सकती है। धीरे-धीरे यह बात लोगों के दिलों में उतरती गई। सालों से संस्था के जरिए नेत्रदान करा कर जरूरतमंदों को नेत्र प्रत्यारोपित किए जाते हैं।

स्वामी ब्रह्मदेव का जीवन दिखावे से दूर रहा है। वह कथा-कीर्तन करते हैं, चढ़ावे में आया धन सेवा में लगा देते हैं। न कोई शोर, न कोई प्रचार। वही सादा वेश, वही सरल बोलचाल। वे खुद संस्था में मौजूद रहते हैं, काम देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। उनके लिए सेवा कोई परियोजना नहीं है, जीवन का स्वभाव है। पदमश्री मिलने के बाद भी उन्होंने श्रेय खुद नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान प्रभु की कृपा और जनता के निःस्वार्थ सहयोग का प्रतिफल है।

आम बजट 2026 विकास व अनुशासन का संतुलन

रजत मेहरोत्रा
वित्तीय एवं आर्थिक विशेषज्ञ

केंद्रीय बजट 2026-27 केवल सरकार का हिसाब-किताब नहीं, बल्कि यह बताता है कि आने वाले समय में देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। दुनिया में व्यापार तनाव, तकनीकी बदलाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच सरकार ने इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है। सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाकर लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये किया है और यह लक्ष्य रखा है कि देश का कुल कर्ज (Debt/GDP) अनुपात को बजट अनुमान 2026-27 में GDP के 55.6 % के रूप में आंका गया है, जबकि संशोधित अनुमान 2025-26 में यह 56.1% था। Debt-to-GDP अनुपात में गिरावट का अर्थ है कि समय के साथ सरकार को ब्याज भुगतान पर कम खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सरकार खर्च भी करेगी और कर्ज को भी नियंत्रण में रखेगी।

बजट में राजकोषीय घाटा लगभग 4.3% ऑफ जीडीपी के स्तर पर रखने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि इससे देश की आर्थिक सेहत मजबूत होती है। जब सरकार का घाटा घटता है, तो उसे कम उधार लेना पड़ता है और ब्याज पर होने वाला खर्च भी कम होता है। इसका सीधा फायदा यह होता है कि सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी क्षेत्रों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। घाटा कम होने से महंगाई पर भी दबाव घटता है। इसके अलावा, जब फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में रहता है, तो विदेशी निवेशकों और रेटिंग एजेंसियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है, जिससे देश में निवेश आता है और रुपया भी मजबूत रहता है। कुल मिलाकर, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट घटाने का उद्देश्य केवल हिसाब संतुलित करना नहीं है, बल्कि भविष्य में विकास के लिए स्थायी और भरोसेमंद आर्थिक आधार तैयार करना है।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट को आय स्थिरता व जोखिम प्रबंधन का बजट कहा जा सकता है। सिंचाई परियोजनाओं, कृषि अवसंरचना और वेयर हाउसिंग नेटवर्क के विस्तार से फसल नुकसान कम होगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी। एग्री-लॉजिस्टिक्स और कोल्ड-चेन पर निवेश बढ़ाकर कृषि उत्पादों की बर्बादी घटाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म और फसल बीमा कवरेज के विस्तार से किसानों की आय में स्थिरता आएगी। कृषि-आधारित एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्धन और रोजगार दोनों बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है।

छात्रों और युवा शक्ति के लिए यह बजट 'शिक्षा से रोजगार' की कड़ी को मजबूत करता है। डिजिटल शिक्षा अवसंरचना, स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक लैब तथा उद्योग से जुड़े कौशल कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। शिक्षा और मेडिकल शिक्षा से जुड़े टीसीएस प्रावधानों को घटाकर 2% किए जाने से विदेश में अध्ययन करने वाले मध्यम वर्गीय छात्रों को सीधी राहत मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल डिग्री उत्पादन नहीं, बल्कि रोजगार योग्य युवा तैयार करना है, ताकि जनसंख्या लाभांश वास्तविक आर्थिक शक्ति बन सके। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बजट में केंद्रीय स्थान मिला है। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण, बीमा और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने से महिलाओं की भागीदारी औपचारिक अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2026 संजीवनी जैसा है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का एमएसएमई ग्रोथ फंड घोषित किया है, जिससे छोटे उद्योगों को सस्ता ऋण और विस्तार का अवसर मिलेगा। यह क्षेत्र देश में 11 करोड़ से अधिक रोजगार देता है, इसलिए इसमें निवेश सीधे रोजगार सृजन से जुड़ा है। एमएसएमई के डिजिटलीकरण और निर्यात क्षमता बढ़ाने से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकेगा। कपड़ा और टेक्सटाइल उद्योग के लिए बजट ने पूरी वैल्यू चेन- फाइबर से फैशन तक को मजबूत करने का रोडमैप दिया है। नई नेशनल फाइबर स्कीम से उत्पादन लागत घटेगी और गुणवत्ता बढ़ेगी। भारत का टेक्सटाइल निर्यात पहले ही लगभग 40 अरब डॉलर के स्तर पर है और इस नीति से इसमें और वृद्धि की संभावना बनेगी। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। इससे पलायन कम होगा।

सरकार ने सात नए रेल कॉरिडोर और टियर-2 शहरों पर फोकस की घोषणा की है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी। उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। रेलवे में निवेश का गुणक प्रभाव स्टील, सीमेंट और निर्माण उद्योग पर पड़ता है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव है। आईटी, एआई और डेटा सेंटर नीति बजट 2026 की सबसे रणनीतिक घोषणाओं में से एक है। सरकार ने एआई के लिए 'पिक एंड शोवेल' अप्रोच अपनाई है यानी सीधे एप्लिकेशन पर नहीं, बल्कि अवसंरचना पर निवेश। विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करने पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने की घोषणा की गई है, बशर्ते वे भारतीय रीसेलर्स का उपयोग करें। इससे भारत ग्लोबल डेटा हब बनने की दिशा में बढ़ेगा और आईटी सेक्टर में उच्च-मूल्य रोजगार सृजित होंगे।

स्वास्थ्य और बायो-फार्मा सेक्टर को बजट में नई ऊर्जा मिली है। अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये की 'बायोफार्मा शक्ति' पहल से अनुसंधान, विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मेडिकल टूरिज्म, आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक सेवाओं और पोस्ट-केयर सुविधाओं के विस्तार से भारत वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभर सकता है। वर्तमान में मेडिकल टूरिज्म बाजार लगभग 9-10 अरब डॉलर का है, जिसे कई गुना बढ़ाने की क्षमता इस नीति में है। रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर रणनीति बजट 2026 का सबसे भू-रणनीतिक पक्ष है। सरकार ने रेयर अर्थ खनिजों के घरेलू उत्पादन, प्रोसेसिंग और वैल्यू-चेन विकास के लिए विशेष आवंटन किया है।

> दुनिया में व्यापार तनाव, तकनीकी बदलाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच सरकार ने इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है।

आमने सामने

खुद के ऊपर 14-14 मुकदमे हैं। उनमें जमानत करा लें। उनको सेटल करा लें सरकार से हाथ-जोड़ी करके। पौने तीन साल बाद में कांग्रेस की सरकार आ रही है। मदन दिलावर जी से मिलने जेल में मैं जाऊंगा। गोविंद डोटासरा तो यहीं रहेगा। कहीं नहीं जाएगा।

–गोविंद सिंह डोटासरा
कांग्रेस नेता, राजस्थान

कांग्रेस सरकार के दौरान मिड-डे मील योजना में करीब दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। जांच की आंच उन 'मगरमच्छों' तक पहुंचेगी, जिन्होंने जनता की कमाई पर डाका डाला। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का जाल बिछ चुका है।

–मदन दिलावर
शिक्षा मंत्री
राजस्थान सरकार

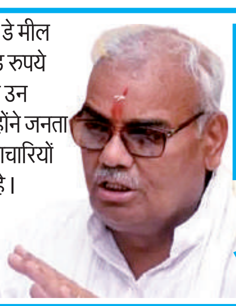

सुप्रीम फैसले से प्राइवेट स्कूलों में बराबरी की बात

रोहित माहेश्वरी
स्वतंत्र पत्रकार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब हर प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी अगर आपके पास साधन नहीं हैं, फिर भी आपका बच्चा महंगे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त पढ़ाई कर सकता है। हाल ही में शिक्षा के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम और दूरगामी फैसला सामने आया है। अदालत ने साफ कहा है कि सच्चा बंधुत्व तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ें। इसी सोच को मजबूत करते हुए शीर्ष अदालत ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट और गैर-सरकारी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत मुफ्त सीटें सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गरीब बच्चों को प्रवेश देना 'एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए।'

आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून, पहली अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके तहत छह से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत यह हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो इसमें कोई भी स्कूल बच्चे को दाखिला देने से मना नही कर सकता है। हर 60 बच्चों पर कम से कम दो प्रशिक्षित अध्यापकों का होना अनिवार्य है। हर तीन किलोमीटर के अंदर स्कूल होना जरूरी हैं। राईट टू एजुकेशन पर होने वाले खर्चों का 55 प्रतिशत केंद्र और 45 प्रतिशत राज्य सरकार उठाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, देश के स्कूल शिक्षा तंत्र में 24.8 करोड़ से अधिक छात्र नामांकित हैं और प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर 96.9 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है।

कोर्ट ने कहा कि कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला केवल कागजी अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को स्पष्ट नियम बनाने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से जुड़े इस मामले में याचिकाकर्ता दिनेश बीवाजी अष्टिकर ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को पड़ोस के निजी स्कूल में 25 फीसदी कोटे के तहत दाखिला नहीं मिला। आरटीआई से सामने आया कि सीटें खाली थीं, फिर भी स्कूल ने जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए राहत नहीं दी कि ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वर्षों की देरी के कारण बच्चों को समय पर राहत मिलना संभव नहीं रहा। इसके बावजूद अदालत ने इसे 'नज़ीर तय करने वाला' मामला मानते हुए व्यापक दिशा-निर्देश देने का फैसला किया। कोर्ट ने माना कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, भाषा की बाधा, डिजिटल अशिक्षा और जानकारी की कमी के कारण गरीब परिवारों के लिए 25 फीसदी कोटे तक पहुंचना आज भी मुश्किल है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पड़ोस के स्कूलों में दाखिला केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है।

अदालत ने यह याद दिलाया कि निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना कोई अलग कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) और 39 (एफ) में निहित बाल विकास और बंधुत्व के सिद्धांतों को लागू करने का जरिया है। शीर्ष अदालत का कहना था कि आरटीई कानून सभी बच्चों को जाति, वर्ग, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना एक ही स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा देने की बात करता है।

अदालत ने कोठारी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम पर जोर दिया गया था, जहां पर समाज के हर वर्ग के बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा मिल सके। संविधान के भाईचारे का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब एक रिक्शा खींचने वाले का बच्चा, एक करोड़पति या सुप्रीम कोर्ट के जज के बच्चे के साथ एक ही स्कूल में पढ़े। शीर्ष अदालत के इस फैसले को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषदों से सलाह लेकर, धारा 12(1)(सी) के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम और कानून तैयार करें और जारी करें। कोर्ट ने आगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियम और कानून जारी करने की जानकारी इकट्ठा करें और 31 मार्च तक कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।

> सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सच्चा बंधुत्व तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ें।

सोशल फोरम

जिगर और नातिया मुशायरा

अजमेर में एक नातिया मुशायरा था। आयोजकों के सामने बड़ी मुश्किल थी कि जिगर मुरादाबादी को इस मुशायरे में कैसे बुलाया जाए। वे खुले रिंद (शराब पीने वाले) थे। नातिया मुशायरे में उनकी शिरकत आसान नहीं थी। आयोजकों में कुछ उनके हक़ में थे, कुछ खिलाफ़। आख़िर बहुत सोच-विचार के बाद आयोजकों ने फैसला किया कि जिगर को दावत दी जानी चाहिए। जब जिगर को बुलाया गया तो वे सिर से पांव तक कांप उठे।

हिस्ट्री अनफोल्ड
ब्लॉगर

'मैं गुनहगार, रिंद, सियाहकार, बदनसीब— और नातिया मुशायरा! नहीं साहब, नहीं।'

अब आयोजकों के सामने यह समस्या थी कि जिगर साहब को कैसे तैयार किया जाए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों से इनकार। आख़िरकार असगर गोंडवी ने हुक्म दिया और जिगर ख़ामोश हो गए। सिरहाने बोतल रखी थी, उसे कहीं छिपा दिया। दोस्तों से कह दिया कि कोई उनके सामने शराब का नाम तक न ले। यह मौक़ा मिला है तो मुझे इसे खोना नहीं चाहिए। शायद यह मेरी बख़्शीश की शुरुआत हो। एक दिन गुज़रा, दो दिन गुज़र गए। नात के मज़मून सोचते थे और ग़ज़ल कहने लगते थे। सोचते रहे, लिखते रहे, काटते रहे, लिखे हुए को काट-काट कर थकते रहे। आख़िर एक दिन नात का मतला हो गया।

फिर एक शेर हुआ, फिर तो जैसे बारिश-ए-अनवार हो गई। नात मुकम्मल हुई तो उन्होंने सज्द-ए-शुक्र अदा किया। मुशायरे के लिए इस तरह रवाना हुए जैसे हज को जा रहे हों। उन्होंने कई दिनों से शराब नहीं पी थी, लेकिन हलक़ सूखा नहीं था। इधर तो यह हाल था, दूसरी तरफ़ मुशायरा-गाह के बाहर और शहर के चौराहों पर विरोध में पोस्टर लग गए थे कि एक शराबी से नात क्यों पढ़वाई जा रही है। आख़िर मुशायरे की रात आ गई। जिगर को बड़ी सुरक्षा के साथ मुशायरे में पहुंचा दिया गया। मंच से आवाज़ उभरी- 'रईस-उल-मुतग़ज़्ज़िलीन हज़रत जिगर मुरादाबादी!'

इस एलान के साथ ही एक शोर उठ खड़ा हुआ। जिगर ने बड़े धैर्य के साथ मजमे की ओर देखा और प्रेम से भरे स्वर में बोले, 'आप लोग मुझे हूट कर रहे हैं, या रसूल पाक की नात को, जिसे पढ़ने की सआदत मुझे मिलने वाली है और जिसे सुनने की सआदत से आप अपने आप को महरूम करना चाहते हैं?'

शोर को जैसे सांप सूंघ गया। बस यही वह विराम था, जब जिगर के टूटे हुए दिल से यह आवाज़ निकली-

एक रिंद है और मद्हत-ए-सुल्तान-ए-मदीना
हां, कोई नज़र-ए-रहमत-ए-सुल्तान-ए-मदीना

-फेसबुक वॉल से

सामयिकी

बेटियों का कागजी कवच और सामाजिक बेड़ियां

बेटियां घर की रौनक होती हैं। समाज की शक्ति होती हैं और राष्ट्र की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर भी देश की बेटियां समान अवसर, सुरक्षा एवं लैंगिक समानता की उपेक्षा का बोझ ढो रही हैं। सरकार ने बेटियों के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और कानून बनाए हैं, जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला आरक्षण विधेयक, पास्को एक्ट, घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाएं, जिनके माध्यम से बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। इन योजनाओं से कुछ सकारात्मक बदलाव भी दिखे हैं।

फिर भी, जमीनी हकीकत आज भी बहुत नहीं बदली है। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में लड़कियों की उन्नति दिखावा मात्र है। जिस समाज में हर रोज कोई लड़की या महिला बलात्कार का शिकार होती हो, उस समाज को प्रगतिशील कहना, दोगलापन है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, देश में प्रतिदिन 81 रेप के पुलिस केस दर्ज होते हैं। ये तो बस आंकड़े हैं, अधिकतर घटनाएं तो लोक-लाज के डर से परिवार और समाज द्वारा छिपा लिए जाते हैं।

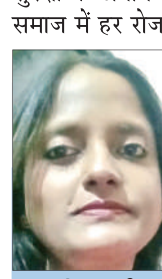

अंबिका अंबी
लेखिका

जहां एक तरफ लड़कियों के लिए समान अवसरों की बातें तो बोली जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ घरेलू जिम्मेदारियां लड़कियों पर ही लाद दी जाती हैं। आज भी लड़कियों को खुद के सपने चुनने का अधिकार नहीं है और न ही स्वतंत्रता से कहीं आने-जाने की छूट ही मिलती है। साथ ही, रसोई और घरेलू कामों का बोझ शुरू से ही उनके कंधों पर डाल दिया जाता है।

वास्तविकता में, लड़कियों को स्वतंत्रता और समान अवसर की सुविधाएं केवल मौखिक एवं कागजी स्तर पर ही सीमित रही है। वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कम है। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी है कि शिक्षा में आगे होने के बावजूद कई लड़कियां नौकरी या आगे की पढ़ाई छोड़ देती हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता, लैंगिक भेदभाव, असुरक्षा की भावना और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसी चुनौतियां हर कदम पर उन्हें कमजोर करती हैं। आज भी लाखों लड़कियां शिक्षा और नौकरी के अवसरों से वंचित रह जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, सामाजिक एवं पारिवारिक सहयोग का प्राप्त न होना।

डिजिटल युग में साइबर हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न ने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। खुले आम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती हैं और गालियां दी जा रही हैं। यह हिंसा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुंचाती हैं, बल्कि उन्हें ऑनलाइन स्पेस से दूर रहने, अपनी राय व्यक्त न करने या डिजिटल दुनिया से कट जाने पर मजबूर करने की साजिश है। यह क्रूर सच्चाई है कि जहां इंटरनेट ने महिलाओं को आवाज दी, शिक्षा दी और अवसर दिए, वहीं इस प्लेटफॉर्म का उनके खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बचपन से ही शिक्षा और घर-समुदाय स्तर पर हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। सही मायने में, देश की बेटियां की वास्तविक प्रगति तब होगी, जब कानून और योजनाएं सिर्फ घोषणाएं न रहें, बल्कि समाज की सोच बदलने, जमीनी सुरक्षा सुनिश्चित करने, घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ बांटने और हर बेटी को बराबरी का हक दिलाने में सक्षम बनें। हमारे देश को 'बेटी बचाव, बेटी पढ़ाओ' नारे की अपेक्षा 'समाज और परिवार में बेटियों के प्रति भेदभाव मिटाओ' नारे की ज्यादा ही जरूरत है।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक हरि ओम गुप्ता द्वारा अमृत विचार प्रकाशन, नवादा जोगियान, चक रोड, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने, बरेली (उ.प्र.), पिन कोड-243006 से मुद्रित एवं 932 कटरा चांद खां, भारत पेट्रोल पंप के सामने पीलीभीत बाईपास रोड बरेली (उ.प्र.) पिन कोड-243005 से प्रकाशित। **संपादक- राजेश श्रीनेत, स्थानीय संपादक- नवीन गुप्ता*** 0581-4000222 (कार्यालय), ईमेल- editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-UPHIN/2019/78502, *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी। (नोट-सभी विवादों का न्यायक्षेत्र बरेली होगा)।

कार खरीदना कुछ लोगों के लिए बुनियादी जरूरत है, तो कुछ लोगों के लिए शानो-शौकत और रुतबे का प्रतीक, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों के लिए यह हमेशा से एक सपने के सच होने जैसा है। कार आज हम सभी के घरों का एक जरूरी और अहम हिस्सा बन चुकी है। इस मांग की वजह से ही हाल के वर्षों में पुरानी कारें खरीदने का चलन तेजी से बढ़ा है और देश में पुरानी कारों का बाजार एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। यह तब हुआ है, जब लोगों को भरोसा हुआ है कि पुरानी कारें भी नई कारों जितनी ही अच्छी हो सकती हैं। एक और वजह यह भी है कि पसंदीदा नई कारें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, ऐसे में कम बजट में बेहतर ब्रांड, शानदार फीचर्स की उपलब्धता भी पुरानी कारों की मांग को शहरों से लेकर कस्बों तक आगे बढ़ा रही है। हालांकि काफी सारे लोग पुरानी कार खरीदने में जोखिम और धोखाधड़ी के कारण बचते हैं, लेकिन पुरानी कारों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने के बाद से चीजें काफी आसान भी हो गई हैं।

-मनोज त्रिपाठी, कानपुर

नई कार स्टेटस देती पुरानी कार समझदारी

पुरानी कारों की बिक्री नई कारों से ज्यादा

भारत में पुरानी कारों की बिक्री नई कारों की तुलना में 8 से 10 फीसदी सालाना वृद्धि दर से बढ़ रही है। वर्तमान में प्रत्येक नई कार की बिक्री पर लगभग 1.4 पुरानी कारें बेची जा रही हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार साल 2026 के अंत तक भारत में इस्तेमाल की गई कारों की बिक्री 75 लाख यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है। यही नहीं इस साल देश में पुरानी कारों का बाजार 3.4 लाख करोड़ से अधिक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि पुरानी कारों के बाजार में हिस्सेदारी की बात करें, तो अभी भी सिक्का स्थानीय डीलरों और ब्रोकर का चलता है, जो बाजार के लगभग 68 फीसदी हिस्से पर काबिज हैं, लेकिन ग्राहकों का भरोसा अब वारंटी और सर्टिफाइड कारों के कारण तेजी से संगठित क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो रहा है। इस बदलाव से डिजिटल माध्यमों से होने वाली पुरानी कारों की बिक्री की हिस्सेदारी इस साल के अंत तक करीब 30 फीसदी पहुंचने की उम्मीद है।

मारुति, टाटा, महिंद्रा के साथ ऑनलाइन स्टार्टअप्स ने जीता यूज्ड कार का भरोसा

पुरानी कारों के संगठित कारोबार में मारुति सुजुकी True Value, महिंद्रा First Choice और टाटा मोटर्स Assured जैसे निर्माताओं के साथ Cars24, Spinny, CarDekho और Droom जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ और भी अनेक ऑनलाइन स्टार्टअप्स शामिल हैं। ये सभी सर्टिफाइड गाड़ियां खोजने, टेस्ट ड्राइव बुक करने और पूरी लेनदेन प्रक्रिया में मदद के अलावा अधिकतर कार के मूल्यांकन और कागजी कार्रवाई में भी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे पुरानी कार खरीदना आसान हो जाता है। इनमें Cars24 को पुरानी कारों की खरीद-बिक्री के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आप कार का मूल्यांकन, टेस्ट ड्राइव और पूरी कागजी कार्रवाई जैसे आरसी ट्रांसफर, लोन आदि में मदद पा सकते हैं। Spinny भी एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, जो सर्टिफाइड और अच्छी क्वॉलिटी वाली पुरानी कारों को आसान और सुरक्षित तरीके से खरीदने का बेहतर अनुभव प्रदान कर रहा है। CarDekho पुरानी और नई दोनों तरह की कारों की पूरी जानकारी जैसे मॉडल, कीमत और माइलेज जैसी डिटेल्स प्रदान करता है। इसके मुकाबले Droom ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहां आप विभिन्न कारों की तुलना कर सकते हैं और कई विकल्प देख सकते हैं। इसी कड़ी में CarWale भी एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, जहां आपको पुरानी और नई कारों के ढेर सारे विकल्प मिलते हैं। इनके अतिरिक्त OLX भी पुरानी कारें खरीदने और बेचने के लिए लोकप्रिय ऐप है, जिसमें आप सीधे विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं।

इसलिए बढ़ रहा है पुरानी कारों का बाजार

देश में हर साल लाखों लोग पहली बार कार खरीदते हैं और उनमें से बड़ी संख्या सेकेंड हैंड या यूज्ड कार को प्राथमिकता देती है। इसके पीछे कारण हैं-

- नई कारों की बढ़ती कीमतें
- कम डाउन पेमेंट और आसान फाइनेंस
- डेप्रिसिएशन का कम झटका
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती विश्वसनीयता
- सर्टिफाइड प्री-ओन्ड कार प्रोग्राम्स

इन कारों की मांग सबसे अधिक

बाजार के ट्रेंड पर नजर डालें, तो हैचबैक मारुति स्विफ्ट, वैगनआर, ग्रैंड आई-10 और सेडान में होंडा सिटी, मारुति सियाज, इसी तरह एसयूवी में क्रेटा, ब्रेजा, डस्टर आदि 5 से 7 साल पुरानी, कम चली और अच्छी तरह मेंटेंड कारें सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं।

खरीदने से पहले जरूरी बातें

- सबसे पहले अपना बजट बनाएं, फिर यह देखें कि पुरानी कार फर्स्ट हैंड है या फिर उसके पहले भी कई ऑनर रह चुके हैं। ऐसी कार लेना हमेशा बेहतर होता है, जो कम किलोमीटर चली हो। भारत में, एक कार औसतन सालाना 6 हजार से 12 हजार किलोमीटर चलती है। यह जरूरी है कि आप सर्विस रिकॉर्ड और गाड़ी की पूरी स्थिति के अनुसार चलाए गए किलोमीटर की जांच करें।
- आरसी, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच करें। ओडोमीटर रीडिंग और सर्विस हिस्ट्री मिलाएं। कार को दिन की रोशनी में ध्यान से देखें।
- टेस्ट ड्राइव जरूर लें, आवाज, ब्रेक, गियर पर ध्यान दें। किसी अच्छे मैकेनिक से पूरा इंस्पेक्शन करवा लें। इंश्योरेंस ट्रांसफर की प्रक्रिया ठीक से समझें।

ऑनलाइन या ऑफलाइन कहां से खरीदें

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म: ज्यादा विकल्प, पारदर्शी कीमत
- डीलरशिप: भरोसेमंद लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा
- डायरेक्ट ऑनर: सस्ता सौदा, पर जोखिम ज्यादा

Hero Vida Dirt .E K3: बच्चों के रोमांच को मिली इलेक्ट्रिक उड़ान

बदलते समय के साथ बच्चों की दुनिया भी स्मार्ट और टेक-फ्रेंडली हो रही है। इसी कड़ी में Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने भारत में बच्चों के लिए एक अनोखी और सुरक्षित इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक Dirt .EK3 पेश की है। यह बाइक न सिर्फ खेल-खेल में राइडिंग का मजा देती है, बल्कि सुरक्षा और सीखने, दोनों का पूरा ध्यान रखती है।

कीमत और उपलब्धता

Vida Dirt .EK3 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 69,990 रखी गई है। पहले 300 यूनिट्स इसी कीमत पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यह बच्चों के लिए एक प्रीमियम, लेकिन समझदारी भरा विकल्प बनती है। इसकी बिक्री 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है।

दमदार बैटरी

Dirt .EK3 में 360 Wh की रिमूवेबल बैटरी और 500W मोटर दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा तक सीमित रखी गई है। बैटरी महज 2 घंटे में 20% से 80% तक चार्ज हो जाती है और एक बार चार्ज करने पर 2 से 3 घंटे तक राइड का मजा देती है। तीन राइडिंग मोड- Beginner, Amateur और Pro, बच्चों को धीरे-धीरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर देते हैं।

सुरक्षा और स्मार्ट फीचर्स

Vida ने सेफ्टी के मामले में कोई समझौता नहीं किया है। बाइक में मैग्नेटिक किल स्विच, चेस्ट पैड, ब्रेक रोटर कवर और रियर ग्रैबरेल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि एक मोबाइल ऐप के जरिए माता-पिता बच्चे की राइडिंग एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं, स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं और अन्य पैरामीटर्स नियंत्रित कर सकते हैं।

इंटरनेशनल पहचान

Dirt .E K3 का डिजाइन सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। इसे Red Dot Award 2025 दिया गया है, जो इसकी क्वालिटी और इनोवेशन का प्रमाण है। कुल मिलाकर, Hero Vida Dirt .EK3 बच्चों के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक राइडिंग अनुभव लेकर आई है, जहां रोमांच, सीख और सुरक्षा तीनों का खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है।

बच्चे के साथ 'बढ़ने' वाली बाइक

इस बाइक की सबसे खास बात है इसका एडजस्टेबल डिजाइन। व्हीलबेस और सस्पेंशन को तीन लेवल- Small, Medium और High पर सेट किया जा सकता है। यानी जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, बाइक भी उसके कद और उम्र के अनुसार ढलती जाएगी। इससे माता-पिता को हर कुछ साल में नई बाइक खरीदने की चिंता नहीं रहती।

काम की बात

सर्दियों में क्यों 'नखरे' दिखाती है बाइक ?

सर्दियों की सुबह बाइक सवारों के लिए अक्सर एक परीक्षा बन जाती है। तापमान गिरते ही कई बाइक्स सेल्फ और किक दोनों पर सुस्त प्रतिक्रिया देने लगती हैं। बार-बार कोशिशों के बाद भी इंजन का स्टार्ट न होना न केवल समय की बर्बादी करता है, बल्कि बाइक की मैकेनिकल सेहत पर भी असर डालता है। ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठंड में बाइक स्टार्टिंग की समस्या पूरी तरह तकनीकी है और सही समझ के साथ इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है।

ठंड का बाइक पर असर

कम तापमान में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को घूमने में अधिक प्रतिरोध झेलना पड़ता है। दूसरी ओर, लेड-एसिड बैटरी की केमिकल रिएक्शन क्षमता ठंड में कमजोर हो जाती है, जिससे सेल्फ स्टार्ट का आउटपुट घट जाता है। यही कारण है कि सर्दियों में सुबह के समय बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत करती है, जिससे बाइक सवार को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, खासकर उन वाहनों में जिनका मेंटेनेंस नियमित नहीं होता।

स्टार्टिंग समस्या से निपटने के स्मार्ट तरीके

- **स्पार्क प्लग की भूमिका अहम-** ठंड और नमी के कारण स्पार्क प्लग पर कार्बन डिपॉजिट या नमी जमा हो सकती है, जिससे स्पार्क कमजोर पड़ जाता है। यदि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले स्पार्क प्लग की जांच जरूरी है। प्लग को साफकर दोबारा फिट करने से करंट फ्लो बेहतर होता है और इंजन आसानी से जान पकड़ता है।
- **क्लच ट्रिक से घटेगा लोड-** सर्दियों में गियरबॉक्स ऑयल भी गाढ़ा हो जाता है। बाइक को न्यूट्रल में रखकर क्लच पूरी तरह दबाने से गियरबॉक्स इंजन से अलग हो जाता है। इससे किक मारते समय इंजन पर कम लोड पड़ता है और स्टार्टिंग आसान हो जाती है।
- **चोक का सही और सीमित उपयोग-** कार्बोरेटर वाली बाइक्स में चोक ठंडे इंजन के लिए बेहद उपयोगी है। चोक खींचने से एयर-फ्यूल मिक्सचर रिच हो जाता है, जिससे इंजन जल्दी स्टार्ट होता है। हालांकि इंजन चालू होने के 20-30 सेकंड बाद चोक बंद कर देना चाहिए, वरना फ्यूल कंजम्पशन बढ़ सकता है।
- **इग्निशन ऑफ रखकर प्री-किक तकनीक-** ऑटो मैकेनिक्स के अनुसार, इग्निशन बंद रखकर 3-4 बार खाली किक मारने से सिलेंडर के भीतर गाढ़ा ऑयल फैल जाता है। इससे इंजन के मूविंग पार्ट्स लुब्रिकेट हो जाते हैं और स्टार्टिंग के समय कम प्रतिरोध पैदा होता है।
- **लगातार फेल स्टार्टिंग का नुकसान-** बार-बार सेल्फ मारने से बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है और स्टार्ट मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वहीं, ठंडे इंजन को जबरदस्ती स्टार्ट करने से पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट पर अनावश्यक घर्षण बढ़ता है, जिससे लंबे समय में इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है।
- **एक्सपर्ट्स की मेंटेनेंस सलाह-** ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में बाइक को खुले में खड़ा करने से बचना चाहिए। कवर का इस्तेमाल बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नमी से सुरक्षित रखता है। साथ ही मौसम के अनुसार सही ग्रेड का इंजन ऑयल और समय-समय पर बैटरी हेल्थ चेक करना बेहद जरूरी है।
- **आने वाला कल-** ऑटो इंडस्ट्री ठंडे मौसम के लिए बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी और लो-विस्कोसिटी इंजन ऑयल पर काम कर रही है। जब तक ये तकनीकें आम नहीं होतीं, तब तक सही ड्राइविंग हैबिट्स और बेसिक मेंटेनेंस से सर्दियों में बाइक स्टार्टिंग की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

माॅय फर्स्ट राइड

सासू मां के साथ मेरी आगे बढ़ने की यात्रा

जीवन में कुछ यात्राएं सड़कों पर तय होती हैं और कुछ हमारे मन और सोच के भीतर। मेरी कार सीखने की यात्रा भी ऐसी ही एक यात्रा रही, जो केवल ड्राइविंग सीखने तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और बदलाव को अपनाने की कहानी बन गई।

2024 में जब मेरी शादी तय हुई, तब तक मैं कार चलाना नहीं जानती थी। मायके में इसकी कभी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी थी, इसलिए यह कौशल मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन शादी के बाद ससुराल का वातावरण अलग था। यहां मेरी सासू मां और ननद दोनों कार चलाती थीं। घर से जुड़ा अधिकांश काम-चाहे फैक्ट्री जाना हो, कच्चा माल लाना हो या बाजार की खरीदारी-कार से ही पूरा होता था। ऐसे में मुझे यह समझ में आने लगा कि अब मुझे भी इस जिम्मेदारी में हाथ बंटाना होगा।

कार सीखने का निर्णय लेना आसान था, लेकिन उसे सीखने की प्रक्रिया उतनी सरल नहीं थी। पहली बार स्टीयरिंग पकड़ते समय हाथ कांप रहे थे। सड़क पर निकलते ही मन में डर और असमंजस बना रहता था। ब्रेक, एक्सेलरेटर और क्लच के बीच तालमेल बैठाने में समय लगा। कई बार छोटी-छोटी गलतियां हुईं, लेकिन हर बार सासू मां ने धैर्य और अपनापन दिखाया। उनका विश्वास और सहयोग मेरे लिए सबसे बड़ा संबल बना।

धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ा और डर कम होने लगा। सुबह की खाली सड़कों से शुरुआत हुई, फिर मोहल्ले की गलियों से होते हुए मैं मुख्य सड़क तक पहुंच पाई। समय के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। आज मैं अपनी सासू मां के साथ फैक्ट्री के कामों के लिए जाती हूं और बाजार की जिम्मेदारियां भी निभाती हूं। अब कार मेरे लिए केवल एक साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान बन गई है।

इस पूरी यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। परिस्थितियां जब बदलती हैं, तो हमें भी अपने भीतर बदलाव लाना पड़ता है। परिवार का सहयोग और विश्वास किसी भी नई शुरुआत को आसान बना देता है। सासू मां के साथ मेरा रिश्ता इस दौरान और भी गहरा हुआ, क्योंकि हमने साथ-साथ सीखने और आगे बढ़ने का अनुभव साझा किया।

आज जब मैं कार चलाती हूं, तो मुझे सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती, बल्कि उस सफर का आनंद भी मिलता है, जिसने मुझे आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनाया। मेरी कार सीखने की यात्रा वास्तव में मेरे नए जीवन की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा बन चुकी है।

-अपर्णा, कानपुर

न्यूज ब्रीफ

भारत बंद को लेकर पुलिस ने किया रूट मार्च

बिल्सी, अमृत विचार : यूजीसी के विरोध में एक फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया था। इसे लेकर रविवार सुबह से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। नगर के मुख्य बाजार के साथ-साथ विभिन्न मार्गों पर पुलिस बल तैनात किया गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने लगातार गश्त की। कोतवाल मनोज कुमार सिंह ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की।

भंडारे के साथ प्रभात फेरी का समापन

बिसौली, अमृत विचार : क्षेत्र के गांव सीकरी में ठाकुरजी के बड़े मंदिर में प्रभातफेरी के समापन पर रामचरित मानस का अखंड पाठ के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन में बाबा फौरन गिरी, नितेश शर्मा, रज्जन शर्मा, हरिओम शर्मा, राजेश, विपिन, विनय, शिवओम, हुकुम सिंह, ज्ञान सिंह, देवेंद्र सिंह, सुभाष शर्मा विशेष सहयोग रहा। इस दौरान अधिवक्ता और कवि उपस्थित रहे। वहीं गांव में जाटव समुदाय के सहयोग से निकली प्रभात फेरी में श्रद्धालु डीजे की धुन पर झूमते रहे। जिसका आरंभ गांव प्राचीन मंदिर गांव देवता से हुआ।

दिल्ली पुलिस का छापा अहिरामई से लड़की बरामद

विजय नगला, अमृत विचार : गांव निवासी एक युवक दिल्ली के भुडारी थाना क्षेत्र में रहकर प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। जहां 18 साल की लड़की भी काम करती थी। दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया था। वह लड़की को बहलाकर अपने घर ले आया। लड़की के पिता ने थाना भुडारी में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने लड़की के मोबाइल नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस की। जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस शनिवार रात थाना मूसाझाग आई और पुलिस को मामले से अवगत कराया। मूसाझाग पुलिस के सहयोग से लड़की को बरामद कर लिया लेकिन युवक भाग निकला। पुलिस लड़की को अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने युवक के रिश्तेदारों को हिरासत में लिया था जब युवक के परिजन ने लड़की बरामद कराई। प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि दिल्ली पुलिस आई थी। लड़की बरामद करके साथ ले गई है।

माघी पूर्णिमा पर गंगा घाट पर गूंजा हर-हर गंगे

हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में किया स्नान, किया दान पुण्य, खराब मौसम के बीच भोर से शुरू हो गया गंगा स्नान

कार्यालय संवाददाता, बदायूं

अमृत विचार : माघ पूर्णिमा पर कछला स्थित गंगा घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ा। खराब मौसम के बीच हजारों श्रद्धालुओं ने कछला सहित अन्य गंगा घाटों पर हर हर गंगे के जयघोष के साथ गंगा में स्नान किया। भोर से ही हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाटों की ओर पहुंचने लगे थे। श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया और दान-पुण्य कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। साथ ही सत्यनारायण की कथा कराने के बाद प्रसाद का वितरण किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। घाट क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, पीएसी और गोताखोर तैनात रहे। गंगा में नावों के माध्यम से निगरानी की गई, वहीं संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती गई।

माघ पूर्णिमा के अवसर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, कासगंज, एटा, बरेली सहित स्थानीय लोगों ने कछला गंगा घाट पर पहुंचकर गंगा में स्नान किया। सुबह के समय आसमान में बादल छाए होने के साथ ही हल्की बूंदा बांदी हुई। इसी खराब मौसम के बीच भोर के समय पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान किया। दस बजे के बाद मौसम साफ हो गया। इसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती चली गई। दिनभर कछला गंगा घाट के साथ जनपद के अन्य घाटों पर भारी भीड़ बनी रही।

लोगों ने गंगा में स्नान करने के बाद दान पुण्य किया। कुछ लोगों ने घाट पर ही सत्यनारायण की कथा कराई। साथ ही दान पुण्य कर परिवार की सुख समृद्धि के लिए मां गंगा से कामना की। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। घाट क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, पीएसी और गोताखोर तैनात रहे।

गंगा में नावों के माध्यम से निगरानी की गई, वहीं संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती गई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए गए थे, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। वहीं प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम एंबुलेंस सहित मौके पर मौजूद रही। अधिकारियों द्वारा समय-समय पर घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।

अटेना गंगा घाट पर गंगा में स्नान करते श्रद्धालु। ● अमृत विचार

● **दान पुण्य करने के साथ सत्यनारायण की करवाई कथा**

अटेना गंगा घाट पर किया गंगा स्नान

उसहैत, अमृत विचार : माघ पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने अटेना गंगा घाट पर गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के दौरान कटान की स्थिति रही। जिससे गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं की हादसे की आशंका व्यक्त करते हुए धडकनें बढ़ी रहीं। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी पुलिस बल तैनात रहा। रविवार को माघ पूर्णिमा पर अटेना गंगा घाट, कटरा, भुंडी, पथरामई, बेहटी आदि गंगा घाटों पर पर हजारों श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखी गई। महिला-पुरुष श्रद्धालुओं ने हर-हर गंगे की गूंज के साथ गंगा में स्नान किया। गंगा स्नान के बाद दान पुण्य कर परिवार के लिए मंगल कामना की। गंगा तट के आस पास हो रहे कटान को देखते हुए तैनात पुलिस श्रद्धालुओं से बार बार सतर्कता बरतने की अपील कर रही थी। गोताखोर घाट पर नजर बनाए हुए थे। गहरे पानी में लोगों को जाने से रोकने के लिए बांस बल्ली लगाई गई थी। श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान करने के बाद लौटते समय श्री कालसेन बाबा मंदिर व पक्का पुल हनुमान मंदिर पर प्रसाद चढा कर पूजा अर्चना की।

माघ पूर्णिमा पर अंबियापुर में हाईवे पर भंडारा

बिल्सी, अमृत विचार : तहसील बिल्सी क्षेत्र के गांव अंबियापुर में माघ माह की पूर्णिमा के पावन अवसर पर समाजसेवी मृदुल शर्मा द्वारा हाईवे किनारे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में राहगीरों, श्रद्धालुओं और ग्रामीणों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। माघ पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस भंडारे की शुरुआत विधिवत पूजा-अर्चना के साथ की गई। इसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। समाजसेवी ने कहा कि माघ माह को पुण्यदायी माना गया है और इस माह में सेवा व दान का विशेष महत्व है। इसी भावना के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रसाद प्राप्त हो सके। पंचायत घर के सामने शिव मंदिर पर ग्राम वासियों द्वारा आयोजित भंडारे में पूर्व जिला पंचायत सदस्य ममता शाक्य ने पहुंच कर आरंभ किया।

राशन लाने की बात पर की थी महिला की हत्या

पुलिस की गिरफ्त में महिला की हत्या करने का आरोपी। ● अमृत विचार

संवाददाता, सहसवान

अमृत विचार : सहसवान पुलिस ने मोहल्ला जहांगीराबाद की कांशीराम कॉलोनी में महिला की हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हत्या में प्रयुक्त ईंट बरामद कराई है।

शुक्रवार रात हरिओम पुत्र गोकन्नी ने पुलिस को सूचना दी कि उनकी बुजुर्ग मां जावित्री का शव घर में पड़ा मिला था। सिर और शरीर पर चोट के निशान थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। जिसमें चोट की वजह से मौत होने की पुष्टि हुई थी। हरिओम की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रविवार को पुलिस ने बरेली के थाना सीबीगंज क्षेत्र के गांव ठिरिया ठकुरान निवासी किशनपाल उर्फ भोला पुत्र होरी लाल को सहसवान-कछला मार्ग के नगला मिश्र तिराहे से गिरफ्तार किया।

उसने बताया कि महिला के बेटे सौदान से उसकी दोस्ती थी। वह सौदान के साथ मजदूरी करने के लिए आया था। दोस्त की मां जावित्री देवी काशीराम कॉलोनी में अकेली रहती थीं। सौदान उसे और अपनी मां को छोड़कर अलीगढ़ में नुमाइश में काम करने गया था। उससे अपनी मां की देखभाल करने को कहा था। 31 जनवरी की सुबह जावित्री ने उससे कहा कि तू मेरे पास रहता है और घर का राशन लेकर नहीं आता। फ्री का खाना खाता है। अभद्र व्यवहार करते हुए वह गाली गलौज करने लगीं। गुस्से में आकर उसने महिला को ईंट मार दी। फिर भाग गया। प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जायन्ट्स ग्रुप के अध्यक्ष बने सुमित, सोमवीर सचिव

संवाददाता, बिसौली

अमृत विचार : नगर बिसौली के समाजसेवी संगठन जायन्ट्स ग्रुप ऑफ बिसौली सिटी का चौथा अधिष्ठापन समारोह श्री राम कृष्ण दास अग्रवाल धर्मशाला में हुआ। कार्यक्रम में समाज सेवा, सहयोग एवं संगठनात्मक एकता का संदेश दिया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिवक्ता सुमित गोयल, सचिव सोमवीर सिंह, कोषाध्यक्ष अंकुर गुप्ता सहित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शपथ ग्रहण की।

ग्रुप के निवर्तमान अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल ने जायन्ट्स कॉलर पहनाकर नवनियुक्त अध्यक्ष गोयल को पदभार सौंपा। मुख्य अतिथि चंदौसी की डॉ. सुधा चौधरी, विशिष्ट अतिथि पदमा भार्गव ने समाज सेवा को जीवन का अभिन्न अंग बताते हुए संगठन के सभी सदस्यों और नव दायित्ववान कार्यकारिणी को निरंतर सेवा कार्यों के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए निवर्तमान सचिव प्रशांत गर्ग ने पिछले साल ग्रुप द्वारा किए गए सेवा कार्यों के बारे में बताया। कार्यक्रम में सभी ने हाउजी गेम का आनन्द लेते हुए उपहार जीते।

बालिका प्रव्या गोयल ने मनमोहक प्रस्तुति दी। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष कृष्ण अवतार शर्मा, श्री अग्रवाल सभा के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कार्यों की प्रशंसा की। यूनिट डायरेक्टर अनुपम वार्ष्णय, ग्रुप के सदस्य चितरंजन गुप्ता, डॉ. अंकुश गुप्ता, विपुल गोयल, शुचित अग्रवाल, युग कृष्ण गर्ग, अमित अग्रवाल, रजत अग्रवाल, प्रियांक अग्रवाल, हिमांशु गुप्ता, नितिन अग्रवाल, डॉ. वैभव वार्ष्णेय डॉ सूरज भौमिक, मोहित अग्रवाल, वैभव माहेश्वरी, विनय गर्ग, राहुल गोयल, डॉ. जितेंद्र गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान मौजूद जायन्ट्स ग्रुप ऑफ बिसौली सिटी के पदाधिकारी।

● **बिसौली के श्री राम कृष्ण दास अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित हुआ कार्यक्रम**

हत्यारोपी पत्नी समेत दो गिरफ्तार

कादरचौक, अमृत विचार : थाना कादरचौक क्षेत्र के गांव भुवईया से ईदगाह मार्ग के चकरोड पर गेहूं के खेत में 26 जनवरी की रात गोली मारकर असीरुद्दीन की हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम कराने पर गोली मारकर हत्या की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि असीरुद्दीन की पत्नी ने अपने मित्र गांव भदसिया निवासी गुलफाम उर्फ गुलजार पुत्र फकरुद्दीन से मिलकर पति की हत्या की थी। पुलिस ने रविवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन दोनों की गहरी दोस्ती थी। असीरुद्दीन इसका विरोध करता था। जिसके चलते उन्होंने योजना बनाई। असीरुद्दीन 26 जनवरी की रात पड़ोस के गांव से अपने गांव लौट रहे थे। गुलफाम ने उनकी सिर पर गोली मार दी थी और शव गेहूं के खेत में फेंक दिया था।

बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे

संवाददाता, सहसवान

अमृत विचार : सकल हिन्दू समाज समिति की ओर से सहसवान के प्रमोद संस्कृत महाविद्यालय के मैदान पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भारतीय संस्कृति के विभिन्न मान बिंदुओं पर आधारित प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे डॉ. बृजेश यादव ने भारतीय संस्कृति की विशेषताओं के बारे में बताते हुए वर्तमान समय में संस्कृति के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में अवगत कराया।

एकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे। कहा कि भारतीय संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ विश्व बंधुत्व का संदेश देती है लेकिन इसके लिए समाज में एकता की शक्ति जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक सुधांशु ने संघ की 100 वर्षों की यात्रा के बारे में बताया। विशिष्ट अतिथि श्री श्री 1008 बुद्ध गिरी ने कहा कि हमको जातियों में नहीं बंटना है। सकल हिंदू समाज को एक रहना आवश्यक है। हिंदू सम्मेलन समिति के अध्यक्ष आलोक माहेश्वरी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज में जागरूकता और सांस्कृतिक चेतना का विस्तार होता है।

हिन्दू सम्मेलन में संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक मोहनलाल दद्दा, प्रेम स्वरूप, प्रजापति ब्रह्माकुमारी आदि को सम्मानित किया। भारत माता की आरती के बाद कार्यक्रम के समापन की घोषणा हुई। संचालन नगर बौद्धिक प्रमुख नरेन्द्र सनातनी ने किया। नगर प्रचारक शरद अत्री, जिला संघ चालक योगेश, आलोक, गोपाल, नितिन, अनुज माहेश्वरी, सुभाष गौड़, पीयूष, डॉ. आईपी सिंह, विवेक सक्सेना, सचिन शर्मा, सौरव माहेश्वरी, राम औतार आदि मौजूद रहे।

प्रमोद संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते वक्ता।

● **प्रमोद संस्कृत महाविद्यालय में हिंदू सम्मेलन में बोले डॉ. बृजेश**

सड़क हादसे में घायल छात्र की मौत

निर्दोष सागर

● **कॉलेज से वापस आते समय स्कूल के सामने हादसे में घायल हुआ था छात्र**

संवाददाता, बिल्सी

अमृत विचार : सड़क हादसे में घायल कक्षा 12 के छात्र की अस्पताल में मौत हो गई।

कोतवाली बिल्सी क्षेत्र के गांव वनबेहटा निवासी निर्दोष सागर (18) पुत्र राजेश एनए इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते थे। वह 12वीं के छात्र थे। 19 जनवरी को वह कॉलेज से पढ़कर बाइक से वापस घर लौट रहे थे। बिल्सी से उझानी मार्ग पर बाबा इंटरनेशनल स्कूल के पास विपरीत दिशा से आई दूसरी बाइक से उनकी बाइक की भिड़ंत हो गई।

हादसे में निर्दोष सागर गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को बिल्सी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। परिजनों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत में सुधार न होने पर घायल को सैफई के राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। जहां इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई।

छात्र की मौत के बाद विलाप करते परिजन और ग्रामीण। ● अमृत विचार

होली पूजन व दहन के लिए चिह्नित हुई जमीन

संवाददाता, कुंवरगांव

अमृत विचार : कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव बागरपुर में होलिका दहन स्थल को लेकर विवाद रहता था। पहले होली रवेन्द्र मिश्रा के दरवाजे के आगे जलाई जाती थी। जिससे आग लगने का डर रहता था। अब ग्रामीणों की सहमति से राजस्व विभाग और पुलिस द्वारा विवाद को निपटा दिया गया है। वैकल्पिक जगह पर होलिका रखी गई है।

ग्रामीणों ने बताया कि पहले होलिका दहन स्थल को लेकर अक्सर विवाद होता था। जिससे गांव में तनाव की स्थिति बन जाती थी। इस बार राजस्व विभाग और पुलिस की पहल से विवाद को सुलझाया गया और गांव में ओवरहेड टैंक के पास जगह चिन्हित की गई। ग्रामीणों के सहयोग से रविवार को पूर्णिमा वाले दिन दोनों जगह पर विधिवत पूजन कराने के बाद होलिका रख दी गई। ग्रामीणों के अनुसार इस निर्णय से गांव में शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा। अब गांव में होली हर वर्ष चयनित जगह पर ही जलाई जाएगी। गांव में एकता और भाईचारा बना रहेगा।

चिह्नित जगह पर होलिका रखते ग्रामीण।

न्यूज डायरी

पांच कुंडीय महायज्ञ का हुआ समापन

करियामई, अमृत विचार : विकासखंड इस्लामनगर क्षेत्र के गांव धर्मपुर में स्थित शिव मंदिर पर चल रहे पांच कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का रविवार को पूर्णाहुति के साथ समापन हो गया। अंतिम दिन सैकड़ों श्रद्धालुओं ने परिक्रमा कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। यज्ञाचार्य कैलाश उपाध्याय, सह यज्ञाचार्य रामबाबू शर्मा, विवेक दीक्षित, अर्जुन शर्मा, गौरव शर्मा ने सभी यजमानों को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूर्णाहुति कराई। आरती के बाद श्री लक्ष्मी नारायण की आरती व पूजन कर प्रसाद वितरण किया। साधु-संत कन्याओं को खीर पूरी हलवा खिलाया। इसके बाद सैकड़ों भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। यजमान संतोष यादव, ध्रुव सिंह, डोरी लाल शर्मा, प्रकाशानंद सहित सड़कों भक्त मौजूद रहे।

संत रविदास ने दिया था समानता व सद्भाव का संदेश

बिल्सी, अमृत विचार : नगर बिल्सी के आर्य समाज रोड स्थित संत रविदास मंदिर पर रविवार को संत रविदास की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का आरंभ संत रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। बिल्सी विधायक हरीश शाक्य ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने समाज को समानता, सद्भाव और मानवता का संदेश दिया। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। पूर्व चेयरमैन ओमप्रकाश सागन ने लोगों से रविदास के विचारों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लेने को कहा। इस मौके पर सभासद प्रदीप गुप्ता, बनवारी लाल मौर्य, उमेश चंद्र, मुनीष कुमार, तेजस्वी सागर, माखन दिवाकर आदि मौजूद रहे।

अजय ने दिल्ली में प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण

बदायूं, अमृत विचार : जिला ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष राजन मेंहदीरत्ता ने बताया कि नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में वर्ल्ड सिख फाउंडेशन एवं सिख फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 30 व 31 जनवरी को द्वितीय एशियन सिख गेम्स के अंतर्गत ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन कराया गया था। जिसमें एपीएस इंटरनेशनल स्कूल के कोच अजय पाल सिंह ने सीनियर वर्ग में की पूमसे टीम स्पर्धा, पूमसे कोरिया, पूमसे खिमजांग, पूमसे टाईबैक में शानदार प्रदर्शन किया। उन्हें स्वर्ण पदक मिला है। उनकी उपलब्धि पर परिचित और संघ के पदाधिकारियों ने बधाई दी है।

वेद को सत्य ज्ञान का स्त्रोत मानते थे संत रविदास

बदायूं, अमृत विचार : विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष नीरज रस्तोगी के आवास पर संत रविदास जयंती मनाई गई। संगठन के जिला मंत्री विनय प्रताप सिंह ने संत रविदास के जीवन और उनकी शिक्षा के बारे में विस्तार से बताया। कहा कि नकी वैदिक धर्म में गहरी आस्था थी। वह वेद को सत्य ज्ञान का स्त्रोत मानते थे। साल 1398 मे माघ पूर्णिमा के दिन वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। जिलाध्यक्ष ने कहा कि संत रविदास ने अपना पूरा जीवन समाज सुधार और कल्याण कार्यों में समर्पित कर दिया। उन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से मानव अधिकारों और समानता का संदेश दिया। जिला उपाध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह, कोषाध्यक्ष नीरज कोचर, जिला सह मंत्री राजेश बाबू, जिला समरसता प्रमुख अरविंद गुप्ता, जिला सह सेवा प्रमुख राजेश सपरा, नगर उपाध्यक्ष संदीप रस्तोगी, धर्म प्रसार प्रमुख अचल सक्सेना आदि मौजूद रहे।

शिक्षकों में मारपीट, पुलिस ने रफा-दफा कराया

संवाददाता, आसफपुर

● **आसफपुर के त्रिवेणी सहाय इंटर कॉलेज का मामला**

अमृत विचार : कस्बा आसफपुर स्थित शिक्षा का मंदिर त्रिवेणी सहाय इंटर कॉलेज अब अनुशासनहीनता और अव्यवस्था का अड्डा बनता जा रहा है। शिक्षकों की आपसी रंजिश और गुटबाजी इस कदर हावी हो चुकी है कि कॉलेज में न तो अनुशासन है और न ही पढ़ाई का माहौल। एक मामला शनिवार को सामने आया। जब दो शिक्षकों के बीच विवाद मारपीट में बदल किया।

मामला मामूली कहासुनी से शुरू हुआ था। जो हाथापाई में बदल किया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि चौकी से पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने दोनों शिक्षकों को समझाकर मामला रफा दफा कराया, लेकिन घटना से कॉलेज की अव्यवस्था उजागर हो गई है।

स्थानीय लोगों और अभिभावकों का कहना है कि कॉलेज में यह कोई नई बात नहीं है। शिक्षकों की आपसी तनातनी लंबे समय से चली आ रही है। गुटबाजी के चलते शिक्षक पढ़ाने के बजाय एक-दूसरे को नीचा दिखाने में व्यस्त रहते हैं। इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। कॉलेज समय में छात्र कक्षाओं में नजर नहीं आते। एक शिक्षक पर शराब पीकर कॉलेज आने का आरोप लगाया है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनोज गंगवार ने मामूली आपसी विवाद बताकर पुलिस की मध्यस्थता से सुलझाने की बात कही है।

यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता, बिसौली

अमृत विचार : यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज आक्रोशित है। रविवार को बिसौली में सवर्ण समाज के लोगों और राष्ट्रवादी प्रताप सेना के पदाधिकारियों ने आवाज उठाई। उन्होंने इस नियम को काला कानून बताते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राशि कृष्णा और सीओ सुनील कुमार को सौंपा।

पदाधिकारियों ने कहा कि देश में पहले से ही एससी-एसटी एक्ट लागू है। जिसका उपयोग अक्सर फर्जी मुकदमों के लिए किया जाता रहा है। भारत सरकार की विश्वसनीय संस्था एनसीआरबी खुद ऐसे फर्जी मुकदमों की पुष्टि करती रहती है। ऐसे में शिक्षा के केंद्रों में नए यूजीसी नियमों को लागू करना समझ से परे है। आरोप लगाया कि समाज में विभाजन पैदा करने के लिए जानबूझकर ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। जिसकी न तो किसी ने मांग की थी और न ही देश को इसकी आवश्यकता है। चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मुकेश ठाकुर, आलोक चौहान, शुभम सक्सेना, वंश शर्मा, रजत शर्मा, मुकेश भदौरिया, गुलशन मिश्रा, हितेश भदौरिया, अमित शर्मा, निखिल मिश्रा, दक्ष चौहान, राहुल सिंह, ओमपाल सिंह, दिनेश कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।

ज्ञापन देने के दौरान एसडीएम और सीओ से बात करते लोग। ● अमृत विचार

● **वक्ताओं ने कहा, बिल वापस न लेने पर किया जाएगा आंदोलन**

न्यूज ब्रीफ

हमला करने का एक आरोपी गिरफ्तार

बरखेड़ा, अमृत विचार : जमीन के विवाद में घर मेंघुसकर हमला करने के ममले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की। बता दें कि थाना क्षेत्र के गांव सिसैईया निवासी लालता प्रसाद ने बीते दिनों रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि गांव के दिलीप कुमार, जियालाल, देवदत्त, भूपेंद्र, डोरी लाल, नरेश, ईशवरी प्रसाद उसकी पुश्तैनी जगह पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। 29 जनवरी को आरोपियों ने इसी रंजिश में हमला कर उसके भाई तौलेराम की पिटाई कर दी। करोड़ चौकी इंचार्ज अवधेश कुमार ने बताया कि आरोपी देवदत्त को रविवार को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया।

ग्रामीण पर हमला करने की एफआईआर दर्ज

बीसलपुर, अमृत विचार : क्षेत्र के ग्राम दुगीपुर बड़गवां निवासी ओमप्रकाश ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 15 जनवरी की रात नौ बजे गांव के ही नन्हेलाल, भगवानदास, फरजीत और अखन ने उनके पुत्र रघुवीर को घेरकर पिटाई कर दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है।

दो पक्षों में लाठी-डंडे चले, मची भगदड़

तिलहर, अमृत विचार : बाईपास चौराहे पर रविवार को पिंक बूथ के पास दो पक्षों में नोंक-झोंक के बाद जमकर लाठी-डंडे चल गए। अचानक हुई मारपीट से चौराहे पर भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक लाठी डंडे चलते रहे। मारपीट के बाद दोनों पक्ष एक-दूसरे को देख लेने की धमकी देते हुए अपने-अपने स्थान की ओर चले गए। मिली जानकारी के अनुसार विवाद डग्गामार टेंपो संचालन को लेकर हुआ था। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि इस संबंध में अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

परामर्श केंद्र पर एक दंपती का हुआ समझौता

शाहजहांपुर, अमृत विचार : पुलिस लाइन में परिवार परामर्श केंद्र पर 5 पत्रावलियों की सुनवावाई की गयी, जिसमें 1 दंपती का समझौता हुआ। थाना रोजा एक दंपती जिनकी शादी लगभग 2 माह पूर्व हुई थी। महिला अपने मायके मे 20 दिन से रह रही थी। महिला का पति शराब पीकर मारपीट करता था तथा जेवर पहनने को नही दे रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के मध्य कहासुनी हो गयी थी। जिस कारण महिला मायके चली आयी थी। दोनों पक्षों को परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया और दोनों पक्षों की आपस में वार्ता कराई गई। दोनों पक्षों में समझौता हो गया।

सड़क हादसे में घायल बहजोई के एसएचओ की जान गई

बिसौली, अमृत विचार : फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के गांव मैथरा निवासी प्रदीप सिंह (48) पुत्र दुर्गपाल सिंह जिला संभल की कोतवाली बहजोई में एसएचओ पद पद पर तैनात थे। 28 जनवरी को कोतवाली बिसौली क्षेत्र के गांव सर्वा के पास छुट्टा पशु के चलते हुए हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। परिजनों ने उन्हें बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। रविवार को गांव मैथरा में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सांसद आदित्य यादव, संभल के एसएसपी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुरेंद्र यादव, संभल एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई, बिसौली एसएचओ राजेंद्र सिंह पुंडीर आदि उपस्थित रहे।

सरकारें देशवासियों को लड़ाने का कर रहीं काम

विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले स्वामी प्रसाद मौर्य

संवाददाता, पलिया कलां

अमृत विचार: रामलीला ग्राउंड में अपनी जनता पार्टी का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रविवार को संपन्न हुआ। सम्मेलन को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उस ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। किसान खेतों में यूरिया डालने के लिए परेशान हैं। गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है। छुट्टा जानवर बड़ी समस्या बने हैं। शारदा नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ किसानों को बर्बाद कर रही है। स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, जो हैं भी उन्हें मतदाता सूची बनाने में लगा दिया गया है। सरकार कभी हिंदू -मुस्लिम तो

कार्यक्रम में बोलते स्वामी प्रसाद मौर्य।

कभी हिंदू- हिंदू को लड़ाने का काम करती है।

उन्होंने प्रश्न खड़े करते हुए कहा कि क्या ऐसे देश विश्व गुरु बन सकेगा। उन्होंने कहा कि देश के नुमाइंदों को संत रविदास, कबीर दास, गुरु नानक आदि संतों से सीख लेनी चाहिए। वे सभी इंसानों को एक मानते थे। हिंदू -मुस्लिम तो एक बहाना है ,काम दोनों की आंख में धूल झोंक अपना उल्लू सीधा करना है। आज यहां की 80 करोड़ आबादी की जिंदगी किसी तरह रेंग रही है। संत रविदास कहते थे कि जब मन चंगा, तो कठौती में गंगा। उन्होंने शंकराचार्य पर भी निशाना साधा। कहा कि आज देश के अनेक मंदिरों में दलितों का प्रवेश नहीं हो पा रहा हैं, क्या वे हिंदू नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि शंकराचार्य जी बताएं कि योगी जी हिंदू हैं अथवा नहीं हैं। सभी को प्रदेश उपाध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह मौर्य, जिला ध्यक्ष दिलीप कुमार, सैयद मकसूद अली गुड्डू ,मोहन सिंह बैरागी, रामचंद्र मौर्य ,भगवती प्रसाद मौर्य, अखिलेश कुमार मौर्य आदि ने भी संबोधित किया। इस दौरान गोपीनाथ मौर्य, अभिलाषा मौर्य एड., आदित्य मौर्य, अमित मौर्य, विनय मौर्य, अजय मौर्य, सुनील भारती, जसपाल सिंह नागी, राम बसंत आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

माघ पूर्णिमा स्नान के साथ कल्पवासियों का कल्पवास हुआ पूर्ण

मिर्जापुर, अमृत विचार: मेला रामनगरिया के मुख्य स्नान पर्व माघ पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को गंगा स्नान के साथ ही हजारों कल्पवासियों का एक माह का कल्पवास पूर्ण हो गया। स्नान के बाद कल्पवासियों ने दान-पुण्य अर्जित किया और इसके साथ ही घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया।

ढाई घाट के गंगा तट पर एक माह से कल्पवास कर रहे हजारों साधु-संतों, सन्यासियों और गृहस्थ श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान कर पूजा-पाठ किया। शास्त्रों के अनुसार माघ मास में गंगा तट पर एक माह का कल्पवास करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कड़ाके की सर्दी के बीच ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और साधना को तपस्या के समान माना जाता है। ढाई घाट की गंगा रेती पर पूरे एक माह तक साधु-संतों के साथ गृहस्थ श्रद्धालुओं ने कल्पवास किया। माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ही सभी का कल्पवास पूर्ण हुआ। स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद श्रद्धालुओं ने दान-दक्षिणा देकर पुण्य अर्जित किया और अपने-अपने घरों की ओर प्रस्थान किया।

एसए जाफर के गजल संग्रह जज्बात के रंग हजार का किया विमोचन

कार्यालय संवाददाता, शाहजहांपुर

अमृत विचार : तौक़ीर आर्केड में विमोचन समारोह तथा काव्य गोष्ठी एवं मुशायरे का आयोजन किया गया। इस दौरान अलीगढ़ के मशहूर चित्रकार प्रो. एसए जाफर तौकीर सा के काव्य संग्रह जज्बात के रंग हज़ार का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम में कवियों एवं शायरों ने कविताओं, नज़्मों एवं ग़ज़लों के माध्यम से तारीफ बंटोरीं। कार्यक्रम का आग़ाज़ मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर पीके तोमर ने दीप प्रज्वलित कर किया। विशिष्ट अतिथि अशफाक उल्ला खां, डॉ. प्रभात शुक्ला, नरेंद्र सक्सेना, डॉ. अमीर सिंह एवं डॉ.आलोक सिंह ने जाफर को गजल संग्रह से प्रकाशन पर बधाई दी।

साहित्यिक संस्था इदराक व नज़र मेमोरियल सोसायटी ने एसए जाफर ''तौक़ीर सा'' को शाल व स्मृति चिह्न प्रदान किया। वहीं इदारा उफ़ुक़-ए-नौ संस्था के राशिद हुसैन राही व दर्पण सामाजिक संस्था के खलीक शौक ने जाफर को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह के साथ ''कला रत्न सम्मान'' दिया। तदोपरांत साहित्यकार कमलेश द्विवेदी एवं चित्रकार डॉ. ऊषा गर्ग ने

प्रो . एसए जाफर के गजल संग्रह जज्बात के रंग हजार का विमोचन करते अतिथि।

- **चित्रकार तौकीर की याद में हुआ साहित्यिक आयोजन**

तौक़ीर सा के ग़ज़ल संग्रह ''जज़्बात के रंग हज़ार'' की समीक्षा की। अध्यक्षता वरिष्ठ कवि एडवोकेट सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने की। कार्यक्रम के आयोजक डॉ. मोहम्मद कमर ने आमंत्रित कवियों शायरों का स्वागत किया। गोष्ठी का संचालन शायरा गुलिस्तां खान ने किया।कार्यक्रम में असगर यासिर, ख़लीक़ शौक़, अजय अवस्थी, शाहिद रज़ा, हमीद ख़िज़र, कमलेश द्विवेदी, ख़ालिद क़ैसर, फ़हीम बिस्मिल, अस्मत अली, वाजिद हुसैन वाजिद, उवैस शिफ़ा, फ़ैसल फ़ैज़, गुलिस्तां ख़ान, सबा नक़वी सबा, डॉ. शाइस्ता नसीम, मुनीब अहमद, रतीश गर्ग, सदफ़ ख़ान आदि गीत-गजलों पर वाहवाही लूटी। इस अवसर पर डॉ ऊषा गर्ग, अहसन'' जलील, दिनेश सिंह, उस्मान ख़ान, मोहम्मद रफी, मोहम्मद तैयब, अजय द्विवेदी, मोहम्मद हसन, ज़ुल्फ़िकार अहमद, रामनयन वर्मा, मुनीर अहमद, अरविंद शुक्ला, परवेज़ अहमद खां, हफ़ीज़ ख़ान, जावेद ख़ान, ज़ुल्फ़िकार, इमरानुद्दीन, ज़फ़र हसनैन, प्रमोद प्रमिल, सैयद क़मर, बलराम शर्मा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, अर्शियान अर्श, मुनीर अहमद, आरिफ खां आदि उपस्थित रहे।

माघ पूर्णिमा ढाईघाट पर उमड़ा आस्था का सैलाब

संवाददाता, मिर्जापुर

अमृत विचार: मेला रामनगरिया के मुख्य स्नान पर्व माघ पूर्णिमा के अवसर पर ढाई घाट स्थित गंगा तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पतित पावनी भागीरथी में लाखों श्रद्धालुओं ने हर-हर गंगे के जयघोष के साथ आस्था की डुबकी लगाई। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर हवन, पूजन, यज्ञ कर गरीबों को दान-दक्षिणा दी और मनौतियां मांगी।

रविवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा की कटरी क्षेत्र के ढाई घाट पर एक माह से चल रहे माघ मेला रामनगरिया के मुख्य स्नान पर्व पर अनुमान से कहीं अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। बीती रात से ही श्रद्धालु जीप, ट्रैक्टर-ट्राली, बग्गी, साइकिल, बाइक और पैदल गंगा तट की ओर

माघ पूर्णिमा पर ढाई घाट गंगा तट पर स्नान करते श्रद्धालु और मेले में उमड़ी भीड़।

रवाना हो गए थे। सूर्य की किरण फूटने से पहले ही स्नान-दान का क्रम शुरू हो गया, जो देर शाम तक चलता रहा। गंगा तट पर मौजूद पंडा-पुजारियों के अनुसार भारी संख्या में गंगा भक्तों ने स्नान के बाद हवन-पूजन किया। श्रद्धालुओं ने गंगा मैया का वस्त्र श्रृंगार किया, कन्या भोज कराया और गंगा घाटों पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। दान-दक्षिणा देकर श्रद्धालुओं ने पुण्य अर्जित किया। मेला क्षेत्र में संत महात्माओं के खटलों पर धार्मिक अनुष्ठान हुए और धर्म के ज्ञाता कथावाचकों ने भगवान की कथाओं का श्रवण कराया। गंगा के सभी घाटों पर दिनभर श्रद्धालुओं की भारी भीड़

- **लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई आस्था की डुबकी**
- **भीड़ में बिछड़े बच्चों और बुजुर्गों को खोया-पाया केंद्र से मिलाया**

बनी रही। मेला ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी मुस्तैद दिखाई दिए और गंगा घाटों पर भ्रमण कर श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने की नसीहत देते रहे। भीड़ अधिक होने के कारण दोपहर करीब एक बजे तक 84 बच्चे और बुजुर्ग अपनों से बिछड़ गए, जिन्हें खोया-पाया केंद्र की मदद से उनके परिजनों से मिलाया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी जलालाबाद अजय राय पुलिस फोर्स के साथ मेला क्षेत्र में व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद रखने में लगे रहे। माघ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर कई भक्तों ने अपने घरों में भी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का आयोजन किया।

लखनऊ में आयोजित महापंचायत में जाएंगे 50 कांग्रेसी

बदायूं, अमृत विचार : परशुराम चौक स्थित कार्यालय पर कांग्रेस जनों की बैठक हुई। लखनऊ में आयोजित होने वाली पार्टी की मनरेगा बचाओ महापंचायत में जाने की तैयारी को लेकर चर्चा की गई।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेटर ओमकार सिंह, मुन्ना लाल सागर, जितेंद्र कश्यप, असरार अहमद ने कहा कि 2 फरवरी को मनरेगा योजना के 20 साल पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय प्रांगण में मनरेगा बचाओ संग्राम की महापंचायत का आयोजन किया गया है। जिसमे मुख्य रूप से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सचिव धीरज गुर्जर रहेंगे। 50 कार्यकर्ता महापंचायत जाएंगे।

कोमलप्रीत बनीं डॉक्टर

परिजनों के साथ डॉ . कोमलप्रीत।

पुवायां, अमृत विचार: क्षेत्र के गांव गुटैया निवासी कोमलप्रीत जोशन ने डॉक्टर बनकर परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कोमलप्रीत ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर भारत में एफएमजीई परीक्षा उत्तीर्ण कर डॉक्टर बनने का सपना साकार किया है। गुटैया निवासी सुखदेव सिंह लाडी की पुत्री कोमलप्रीत जोशन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जनपद से ही ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पांच वर्षों तक मॉरीशस से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। विदेश में पढ़ाई के उपरांत भारत लौटकर उन्होंने एफएमजीई परीक्षा दी, जिसमें सफलता प्राप्त कर उन्होंने देश में डॉक्टरी करने की पात्रता हासिल की। क्षेत्रवासियों और शुभचिंतकों ने भी कोमलप्रीत की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाइयां दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

गांव वनगवां में गंदगी से बीमारी फैलाने का भय

संवाददाता, कुंवरगांव

अमृत विचार : विकास खंड सालारपुर के अंतर्गत गांव वनगवां में व्याप्त गंदगी स्वच्छ भारत मिशन अभियान को पलीता दिखा रही है। गांव में तैनात सफाई कर्मचारी कथित रूप से घर बैठकर वेतन ले रहा है। गांव में नियमित सफाई नहीं हो रही है। गांव के प्रधान की अनदेखी भी चर्चा का विषय है।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं और नालियां चोक है। जिससे मच्छरों व अन्य कीटों का प्रकोप बढ़ गया है। इसके चलते डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सफाई कर्मचारी की व्यवस्था कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही गांव में सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ग्रामीणों का आरोप

गांव में व्याप्त गंदगी।

- **गांव में तैनात सफाईकर्मी पर घर बैठे वेतन लेने का आरोप**

है कि जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ही गांव की यह दुर्दशा बनी हुई है। प्रशासन से मांग की है कि लापरवाह सफाई कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और गांव में नियमित सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों को गंदगी और बीमारियों से राहत मिल सके।

जीएम के निरीक्षण को लेकर स्टेशन पर सफाई व्यवस्था में तेजी

शाहजहांपुर, अमृत विचार : उत्तर रेलवे के जीएम अशोक कुमार निरीक्षण को लेकर शाहजहांपुर व रोजा रेलवे स्टेशन पर सफाई व्यवस्था को लेकर तैयारी जोर शोर पर चल रही है। स्टेशन परिसर में निर्माण कार्य में तेजी लायी गयी है। उत्तर रेलवे के जीएम अशोक कुमार फरवरी के दूसरे सप्ताह में शाहजहांपुर और रोजा स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा प्लेटफार्म एक पर और सर्कुलेटिंग एरिया में निर्माणाधीन कार्य में तेजी लायी गयी है। इधर प्लेटफार्म पर निर्माणधीन फुट ओवरब्रिज और स्वचालित सीढ़ियों में भी कार्य काफी तीव्र गति से हो रहा है। जीएम के निरीक्षण से प्लेटफार्म एक पर निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाए। इधर रोजा स्टेशन पर भी निरीक्षण को लेकर कार्य में तेजी लाई गयी है। यहां भी सफाई व्यवस्था आदि पर ध्यान दिया जा रहा है। इधर सीएचआई स्टेशन परिसर में गंदगी फैलाने वाले तीन लोगों पर 600 रुपये जुर्माना किया है।

चिकित्सा मिली, अब पुरानी पेंशन के लिए होगा आंदोलन

कार्यालय संवाददाता, शाहजहांपुर

अमृत विचार: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला बैठक एनआरएमयू कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष ऋषिकान्त पांडेय ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और अन्य परिषदीय कार्मिकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा की स्वीकृति शिक्षकों के लंबे संघर्ष का परिणाम है।

पांच सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री की ओर से कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा की गई थी, जो अब लागू हो रही है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि अब संघ को उम्मीद है कि इसी तरह पुरानी पेंशन की मांग भी स्वीकार की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन के नेतृत्व में निर्णायक आंदोलन किया जाएगा। बैठक में प्राथमिक शिक्षक संघ के चल रहे ब्लॉक स्तरीय निर्वाचन के अगले चरण की घोषणा भी की गई। 15 फरवरी 2026 को शेष 10 ब्लॉक इकाइयों और नगर इकाई के तीनों पदों के लिए नामांकन होगा। बैठक में संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय की उपस्थिति रहेगी। जिला बैठक का संचालन करते हुए डॉ. रत्नाकर दीक्षित ने विचार व्यक्त किए। बैठक में राजकुमार सिंह दद्दू, सचिन मिश्रा, विक्रांत मिश्रा, संदीप कुमार, अरविन्द शुक्ला, जितेंद्र कुमार सिंह, नवनीत तिवारी, दशरथ नंदन अवस्थी, अरविन्द वर्मा, सचिन कुमार मिश्रा, मनोज मलिक, अभिषेक गंगवार, शशांक शेखर बाजपेई, राजेश कुमार, संतोष कुमार, वेद वर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और शिक्षक उपस्थित रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत बसौमी विकास खण्ड आसफपुर बदायूँ

पत्रांक : मेमो/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान/सामग्री आपूर्ति सूचना/2025-26 दिनांक : 02.01.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत समस्त फर्मों के सामग्री आपूर्तिकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत बसौमी वि.खं. आसफपुर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्नलिखित कार्य कराया जाना है :-

क्र.सं.	कार्य	अनु. लागत
1.	ग्राम पंचायत में जनसेवा केन्द्र (CSC) की स्थापना का कार्य	प्राक्कलन अनुसार

उपरोक्त कार्य हेतु प्राक्कलन में दी गई सामग्री/उपकरण क्रय किये जाने है। ग्राम पंचायत में सामग्री/उपकरण की आपूर्ति करने हेतु सील बन्द निविदाएं ग्राम पंचायत कार्यालय में दिनांक 05.01.2026 तक आमंत्रित की जाती है। जो उक्त दिनांक को ग्राम पंचायत कार्यालय पर अपरान्ह 05:00 बजे खोली जायेंगी। प्राप्त निविदाओं में उल्लिखित दरों में वर्ष 2025-26 को कोई मूल प्रतिवर्तन नहीं होगा। प्रस्तुत निविदाओं में मानक के अनुसार ब्राण्डेड मार्का सामग्री की आपूर्ति का उल्लेख किया जायेगा। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

रूप किशोर-ग्राम प्रधान
अंकित कुमार-सचिव

कार्यालय उपजिलाधिकारी सहसवान, बदायूं

पत्रांक : 17/उ.जि.अ./आपूर्ति-2026
दिनांक : 23.01.2026

प्रेस विज्ञप्ति

मा. अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) बदायूं के न्यायालय से निर्णीत वाद संख्या 4/2011-2012 सरकार बनाम वीरेन्द्र सिंह, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी201212700177 अन्तर्गत धारा-essencial Act. उ.प्र. एवं निर्णीत वाद संख्या 1475/2017 सरकार बनाम टीकम सिंह, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी201712701475 अन्तर्गत धारा-6क, उ.प्र. आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2025 एवं मा. अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) महोदय बदायूं कि न्यायालय से निर्णीत वाद संख्या 18/2011-2012 सरकार बनाम वीरेन्द्र सिंह कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या डी201212700569 अन्तर्गत धारा- essencial Act. उ.प्र. आवश्यक वस्तु एवं खाद्य अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 03.10.2025 जो कि एक ही प्रकरण से सम्बन्धित है, में राज्य सरकार के पक्ष में जब्त 10 कुन्तल अखाद्य गेहूँ, चावल जो श्री सुबोध कुमार उचित दर विक्रेता नगर क्षेत्र सहसवान की सुपुर्दगी में है, को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया गया है, जिसकी सार्वजनिक नीलामी/निविदा हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति समक्ष नीलामी प्रक्रिया पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। निविदादाता को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु निम्न शर्ते पूर्ण की जानी है।

1. निविदादाता मण्डी समिति एवं व्यापार कर में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. निविदादाता को पंजीयन के समय बोली में भाग लेने के लिये 500/- रूपये की अर्नेस्ट मनी उपजिलाधिकारी सहसवान (बदायूं) के पक्ष में जमा करनी होगी तथा जिसके पक्ष में बोली/नीलामी छूटेगी जिसकी अर्नेस्ट मनी जमा कर ली जायेगी,शेष अर्नेस्ट मनी बोली/नीलामी में भाग लेने वाले निविदादाताओं को वापस कर दी जायेगी।
3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा बनायी गयी कमेटी के समक्ष बोली/नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

अत: उपरोक्त बोली/नीलामी में इच्छुक निविदादाता दिनांक 5.02.2026 समय अपरान्ह 02:00 बजे कृषि उत्पादन मण्डी समिति सहसवान में उपस्थित होकर नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते है।

उपजिलाधिकारी, सहसवान

कार-टैंपो की भिड़ंत में युवक की मौत

संवाददाता, सिंधौली/ पुवायां

अमृत विचार : पुवायां रोड पर तेज गति से जा रही कार ने टेपो को टक्कर मार दी। हादसे में टेपो सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजा, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। घायलों में दो की हालत गंभीर बताई गई है। उनका उपचार राजकीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

पुवायां के मोहल्ला तकिया निवासी रंजीत टेंपो चलाता है। रविवार की सुबह 7.30 बजे चालक रंजीत शाहजहांपुर से सवारियां लेकर पुवायां जा रहा था। पुवायां रोड पर कोरोकुइया गांव के सामने तेज गति से आ रही कार ने टैंपो को टक्कर मार दी, जिससे टैंपो में सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त टैंपो

टेंपो में मिथुन(26) निवासी बरौना थाना पुवायां, वीरपाल निवासी भटियुरा थाना पुवायां, रंजीत निवासी तकिया थाना पुवायां, सत्यम निवासी नगरिया बुजुर्ग थाना सिंधौली, अंकित निवासी चक ऊदम थाना पुवायां घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को पुवायां सीएचसी भेज दिया। जहां

- **पुवायां रोड पर तेज गति से आ रही कार ने मारी टक्कर**
- **कार छोड़कर चालक हो गया फरार, अन्य हादसे में दो घायल**

डाक्टर ने मिथुन को मृत घोषित कर दिया। चालक रंजीत और वीरपाल को मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया। अन्य घायलों का उपचार चल रहा है। चालक कार को मौके पर छोड़कर भाग गया। टेंपो और कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने कार और टैंपो को कब्जे में ले लिया। प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र सिंह ने बताया कि हादसे में मिथुन की मौत हो गयी है। चालक कार छोड़कर भाग गया है। उन्होंने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मिथुन की मौत से परिजनों का रो रोकर बुराहाल है।

व्यापारी की जेब काट एक लाख चुराए

कार्यालय संवाददाता, शाहजहांपुर

अमृत विचार: कार में सवार बदमाशों ने व्यापारी को सवारी के रुप में हथौड़ा चौराहे से बैठा लिया मोहम्मदी छोड़ने के लिए बैठा लिया। दो बदमाशों ने उसे बीच में बैठा लिया। बदमाशों ने उसकी जेब काटकर एक लाख रुपये निकाल लिए। बदमाशों ने मोहम्मदी रोड पर पिपरिया मोड़ पर उसे उतार दिया और कार से चंपत हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस ने चोरी में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के गांव बनजरिया निवासी व्यापारी आनंद तिवारी ने बताया कि पराली का बंडल बनाकर बेचने का धंधा करते है। शनिवार को वह तिलहर भुगतान के लिए

- **मोहम्मदी जाने के लिए बैठे थे चार लोगों ने जेब काट कर उड़ाए रुपये**

गए थे। उन्होंने एक लाख रुपये भुगतान लिया। वह रोडवेज बस से तिलहर से हथौड़ा चौराहे के लिए बेठे। रोडवेज से बस शाम को हथौड़ा चौराहे पर उतर गए। वह हथोड़ा चौराहे पर मोहम्मदी जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान उनके पास एक डिजायर कार आकर रुकी।

कार में चालक समेत चार लोग थे। कार में सवार लोगों ने व्यापारी से पूछा कि कहां जाओगे। व्यापारी ने कहा कि मोहम्मदी जाना है। कार में सवार लोगों ने व्यापारी को बीच में बैठा लिया। इस दौरान कार में सवार लोगों ने उनकी जेब काट ली और एक लाख रुपये निकाल लिए। कार में सवार लोगों ने पिपरिया मोड कार से उतार दिया। चालक कार लेकर मोहम्मदी की तरफ निकल गया।

उन्होंने डायल 112 को सूचना दी। सिपाहियों ने रोजा थाना को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और व्यापारी से जानकारी की। प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार ने बताया कि कार में सवार लोगों ने उसकी जेब काटकर एक लाख रुपये चुरा लिए है।

उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अज्ञात में कार सवार लोगों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। पुलिस ने चोरी में रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज, बरेली

पत्रांक : ध्वस्तीकरण/918-सी/2025-26
दिनांक : 31.01.2026

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय इण्टर कालेज, बरेली का वोकेशनल एजुकेशन भवन एवं काष्ट कला भवन जो जीण/शीर्ण एवं जर्जर हो चुके है, जिसका ध्वस्तीकरण/नीलामी शिक्षा निदेशक (मा.) उ.प्र. प्रयागराज की अनुमति पर किया जाना है। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि. बरेली द्वारा उक्त जर्जर भवनों के ध्वस्तीकरण सहित मलबे का न्यूनतम मूल्य रू. 5,39,130/- निर्धारित किया गया है। उक्त नीलामी/बोली दिनांक 10.02.2026 को अपरान्ह 02:00 बजे से राजकीय इण्टर कालेज, बरेली के सभागार में की जायेगी। इच्छुक ठेकेदार/व्यक्तियों को सूचना दी जाती है कि वे खुली नीलामी/बोली में प्रतिभाग कर सकते है। नीलामी हेतु शर्ते निम्नवत् है :-

01. न्यूनतम बोली अनुमानित लो.नि.वि. की धनराशि से कम पर नहीं होगी।
02. नीलामी में भाग लेने वाले क्रेता के पास आधार और PAN होना अनिवार्य है।
03. नीलामी में भाग लेने वाले क्रेता को जमानत के रूप में न्यूनतम रू. 26757/- नीलामी शुरू होने से पहले जमा करना होगा तभी नीलामी में भाग ले सकेगे।
04. नीलामी की अधिकतम बोलने वाले को क्रेता के रूप में अधिकृत माना जायेगा।
05. नीलामी के बाद अन्तिम नीलामी की धनराशि को क्रेता के द्वारा नगद उसी दिन कार्यालय में जमा करना होगा एवं मलबे को विद्यालय परिसर से उठा लेना होगा।
06. नीलामी के समय जो टैक्स, आयकर, स्टाम्प या अन्य जो भी हो क्रेता के द्वारा वहन किया जायेगा।
07. नीलामी के बाद जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण शासकीय भवन/मुख्य सड़क को ध्यान में रखते हुये सुरक्षा की दृष्टि से किया जायेगा। जर्जर भवनों का ध्वस्तीकरण छः दिन के अन्दर पूर्ण करना होगा। यदि किसी प्रकार क्षति होती है तो उसकी भरपाई क्रेता को करनी होगी।

प्रधानाचार्य
पी.एम. श्री राजकीय इन्टर कालेज
बरेली।

न्यूज ब्रीफ

जाली नेपाली और भारतीय मुद्रा के साथ 10 लोग गिरफ्तार

मोतिहारी। बिहार के पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी से 25 लाख 18 हजार 5 सौ की जाली नेपाली और भारतीय मुद्रा बरामद की गयी है। इस मामले में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भारत-नेपाल बार्डर क्षेत्र के रक्सौल में जाली मुद्रा के बड़े कारोबारी नेटवर्क का खुलासा किया है। सीमावर्ती क्षेत्र हरैया थाना की पुलिस और सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ने बड़ी कर्रवाई करते हुए 25 लाख की जाली नेपाली मुद्रा और 18,500 की जाली भारतीय मुद्रा के साथ 4 नेपाली नागरिकों समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है।

गांजा तस्करों के हमले में आबकारी कांस्टेबल की मौत

हैदराबाद। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में हाल में कथित रूप से गांजा तस्करों के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई 23 वर्षीय महिला आबकारी कांस्टेबल की यहां सरकारी निम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जी सौम्या को 23 जनवरी को गांजा तस्करों ने उस वक्त कार से टक्कर मार दी थी जब सौम्या ने कार को रुकने का इशारा किया था। टक्कर मारे जाने से सौम्या गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। सौम्या को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उन्हें ''निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज'' (निम्स) में स्थानांतरित कर दिया गया जहां शनिवार रात को उन्होंने दम तोड़ दिया।

रांची में अंतर्राज्यीय टर्मिनल पर छह बसें जलकर राख

रांची। रविवार दोपहर रांची के एक अंतरराज्यीय टर्मिनल पर लगी भीषण आग में वहां खड़ी कम से कम छह बसें जलकर नष्ट हो गईं। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि लोअर बाजार थाना क्षेत्र के खादगढ़ा में हुई इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि आग एक खराब बस में लगी और उसने जल्द बस के अगल बगल खड़ी अन्य गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। खादगढ़ा पुलिस चौकी के प्रभारी सुनील ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है क्योंकि आग लगने के समय किसी भी वाहन में कोई भी मौजूद नहीं था।

राकांपा राजग में बनी रहेगी, विलय की अटकलों पर बोले सुनील तटकरे

कहा-संगठन दिवंगत अजित पवार की विचारधारा और मार्ग पर आगे बढ़ेगा

मुंबई, एजेंसी

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य सुनील तटकरे ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी भाजपा नीत राजग का हिस्सा बनी रहेगी और संगठन दिवंगत अजित पवार द्वारा निर्धारित विचारधारा एवं मार्ग पर आगे बढ़ेगा। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब यह दावा किया जा रहा था कि राकांपा और राकांपा (शरदचंद्र पवार) के विलय की घोषणा की तारीख 12 फरवरी तय कर दी गई थी। राकांपा के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में तटकरे ने कहा कि लोग चाहे कुछ भी कहें, हमारा रुख स्पष्ट है। हम पार्टी और अजित दादा की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। हम इस रुख पर अडिग हैं। रायगड के सांसद ने कहा कि हम राजग के साथ हैं और राजग के साथ ही रहेंगे। अजित दादा ने यह निर्णय सोच-समझकर लिया था।

तटकरे ने कहा कि सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के साथ तालमेल का निर्णय अजित पवार के नेतृत्व में सामूहिक रूप से लिया गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने अजित पवार की सहमति के बिना कभी कोई राजनीतिक निर्णय नहीं लिया। अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की जल्दबाजी पर आलोचना का जिक्र करते हुए तटकरे ने कहा कि संविधान सभी को अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय महाराष्ट्र के हित में और राकांपा को मजबूत करने के लिए लिया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में स्थिरता और अजित पवार के विकसित राज्य के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए उनके शपथ लेने में कुछ भी गलत नहीं है।

मैं राकांपा अध्यक्ष नहीं, खबरें निराधार : पटेल

मुंबई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने रविवार को उन खबरों को निराधार बताया, जिनमें उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की बात कही गई थी। पटेल ने एक्स पर कहा कि मैंने राकांपा अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति के संबंध में मीडिया में प्रसारित हो रही कुछ खबरों पर गौर किया है। मैं पूरी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि ये खबरें पूरी तरह निराधार हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पटेल का यह बयान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार में की गई टिप्पणियों के बाद आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक संस्था है। इतना बड़ा फैसला हमारे वरिष्ठ नेतृत्व और विधायकों से परामर्श करने, हमारे समर्पित पार्टी पदाधिकारियों से बातचीत करने और हमारे सभी पार्टी सदस्यों की भावनाओं और सामूहिक इच्छा का सम्मान करने के बाद ही लिया जाएगा।

तटरक्षक बल राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत स्तंभ: राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की बहु-स्तरीय समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में उत्कृष्ट अंतर-सेवा समन्वय देखने को मिला। सिंह ने भारतीय तटरक्षक बल के 50वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि संवेदनशील समुद्री परिस्थितियों के दौरान बल ने त्वरित और सशक्त प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिमी तट पर निगरानी बढ़ाई और उच्च सतर्कता बनाए रखी।

रक्षा मंत्री ने तटरक्षक बल को भारत की समुद्री सीमाओं पर विश्वास की दीवार बताते हुए कहा कि आतंकवाद, तस्करी, समुद्री डकैती, नशीले पदार्थों की तस्करी और समुद्री प्रदूषण से निपटने में इसकी भूमिका निर्णायक रही है। उन्होंने कहा कि तटरक्षक बल राष्ट्रीय सुरक्षा का मजबूत स्तंभ हैं।

गुरु रविदास के नाम का हुआ आदमपुर हवाई अड्डे का नाम

- प्रधानमंत्री ने हलवारा हवाई अड्डे पर किया टर्मिनल का उद्घाटन
- औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद

जालंधर, एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, आदमपुर किया और लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर सिविल टर्मिनल भवन का ऑनलाइन तरीके से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी अपराह्न लगभग तीन बजकर 45 मिनट पर आदमपुर हवाई अड्डे पहुंचे। गुरु रविदास की 649वीं जयंती के मौके पर मोदी यहां डेरा सचखंड बल्लां भी गए। इस बीच, मोदी ने लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया, जिससे पंजाब में बुनियादी विमानन ढांचे को और बढ़ावा मिलेगा। रायकोट उपखंड के हलवारा स्थित भारतीय वायु सेना अड्डे पर विकसित इस टर्मिनल से क्षेत्र में हवाई संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होने और औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

हवाई अड्डे की टर्मिनल भवन परियोजना को पंजाब सरकार और भारतीय विमानन प्राधिकरण के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 54.67 करोड़ रुपये के परिव्यय से स्थापित किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापु, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य गणमान्य व्यक्ति लुधियाना के हलवारा हवाई अड्डे पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी के जालंधर दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर पर गोलीबारी

- पांच गोलियां चलाईं, पुलिस ने चार लोगों को हिरासत में लिया

मुंबई, एजेंसी

मुंबई के जुहू इलाके में फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के घर पर शनिवार देर रात हुई गोलीबारी के सिलसिले में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। इस संबंध में एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और अभी यह पता नहीं चल पाया है कि गोलीबारी के समय शेट्टी अपने घर पर थे या नहीं। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने रात करीब पौने एक बजे नौ मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर गोलीबारी की।

अधिकारी ने बताया कि कम से कम पांच गोलियां चलाई गईं, जिनमें से एक गोली इमारत में स्थित जिम के शीशे पर लगी। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद इमारत के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारी ने कहा कि किसी ने इमारत पर गोली चलाई। क्षेत्रीय पुलिस और अपराध शाखा की टीम मामले की जांच कर रही हैं।

अधिकारी ने कहा कि वारजे मालवाड़ी थाने के कर्मियों द्वारा चलाए गए एक अभियान के दौरान पुणे शहर के कारवेनगर और धायरी इलाकों से चार लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि जुहू पुलिस और अपराध शाखा की टीम मौके पर पहुंचीं तथा जांच शुरू कर दी। घटनाक्रम का पता लगाने के लिए पुलिस इमारत के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की पड़ताल कर रही है। साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान और बैलिस्टिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके पर पहुंची। निर्माता एवं निर्देशक शेट्टी गोलमाल, सिंघम और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।

पलामू में पति-पत्नी और बेटे की हत्या बहु-पोती गंभीर

रांची, एजेंसी: झारखंड के पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसडी गांव में पति-पत्नी और उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान विजय भुइयां, उनकी पत्नी और बेटे के रूप में हुई है। इस हमले में विजय भुइयां की बहु नीलू देवी और पोती ममता कुमारी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (एमएमसीएच) में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। घटनास्थल पांकी थाना से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित है। थाना प्रभारी रंजन ने बताया कि ग्रामीणों के माध्यम से पुलिस को तीन लोगों की हत्या की जानकारी मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई।

बलूचिस्तान में हुई हिंसा में भारत का हाथ नहीं पाकिस्तान के आरोप को निराधार बताया

- विदेश मंत्रालय ने कहा-ध्यान भटकाने का काम कर रहा पड़ोसी देश पाकिस्तान

नई दिल्ली, एजेंसी

भारत ने बलूचिस्तान प्रांत में शनिवार को हुई हिंसा में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता के पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें ''निराधार'' बताया और कहा कि ऐसा कहकर पाकिस्तान अपने आंतरिक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को ''बेतुके दावे'' करने की बजाय अपने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान द्वारा लगाए गए निराधार आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं, जो उसकी अपनी आंतरिक विफलताओं से ध्यान भटकाने की उसकी सामान्य रणनीति के अलावा और कुछ नहीं है। हर बार जब कोई हिंसक घटना होती है, तो ऐसे दावों को दोहराने की बजाय पाकिस्तान को अपने लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने पर ध्यान देना चाहिए। दमन, क्रूरता और मानवाधिकारों के उल्लंघन का उसका रिकॉर्ड जगजाहिर है।

यह बयान पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी द्वारा हमलों में भारत पर शामिल होने का आरोप लगाने के बाद आया है। भारत ने पाकिस्तान के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड और क्षेत्र में लंबे समय से चले आ रहे दमन को उजागर करके पलटवार किया।

बलूचिस्तान में 16 जगहों पर हुए हमले

गौरतलब है कि शनिवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कम से कम 16 जगहों पर हमले हुए। क्वेटा, ग्वादर, कल्लात, खारान, मस्तुंग, पसनी, दलबांदिन, नोशकी, बुलाइदा, टंप, मच और आसपास के इलाकों में विस्फोट और सशस्त्र हमलों की सूचना मिली। बलूचिस्तान में हुई हिंसा की जिम्मेदारी शनिवार को बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने ''ऑपरेशन हेरोफ फेज दो'' के हिस्से के रूप में ली। बीएलए के अनुसार दस घंटे की अवधि में 14 शहरों में हुए हमलों में सैन्य, प्रशासनिक और सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया।

हमलों में मारे गए थे 84 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी

बलूच समूह ने दावा किया कि हिंसा में 84 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, 18 को जिंदा पकड़ा गया, 30 सरकारी संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया या जब्त कर लिया गया और 23 दुश्मन वाहनों में आग लगा दी गई। बीएलए ने यह भी कहा कि उसने केंद्रीय सैन्य मुख्यालय सहित कई दुश्मन चौकियों पर नियंत्रण कर लिया, जिससे कई शहरों में आवाजाही प्रतिबंधित हो गई। सोशल मीडिया पर प्रसारित कई वीडियो में हमलों की पुष्टि हुई।

बजट पर प्रतिक्रियाएं

एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगी नई रफ्तार

केंद्रीय बजट 2026-27

- आईआईए लखनऊ में बजट देखने और चर्चा सत्र का हुआ आयोजन
- उद्योग जगत ने बताया भविष्योन्मुखी और विकास-संचालित बजट

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

लखनऊ में आम बजट पर चर्चा करते आईआईए के पदाधिकारी। • अमृत विचार

अमृत विचार: इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने रविवार को आईआईए भवन, लखनऊ में केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर चर्चा सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर आईआईए के पदाधिकारी, उद्योगपति, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और नीति विशेषज्ञ बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय बजट की प्रमुख घोषणाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इस मौके पर पर आईआईए के राष्ट्रीय सचिव प्रमित कुमार सिंह, डिविज़नल चेयरमैन (अयोध्या) कैप्टन राजेश कुमार तिवारी, लखनऊ चैप्टर चेयरमैन विकास खन्ना, एसके गुप्ता, अविरल कुमार, अक्षय कुमार सहित अनेक पदाधिकारी/उद्योगपति मौजूद रहे।

नॉन-पॉपुलिस्ट लेकिन ग्रोथ ओरिएंटेड बजट

आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 सभी क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था और एमएसएमईज के विकास के प्रति सरकार की मज़बूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बजट स्पष्ट रूप से भविष्योन्मुखी और विकास-संचालित है। इसके साथ उन्होंने बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और हाई-स्पीड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े आवंटन, साथ ही सूक्ष्म उद्योगों के लिए प्रस्तावित एसएमई ग्रोथ फंड, भारत के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को सशक्त करने के साथ एमएसएमई सेक्टर को सीधा लाभ देने की बात कही। उन्होंने इक्विटी स्पोर्ट, एसएमई ग्रोथ फंड, ट्रेड्स प्राप्तियों को एसेट-बैक्ड सिक्योरिटी के रूप में मान्यता, टियर-2 और टियर-3 शहरों पर फोकस, कॉर्पोरेट मित्र पहल और सेक्टर-स्पेसिफिक संरचनात्मक समर्थन को उत्साहजनक बताया।

हाई-टेक टूल रूम और जलमार्गों पर फोकस का स्वागत

आईआईए के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश अग्रवाल ने कहा कि हाई-प्रिसिजन कंपोनेंट्स के लिए हाई-टेक टूल रूम की स्थापना, चैंपियन एमएसएमईज का निर्माण और रेयर अर्थ मैग्नेट पर नए सिरे से फोकस, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में घरेलू क्षमताओं को काफी बढ़ाएगा। उन्होंने अगले पांच वर्षों में 22 नए जलमार्गों और कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं की घोषणा को दूरदर्शी कदम बताया।

एमएसएमई के लिए तत्काल उपायों की कमी

आईआईए के पूर्व अध्यक्ष वीके अग्रवाल ने बजट पर मिश्रित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए अपेक्षित स्तर का तात्कालिक समर्थन नहीं दिखता। कई घोषणाएं लंबी अवधि की हैं, जबकि वर्तमान चुनौतियों के समाधान के लिए एक-वर्षीय तत्काल उपायों की ज़रूरत थी।

जेम-ट्रेंड्स इंटीग्रेशन से सुधरेगी एमएसएमईज की लिक्विडिटी

आईआईए की बैंकिंग समिति के चेयरमैन केके अग्रवाल ने जेम को ट्रेड से जोड़ने की घोषणा को अहम सुधार बताया। वहीं उन्होंने कहा कि इससे एमएसएमईज की लिक्विडिटी समस्याएं कम होंगी, अधिक सरकारी संस्थान और पीएसयू ट्रेड्स के दायरे में आएंगे और पेमेंट साइकिल तेज़ होगी।

एफटीए अनुरूप कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर से स्वदेशीकरण को बढ़ावा

आईआईए की जीएसटी समिति के चेयरमैन कपिल वैश्य ने कहा कि तैयार माल के बजाय कंपोनेंट्स पर कस्टम ड्यूटी कम करना, हाल ही में घोषित ईयू-एफटीए के अनुरूप है। यह नीति लंबे समय में स्वदेशीकरण को मज़बूत करेगी और घरेलू वैल्यू एडिशन बढ़ाएगी।

चैंपियन एमएसएमईज और इंडस्ट्रियल प्रतिस्पर्धा पर ज़ोर

आईआईए के चेयरमैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियां, फाइनेंस और टैक्सेशन शशांक शेखर गुप्ता ने कहा कि बजट में इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग पर दिया गया है। एमएसएमईज को बढ़ावा देने की सरकार की यह मंशा को स्पष्ट करता है। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और प्रतिस्पर्धात्मकता दोनों को बल मिलेगा।

कैश फ्लो को मिलेगी मदद

सीए अशोक सेठ ने कहा कि टीडीएस और टीसीएस में कमी से कारोबारियों के हाथों में अधिक नकदी आएगी, जिससे कैश फ्लो मैनेजमेंट और व्यवसाय विस्तार में मदद मिलेगी।

बजट में हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल सहित कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। एमएसएमई, अवसंरचना, डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन और क्षेत्र-विशिष्ट प्रोत्साहनों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट खादी, हथकरघा एवं हस्तशिल्प को प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, गुणवत्ता सुधार, ब्रांडिंग और वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए एक पहल है। बुनकरों, ग्रामोद्योग, ओडीओपी उत्पादों और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। कपड़ा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एकीकृत इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें मशीनरी के लिए कैपिटल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और कॉमन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर के ज़रिए पारंपरिक क्लस्टर का मॉडर्नाइज़ेशन शामिल है। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना शुरू की गई है। - **डा. नीरज खन्ना**, अध्यक्ष हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच)-मुरादाबाद

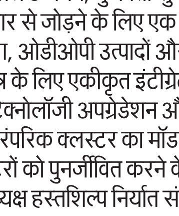

बजट में किसान, मजदूर, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। इतना दूरगामी बजट से आम आदमी को कोई लाभ पहुंचने वाला नहीं है। सरकार वर्ष 2047 के सापेक्ष यदि 2026-27 पर फोकस करते हुए बजट पेश करती तब लोगों का भला हो सकता था। - **अजय सागर**, जिलाध्यक्ष सपा-रामपुर

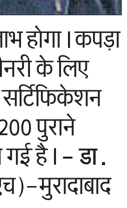

केंद्र सरकार का बजट ऊंट के मुंह में जीरे समान है, युवाओं, किसानों और सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट है। आम जनता को राहत देने वाला बजट होना चाहिए था।

-**मोहिब्बुल्लाह नदवी**, सांसद रामपुर

केन्द्रीय आम बजट

बजट सुधारों को अपनाया गया है

केंद्र सरकार का युवा शक्ति ड्राइवर बजट है जो कि गरीबों, वंचित और पिछड़ों पर ध्यान केंद्रित बजट है। चैंपियन एमएसएमई की कल्पना करते हुए त्रिपक्षीय दृष्टिकोण रखा गया है, जिसके अंतर्गत इक्विटी समर्थन जिसमें 10 करोड़ रुपये का फंड, व्यावसायिक सहायता एवं ट्रेंडस के माध्यम से तरलता सहायता के प्रावधान के साथ विनिर्माण क्षेत्र को अग्रिम क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु भारत सेमीकंडक्टर 2.0, टेक्सटाइल प्रमोशन, इलेक्ट्रॉनिक घटक योजना, किफायती रेल सामग्री योजना एवं उच्च मूल्य और तकनीकी रूप में उन्नत निर्माण और अवसंरचना उपकरणों के घरेलू उत्पादन को मजबूत करना सम्मिलित है। केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार के द्वारा बजट सुधारों को अपनाया गया है चाहे वह एनआरआई, निर्माण क्षेत्र या फिर घरेलू क्षेत्र को प्रोत्साहित करना ही क्यों ना हो। कुल मिलाकर यह बजट इस वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिवेशों को ध्यान में रखते हुए देश में सभी क्षेत्रों के आंतरिक विकास उन्नयन एवं संवर्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उद्योगों में वर्तमान की चुनौतियों को देखते हुए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किया जाना प्रशंसनीय है। यह बजट सरकार का कम राजकोषीय घाटे हेतु एक संतुलित बजट है।

-**डॉ. राहुल कुमार मिश्रा**, अर्थशास्त्र विभाग, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

'रेवड़ी संस्कृति' की जगह तकनीकी सशक्तीकरण पर दिया गया जोर

महिलाओं के लिए दो करोड़ रुपये तक के उद्यमिता ऋण और हर जिले में 'गर्ल्स हॉस्टल' के साथ-साथ, दिव्यांगजनों के लिए 'सहारा योजना' और 'दिव्यांगजन कौशल योजना' की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त, बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान के लिए जिला स्तर पर 'मेंटल हेल्थ केयर' केंद्रों के विस्तार और परामर्श सेवाओं को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। बुनियादी ढांचे में 12.2 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक निवेश, सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और रक्षा क्षेत्र में 'ड्रोन शक्ति 2.0' भारत को एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़े कदम हैं। शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक के 'बोलबाले' का साक्षी है। यह बजट 'रेवड़ी संस्कृति' के स्थान पर तकनीकी सशक्तिकरण, समावेशी शिक्षा और आधुनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से दीर्घकालिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। -**प्रो. अनामिका चौधरी**, अर्थशास्त्र विभाग। -**डॉ. शकुंतला मिश्रा** राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

पर्यावरण, पर्यटन और रोजगार केंद्रित बजट

बजट में व्यापक आर्थिक उद्देश्यों के रूप में स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन, सतत विकास और मध्यम मुद्रास्फीति को शामिल किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के संवर्धन, हरित ऊर्जा, बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने, प्रत्यक्ष कर संरचना के सरलीकरण और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे जैव-फार्मा, मत्स्य पालन और अन्य अनौपचारिक कृषि क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों पर दीर्घकाल में रोजगार सृजन और आय वृद्धि के दृष्टिकोण से विशेष बल दिया गया है। विनिर्माण क्षेत्र में उच्च और सतत विकास के लिए नए उपक्रमों तथा उपयुक्त बजट आवंटन की घोषणा की गई है, जैसे दुर्लभ खनिज खनन पर अनुसंधान, सेमीकंडक्टर मिशन, समर्पित रासायनिक पार्क, वस्त्रों के लिए एकीकृत कार्यक्रम तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु 10 हजार करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड दिया गया है। परमाणु ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने पर भी विशेष बल दिया गया है। -**प्रो. सनातन नायक**, अर्थशास्त्र विभाग, बाबा साहब आंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

आम आदमी के लिए खास नहीं उद्यमियों को तमाम सुविधाएं

एक कार्यालय में बजट देखते लोग। • अमृत विचार

कार्यालय संवाददाता, रामपुर

अमृत विचार : उद्यमियों सहित भाजपा नेताओं ने केंद्र सरकार का बजट दूरगामी बताया है, जबकि विपक्षी बजट को दमदार नहीं मान रहे हैं। केंद्र सरकार के 9वें आम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि विदेश यात्रा, कैंसर की 17 दवाओं समेत, लिथियम बैटरी, कपड़ा, सीएनजी, माइक्रोवेव ओवन को सस्ता किया है। जबकि खनिज, स्क्रैप और शराब महंगी हुई है। डिफाल्टर आयकर करदाताओं के लिए सजा नहीं, बल्कि जुर्माने का प्रावधान किया है। बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है जबकि, उद्यमियों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं।

बजट में व्यवसाय क्षेत्र के लिए राहत है। छोटे उद्यमियों के लिए उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत 10 लाख क्रेडिट कार्ड 5 लाख रुपये की सीमा तक जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की गई है। टीडीएस और टीसीएस दरों में राहत दी गई है। छोटे-मझोले आयकरदाताओं की सरलता के लिए आईटीआर रिवाइज की समय सीमा 31 मार्च कर दी गई है। किसान आस लगा रहे थे कि किसान सम्मान निधि की धनराशि बढ़ जाएगी जो पूरी नहीं हुई। हालांकि, आयात में टैरिफ 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग के 40 हजार करोड़ का प्रावधान व बायोगैस के दामों में कमी की गई है। चमड़ा, वस्त्र परिधान और लिथियम पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। बजट में आम आदमी के लिए कुछ खास नहीं है जबकि, उद्यमियों को तमाम सुविधाएं दी गई हैं। गृहणियों को भी कोई राहत नहीं है। गैस के दाम, गरम मसाले, आटा, दाल के भाव जस के तस हैं। पेश है सीए, उद्यमियों, नौकरीपेशा, किसानों और गृहणियों से हुई बातचीत के मुख्य अंश...

उद्यमीबोले बड़े उद्योगों पर टैक्स वृद्धि से व्यापार पर पड़ेगा असर: उप्र उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष अनिल अग्रवाल के आवास पर व्यापारियों ने बजट का लाइव प्रसारण देखा। व्यापारियों जिसमें बजट के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की इस बजट में सात हाई स्पीड ट्रेन, सड़क, पुल व ई बस के संचालन के लिए विशेष पैकेज दिया है। उप्र उद्योग व्यापार मंडल के जिला मंत्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि इस बजट में चिकित्सा के लिए अधिक धन की व्यवस्था रखी गई तथा 17 मुख्य गंभीर बीमारियों की दवाओं के मूल्य कम किए हैं। परंतु व्यापार मंडल की मांग थी कि पंजीकृत व्यापारियों को चिकित्सा बीमा मिले परंतु वित्त मंत्री ने निराश किया। किसानों को विशेष पैकेज देते हुए लोन की सीमा तीन लाख से बड़ा कर पांच लाख कर दी। साथ ही कोको, काजू और चंदन की लकड़ी की खेती को बढ़ावा दिया है।

जेफरी एपस्टीन फाइल : ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू से पूछताछ का बढ़ा दबाव

लंदन, एजेंसी

- पूर्व प्रिंस पर महिला ने लगाया है यौन संबंध बनाने का आरोप

ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर पर यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के अपराधों के स्तर की जांच कर रही अमेरिकी समिति के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने का दबाव बढ़ गया है। विंडसर की शाही स्थिति उनके भाई और ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने रद्द कर दी थी।

मामले में एक महिला ने आरोप लगाया है कि एपस्टीन उसे 2010 में तत्कालीन प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए ब्रिटेन ले गया था। महिला का दावा है कि वह विंडसर कैसल एस्टेट स्थित एंड्रयू के शाही निवास में गई थी। ब्रिटिश राजपरिवार के पूर्व सदस्य पर इस तरह का आरोप लगाने वाली यह दूसरी महिला है।

एंड्रयू लगातार आरोपों से इनकार करते रहे हैं। हालांकि, नवीनतम मामले में उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जापान की यात्रा पर गए ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने रविवार को इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि मैंने हमेशा एपस्टीन के कृत्यों से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता देते हुए मामले पर विचार किया है।

एपस्टीन के पत्राचार में मैक्रों का भी जिक्र

वाशिंगटन। जेफरी एपस्टीन ने कथित तौर पर अपने पत्राचार में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का जिक्र किया था, जो एक प्रतिशील एजेंडा को बढ़ावा देने की संभावनाओं में रुचि रखते थे। नए दस्तावेजों में रविवार को यह दावा किया गया। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा प्रकाशित एपस्टीन मामले में एक ई-मेल की कॉपी में यह कहा गया है। यह पत्र सितंबर 2018 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे को एक ऐसी ई-मेल से भेजा गया था।

चिकित्सकों ने तलाश ली घातक सल्फास विषाक्तता की काट

- चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों को मिली बड़ी सफलता

चंडीगढ़, एजेंसी

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं अनुसंधान (पीजीआईएमईआर) के चिकित्सकों ने एल्युमिनियम फॉस्फाइड (जिसे आमतौर पर सल्फास के नाम से जाना जाता है) नामक घातक कीटनाशक से होने वाली विषाक्तता के उपचार में एक बड़ी सफलता हासिल की है।

पीजीआईएमईआर ने एक बयान में बताया कि संस्थान के आंतरिक चिकित्सा विभाग द्वारा किये गए अनुसंधान में पहली बार प्रदर्शित किया गया कि सल्फास की विषाक्तता के इलाज में इंट्रावेनस लिपिड इमल्शन प्रभावी जीवन रक्षक तरीका है। बयान के मुताबिक इन महत्वपूर्ण निष्कर्षों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रिका यूरोपियन रिव्यू ऑफ मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेज में प्रकाशित किया गया है, जिससे इस अध्ययन को वैश्विक मान्यता मिली है। पीजीआईएमईआर के मुताबिक इन निष्कर्षों से स्पष्ट होता कि इस इलाज पद्धति को तुरंत इस्तेमाल करने से एल्युमिनियम फॉस्फाइड विषाक्तता के इलाज में अहम बदलाव आ सकता है। इसमें कहा गया है कि अध्ययन के परिणाम बेहद उत्साहजनक थे। जिन रोगियों को मानक चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त अंतःशिरा लिपिड इमल्शन दिया गया, उनमें मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई, साथ ही गंभीर चयापचय अम्लता का तेजी से सुधार हुआ, हेमोडायनामिक स्थिरता में सुधार हुआ तथा सदमे और हृदय संबंधी जटिलताओं से पीड़ित रोगियों सहित गंभीर रूप से बीमार रोगियों में बेहतर परिणाम प्राप्त हुए।

कम लागत में अब आसानी से मिलेगा उपचार

चिकित्सकों के मुताबिक इस नवीन उपचार का एक प्रमुख लाभ इसकी व्यावहारिकता है, क्योंकि इंट्रावेनस लिपिड इमल्शन सस्ता है, व्यापक रूप से उपलब्ध है, और पहले से ही भारत भर के अधिकांश अस्पतालों में, जिनमें जिला अस्पताल और परिधीय स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं, स्टॉक में मौजूद है। बयान में कहा गया है कि इसकी कम लागत और आसानी से उपलब्धता के कारण, इस चिकित्सा पद्धति में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाने की क्षमता है, जहां सेल्फ़ोस विषाक्तता का बोझ सबसे अधिक है और उन्नत गहन देखभाल तक पहुंच अक्सर सीमित होती है। संस्थान ने कहा कि कम लागत और आसानी से उपलब्धता के कारण, इस चिकित्सा पद्धति में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाने की क्षमता है, जहां सेल्फ़ोस विषाक्तता के मामले सबसे अधिक आते हैं और उन्नत गहन देखभाल तक पहुंच सीमित होती है।

गंभीर जन स्वास्थ्य के लिए था चुनौती

इसमें कहा गया कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड विषाक्तता एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में, जहां अनाज को संरक्षित रखने के लिए इस यौगिक का व्यापक इस्तेमाल होता है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए एक प्रभावी, किफायती और साक्ष्य-आधारित उपचार की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। बयान के अनुसार, यह अध्ययन पीजीआईएमईआर के आंतरिक चिकित्सा विभाग के डीन (अकादमिक), प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. संजय जैन के मार्गदर्शन में किया गया था।

वर्ल्ड ब्रीफ

सिंगापुर में हिंदुओं ने मनाया थाईपुसम

सिंगापुर। सिंगापुर के संस्कृति मंत्री दिनेश वासु दास ने यहां श्रद्धालुओं के साथ एक धार्मिक उत्सव में भाग लिया। मंत्री ने रविवार को थाईपुसम उत्सव में भाग लिया। उत्सव के तहत श्रीनिवास पेरुमल मंदिर से श्री थेंदायुतपानी मंदिर तक शोभायात्रा निकाली गई और इस दौरान श्रद्धालुओं ने 3.2 किलोमीटर तक यात्रा की। श्रद्धालु अपने साथ पालकुडम (दूध के पात्र) लिए हुए थे। हिंदू एंडोमेंटस बोर्ड (एचईबी) ने बताया कि शोभायात्रा शनिवार देर रात शुरू हुई और रविवार तक जारी रही। शोभायात्रा में सिंगापुर के संस्कृति, समुदाय और युवा एवं श्रमशक्ति मंत्री दिनेश वासु दास और उनकी पत्नी डॉ. रश्मीथा वेलाइथम भी शामिल थीं।

आइवरी कोस्ट में हादसे में 14 की मौत

अबिजान। आइवरी कोस्ट में शनिवार को एक सड़क हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह हादसा सुबह करीब पांच बजे कबाडूगू इलाके में हुआ और इसमें एक ट्रक शामिल था जो अनाज ले जा रहा था और जिसमें अवैध रूप से 69 यात्री सवार थे। परिवहन मंत्री अमादौ कोने ने कबाडूगू क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों को हादसे की शुरुआती जानकारी इकट्ठा करने के लिए तुरंत मौके पर जाने का निर्देश दिया है।

थाईलैंड में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू

बैंकॉक। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए पूर्व मतदान रविवार को शुरू हुआ जिसमें 20 लाख से ज्यादा पात्र मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, जो आठ फरवरी को आधिकारिक मतदान के दिन अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। मतदान शाम 5 बजे समाप्त होगा और आठ फरवरी के बाद सभी मतपत्रों की गिनती की जाएगी। चुनाव में पांच करोड़ से ज्यादा मतदाता कुल 500 सदस्य चुनेंगे।

एयर इंडिया की शंघाई दिल्ली उड़ान शुरू

बीजिंग। एयर इंडिया ने रविवार को शंघाई और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू की। इसी के साथ लगभग छह वर्षों के अंतराल के बाद दोनों शहरों के बीच विमानन कंपनी की सेवाएं फिर से बहाल हो गईं। शंघाई स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के मुताबिक, शंघाई और नई दिल्ली के बीच उड़ान शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुई। इस उड़ान में 230 से अधिक यात्री सवार थे। लगभग छह वर्षों के बाद एयर इंडिया की उड़ानों की बहाली, 2020 की शुरुआत में सेवाओं के निलंबन के बाद महत्वपूर्ण घटना माना जा रहा है।

अमेरिका ने युद्ध छेड़ा तो इस बार पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आएगा

ट्रंप की जंग की धमकी पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने दी चेतावनी

- खामेनेई ने दोहराया, ईरान पर हमलावरों को देंगे कड़ा जवाब

दुबई, एजेंसी

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी पर पलटवार करते हुए रविवार को चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने हमला किया, तो पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है। अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन और इससे जुड़े युद्धपोत फिलहाल अरब सागर में तैनात हैं, जिन्हें ट्रंप ने तेहरान में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद भेजा था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप सैन्य ताकत का उपयोग करेंगे या नहीं।

उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान बातचीत चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हल होते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि, खामेनेई ने राष्ट्रीय स्तर पर जारी विरोध प्रदर्शनों को तख्तापलट जैसा बताया और कहा कि इससे सरकार का रुख और कड़ा हो गया है। विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से लाखों लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। ईरान में राजद्रोह के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है। इससे यह चिंता फिर से बढ़ गई है कि तेहरान गिरफ्तार लोगों को सामूहिक रूप से फांसी दे सकता है। ईरान ने रविवार और सोमवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य अभ्यास करने की योजना भी बनाई है। होर्मुज जलडमरूमध्य से बड़ी मात्रा में दुनियाभर में तेल की ढुलाई होती है। खामेनेई ने कहा, अमेरिकियों को यह समझ लेना चाहिए कि यदि वे युद्ध शुरू करते हैं, तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। खामेनेई ने कहा, हम न तो उकसाने वाले हैं और न ही किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरान पर जो कोई भी हमला करेगा उसे ईरानी जनता कड़ा जवाब देगी।

ईयू सेनाओं को आतंकवादी समूह मानता है ईरान

दुबई। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने रविवार को कहा कि इस्लामी गणराज्य अब यूरोपीय संघ की सभी सेनाओं को आतंकवादी संगठन मानता है। उनका यह कड़ा बयान उस फैसले के बाद आया है, जिसमें यूरोपीय संघ ने देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई को लेकर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ द्वारा की गई यह घोषणा मुख्यतः प्रतीकात्मक मानी जा रही है। ईरान 2019 में पारित एक कानून के तहत पहले भी अमेरिका द्वारा रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में अन्य देशों की सेनाओं को आतंकवादी संगठन करार दे चुका है।

हालिया प्रदर्शन तख्तापलट जैसा

दुबई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने देशभर में जारी उन विरोध-प्रदर्शनों की तुलना एक तख्तापलट से की, जिनसे वहां की धार्मिक शासन व्यवस्था को चुनौती मिली है। ईरान के सर्वोच्च नेता 86 वर्षीय खामेनेई की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में कथित तौर पर हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईरान में राजद्रोह के आरोपों में मौत की सजा तक का प्रावधान है। ईरान में 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। शुरुआत में ईरानी मुद्रा रियाल के पतन के विरोध में हुए थे। जल्द ही ये खामेनेई शासन के लिए चुनौती बन गए।

फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम से पूछताछ

हैदराबाद। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) रविवार को बीआरएस की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान फोन टैपिंग से संबंधित एक मामले में तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष अपने आवास पर पूछताछ के लिए पेश हुए। पूछताछ से कुछ घंटे पहले, राव हैदराबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर येर्रावल्ली स्थित अपने फार्म हाउस से निकले और एसआईटी के सामने पेश होने के लिए नंदी नगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे। एसआईटी अधिकारियों का एक दल भी बीआरएस अध्यक्ष के आवास पहुंचा। राव के आवास के पास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और गली को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। केसीआर के नाम से चर्चित राव ने शनिवार को एसआईटी से कहा था कि वह एक फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होंगे। उन्होंने नोटिस जारी करने में जांच अधिकारी पर कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किए जाने का भी आरोप लगाया। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने रविवार को कांग्रेस सरकार द्वारा उनके नेता के राजनीतिक उत्पीड़न के विरोध में तेलंगाना में प्रदर्शन किया।

सरकारों के हाथ से निजी कंपनियों को जा रही सत्ता

- संरा महासचिव ने किया शांति, न्याय, सतत विकास का आह्वान

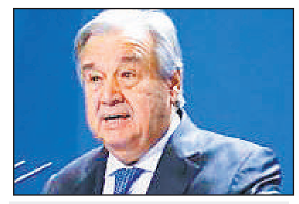

न्यूयॉर्क, एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच शांति, न्याय और सतत विकास के लिए नए प्रयासों का आह्वान किया है। गुटेरेस ने यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि दुनिया शायद हमारे समय के सबसे बड़े सत्ता हस्तांतरण से गुजर रही है। सत्ता सरकारों से निजी तकनीकी कंपनियों के हाथों में जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी, जब व्यवहार, चुनाव, बाजार और यहां तक कि संघर्षों को आकार देने वाली तकनीकें बिना किसी सुरक्षा घेरे के काम करती हैं, तो प्रतिक्रिया नवाचार नहीं, अस्थिरता होती है।

महासचिव ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष यानि 2026 की प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश करते हुए, कहा कि 2026 'अभी से निरंतर आश्चर्य और उथल-पुथल वाले वर्ष के रूप में आकार ले रहा है।' उन्होंने कहा कि अत्यधिक बदलाव के समय में वह उन सिद्धांतों की ओर लौटते हैं, जो बताते हैं कि ताकतें कैसे काम करती हैं। इसमें न्यूटन का तीसरा नियम भी है, जो कहता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गुटेरेस ने कहा, इस वर्ष की शुरुआत में, हम ऐसी कार्रवाइयों को चुनने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं जो ठोस और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करें। हमारे संकटपूर्ण समय में शांति, न्याय, जिम्मेदारी और प्रगति की प्रतिक्रियाएं। महासचिव ने चैन रिएक्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज जड़ न मिलने का भाव संघर्षों को बढ़ावा दे रहा है, अविश्वास गहरा रहा है और हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।

संरचनाएं पुरानी हो सकती हैं, मूल्य नहीं

संयुक्त राष्ट्र की ओर इशारा करते हुए गुटेरेस ने कहा कि संरचनाएं पुरानी हो सकती हैं, लेकिन मूल्य नहीं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर लिखने वाले लोग समझते थे कि हमारे संस्थापक दस्तावेजों में निहित मूल्य केवल ऊंचे विचार नहीं थे बल्कि व्यावहारिक शांति और न्याय के लिए अनिवार्य शर्तें थे।

तुर्किये में बस दुर्घटना में आठ लोगों की मौत

इस्तांबुल। तुर्किये के अंताल्या प्रांत में एक यात्री बस के सड़क से फिसलकर पलट जाने से इसमें सवार आठ लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकारी प्रसारक टीआरटी द्वारा प्रसारित तस्वीरों में बस डेमिरेल्टी जिले में एक राजमार्ग से फिसलकर पलटती दिखती है। प्रांतीय गवर्नर हुलुसी साहिन ने बताया कि इस दुर्घटना में 26 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। समाचार एजेंसी डीएचए के अनुसार, बस के पलटने के बाद कुछ यात्री इसमें से बाहर निकलने में सफल रहे। भूमध्य सागर के किनारे स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल अंताल्या में हाल के दिनों में भारी बारिश हुई है।

धोखाधड़ी में 36 भारतीयों सहित दो हजार गिरफ्तार

नोम पेन्ह, एजेंसी

- कंबोडिया में कैसिनो में छापामारी के दौरान की गई कार्रवाई

कंबोडिया में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ नवीनतम कार्रवाई के दौरान कुल 2,044 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 36 भारतीय भी शामिल हैं। यह जानकारी कंबोडियाई गृह मंत्रालय ने रविवार को दी। शनिवार को दक्षिणपूर्वी स्वे रींग प्रांत के बावेत शहर में 22 इमारतों वाले एक कैसिनो पर छापेमारी के दौरान आठ अलग-अलग देशों के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार कुल 2,044 विदेशी नागरिकों में 1,792 चीनी, 177 वियतनामी, 179 म्यांमारी, 30 नेपाली, पांच ताइवानी, एक मलेशियाई, दो लाओसी, 36 भारतीय और एक मैक्सिकन नागरिक हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता टच सोखाक ने कहा कि कंबोडियाई सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल अपराधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई में कभी ढील नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कंबोडिया अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं बल्कि नरक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू की है। पिछले सात महीनों में 23 देशों के कुल 5,106 धोखाधड़ी के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

इजराइल ने रफाह सीमा को प्रायोगिक तौर पर खोला

काहिरा। इजराइल ने फलस्तीनियों के सीमित आवागमन के मद्देनजर गाजा की मिस्र के साथ रफाह सीमा क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोलने की अनुमति दे दी है। इस घोषणा के बाद रफाह सीमा क्रॉसिंग पर रविवार को चहल-पहल देखी गई। रफाह सीमा क्रॉसिंग को दोबारा खोलना इजराइल-हमास संघर्षविराम के आगे बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इजराइल ने रविवार को घोषणा की कि रफाह क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोल दिया गया है। गाजा को मानवीय सहायता के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली इज़राइली सैन्य एजेंसी सीओजीएटी ने एक बयान में कहा कि क्रॉसिंग को पूर्ण संचालन के लिए सक्रिय रूप से तैयार किया जा रहा है।

ट्रंप का दावा, भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से खरीदेगा तेल

न्यूयॉर्क, एजेंसी

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा तेल के लिए चीन भी करार कर सकता है सौदा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने शनिवार को फ्लोरिडा के पाम बीच जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी इस सवाल के जवाब में की कि क्या चीन वेनेजुएला को दिए गए कर्ज की भरपाई तेल आपूर्ति के बदले कर पाएगा।

ट्रंप ने कहा कि चीन का स्वागत है और वह तेल के मामले में एक बड़ा सौदा कर सकता है। हम चीन का स्वागत करते हैं। हम पहले ही एक सौदा कर चुके हैं। भारत आ रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। हमने पहले ही यह सौदा कर लिया है, कम से कम इस सौदे की अवधारणा तो तय हो चुकी है। ट्रंप की इन टिप्पणियों पर नई दिल्ली की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत 2019 तक ईरानी तेल का एक प्रमुख खरीदार रहा है, लेकिन तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंध दोबारा लगाए जाने के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात में काफी कटौती कर दी थी।

ट्रंप के ये बयान ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों और इन देशों से कच्चा तेल न खरीदने को लेकर प्रमुख ऊर्जा आयातक देशों पर बनाए जा रहे दबाव की पृष्ठभूमि में आए हैं। हाल के वर्षों में भारत में रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, जिससे रूस भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगाया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद के कारण लगाया गया 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा एवं विस्तृत करने पर सहमति जताई।

आज का भविष्यफल -पं.मनोज कुमार द्विवेदी

आज की ग्रह स्थिति : 2 फरवरी, सोमवार 2026 संवत-2082, शक संवत 1947 मास-फाल्गुन, पक्ष-कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा 3 फरवरी 01.52 तक तत्पश्चात द्वितीया।

आज का पंचांग

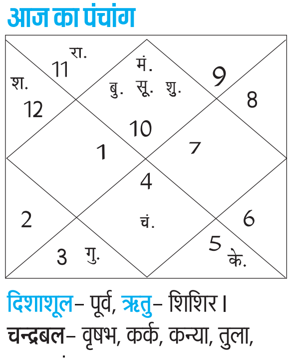

दिशाशूल- पूर्व, **ऋतु**- शिशिर।
चन्द्रबल- वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ।
ताराबल- अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद, रेवती।
नक्षत्र-अश्लेशा 22.47 तक तत्पश्चात मघा।

मेष आज आयात-निर्यात के कारोबार में तेजी आएगी। अधिकारी वर्ग आपकी अनदेखी कर सकते हैं। विरोधियों को हल्के में न लें। अपनी जीवनशैली को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। धार्मिक साहित्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है।

वृष आज तीर्थ यात्रा सुखद रहेगी। व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप अपनी योजनाओं को लेकर थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नए दोस्त बन सकते हैं। परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। धर्म-कर्म के प्रति विश्वास बनाए रखें।

मिथुन आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को प्रोफेशनल जीवन से अधिक महत्व देंगे। जीवनसाथी से अपने मन की बातें शेयर करने के लिए दिन उत्तम है। प्रेम संबंधों को लेकर परिवार में चर्चा हो सकती है। वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद रहेगा।

कर्क आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का दबाव रहेगा। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। आपके ऊपर काफी जिम्मेदारियां रहेंगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में उत्तम सफलता मिल सकती है।

सिंह आज दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। व्यवसाय में आपको कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। धन लाभ के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। विदेश से जॉब के अवसर मिलने की संभावना है। बुद्धिमान लोगों के बीच आपका दायरा मजबूत होगा।

कन्या आज दिन का शुरुआती भाग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप कुछ नया सीखने को लेकर प्रेरित हो सकते हैं। आपके ऊपर पुराने ऋण को चुकाने का दबाव हो सकता है। संपत्ति के क्रय-विक्रय से बेहतरीन लाभ मिलेगा। शाम को सिरदर्द की शिकायत होगी।

तुला आज इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का काम बढ़ने वाला है। गुप्त शत्रुओं की वजह से कार्यक्षेत्र में कुछ समस्या हो सकती है। रचनात्मक कार्यों में आप रुचि लेंगे। दूसरों के झगड़ों में मध्यस्थता न करें। ऑनलाइन कारोबार में आपको बड़ा लाभ होगा।

वृश्चिक आज आय के नए स्रोत विकसित होने के योग बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों का भरपूर आनंद लेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा।

धनु आज आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र की राजनीति के कारण आपको समस्या होगी। जॉब में आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है। अपने खर्चों को नियंत्रित रखने का प्रयास करें।

मकर आज शाम को आपके कुछ काम बिगड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके साथ अच्छा करें वही आपको महत्व न दें। नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। नजदीकी व्यक्तियों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे।

कुंभ आज फाइनेंस और लोन से जुड़े हुए अटके काम शुरू हो सकते हैं। नए कारोबार की शुरुआत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपकी इच्छाशक्ति आपके लिए विपरीत परिस्थितियों में ढाल के रूप में काम करेगी।

मीन आज सहकर्मियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। संपत्ति विवादों का समाधान निकल सकता है। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से बचें। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जॉब की चिंता हो सकती है। संतान की चिंता हो सकती है।

सुडोकू-49

सुडोकू एक तरह का तर्क वाला खेल है, जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। जब आप इस खेल को खेलना सीख जाते हैं तो यह बहुत ही सरलता से खेला जा सकता है। सुडोकू खेल में बॉक्स में 1 नंबर से 9 नंबर तक आने वाले अंक दिए हैं। इसमें कुछ बॉक्स खाली हैं, जिन्हें आपको भरना है। कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन तथा बॉक्स में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए।

			6				8	
	8	9			4			5
3			2			7		
	2			8	9			6
		7				3	9	
9				1			4	
		1			7			8
4			1			9	5	
	9				5			

सुडोकू - 48 का हल

7	6	5	9	3	1	2	4	8
9	4	3	6	2	8	1	5	7
8	2	1	5	7	4	3	9	6
5	9	6	8	1	3	7	2	4
3	7	4	2	5	9	8	6	1
1	8	2	7	4	6	9	3	5
4	3	7	1	6	2	5	8	9
6	1	9	3	8	5	4	7	2
2	5	8	4	9	7	6	1	3

> मुझे लगता है कि हमारी टीम को अलग-अलग तरह की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा। चेन्नई में हम तीन मैच खेलेंगे और हो सकता है कि वहां की पिच यहां की पिच की तुलना में अलग हो या फिर वैसी ही हो। और अगर ऐसा होता है, तो हमें पता है कि कैसे खेलना है।
> -मिचेल सैंटनर

स्टेडियम

बरेली, सोमवार, 2 फरवरी 2026

अमृत विचार
www.amritvichar.com

हाईलाइट

लवलीना, पूजा करेंगी भारतीय मुक्केबाजी टीम की अगुवाई

ला नुसिया (स्पेन)। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और ओलंपियन पूजा रानी मंगलवार को स्पेन के एलिकांटे के ला नुसिया में होने वाले बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 में भारत की 33 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम की अगुवाई करेंगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल के स्वर्ण पदक विजेता हितेश गुलिया और सचिन सिवाच भी इस टीम का हिस्सा हैं। निकहत ज़रीन (51 किग्रा) ने मार्च के आखिर में होने वाली एशियन चैंपियनशिप जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के रास्ते में एक अहम कदम है – की तैयारी पर ध्यान देने के लिए इस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है।

गुकेश ने नीमैन को बराबरी पर रोका

विक आन जी (नीदरलैंड्स)। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने टाटा स्टील मास्टर्स के 12वें चरण में रविवार को यहां हांस मोके नीमन के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि नोडिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने मैथियास ब्लूबाउम पर दमदार जीत दर्ज कर एकल बढ़त कायम करते हुए खिताब की ओर कदम बढ़ा दिया। जावोखिर सिंदारोव ने आर प्रज्ञानानंदा के खिलाफ कोई जोखिम नहीं लिया जिससे उन्हें ड्रॉ पर संतोष करना पड़ा। वह 7.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए। वह अपने हमवतन अब्दुसत्तोरोव से आधा अंक पीछे हैं। टूर्नामेंट में अब सिर्फ एक दौर का खेल बचा है और उज्बेकिस्तान के इन दोनों खिलाड़ियों ने शीर्ष दो स्थान के साथ साल के पहले सुपर-टूर्नामेंट में अपने देश का दबदबा कायम किया।

विदर्भ से हारकर यूपी रणजी ट्रॉफी से बाहर

नागपुर। गत चैंपियन विदर्भ ने रविवार को यहां उत्तर प्रदेश को चार विकेट से हराकर ग्रुप ए से आंध्र के साथ एलीट रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विदर्भ की टीम ग्रुप ए में आंध्र के बाद दूसरे स्थान पर रही। दोनों टीम ने सात मैच में समान 31 अंक हासिल किए लेकिन आंध्र की टीम बेहतर नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर रही। उत्तर प्रदेश के 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विदर्भ की टीम ने चौथे और अंतिम दिन चार विकेट पर 91 रन से आगे खेलते हुए छह विकेट गंवाकर 58.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज अमन मोखाडे 150 गेंद में 83 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके मारे।

देविका सिहाग ने जीता पहला सुपर 300 खिताब

बैंकॉक, एजेंसी

भारत की युवा शटलर देविका सिहाग ने रविवार को यहां 250,000 डॉलर इनामी थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के बीच से हट जाने के बाद अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीता।

हरियाणा की रहने वाली 20 वर्षीय खिलाड़ी देविका तब 21-8, 6-3 से आगे चल रही थी, जब विश्व में 68वें नंबर की खिलाड़ी और दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन गोह ने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इससे भारतीय खिलाड़ी अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीतने में सफल रही। उन्होंने कहा मैंने शुरुआत से ही अच्छी गति बनाने की योजना बनाई थी और वह कारगर रही। मेरा मानना है कि वह थकी हुई थीं और उन्हें ऐंठन भी थी। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। देविका इस जीत के साथ सुपर 300 महिला एकल खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं। इससे पहले यह उपलब्धि केवल पीवी सिंधू और साइना नेहवाल ने हासिल की थी। विश्व रैंकिंग में 63वें स्थान पर काबिज देविका बेंगलुरु के पादुकोण-द्रविड़ सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में कोच उमेंद्र राणा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके साथ ही वह इंडोनेशिया के रहने वाले कोच इरवानस्याह आदि प्रतामा की देखरेख में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु के साथ अपने खेल को निखार रही हैं। भारतीय खिलाड़ी क्रॉस कोर्ट और सीधे स्मैश लगाने की अपनी क्षमता और साथ ही बड़ी कुशलता से ड्रॉप शॉट लगाने से जल्द ही 9-2 से आगे हो गईं। इंटरवल तक उन्होंने 11-4 की बढ़त हासिल कर ली। गोह को देविका ने उन्हें कोर्ट पर खूब दौड़ाया।

प्रतिद्वंद्वी मलेशिया की गोह जिन वेई बीच से हटीं

देविका के लिए फाइनल शानदार रहा लेकिन उनकी प्रतिद्वंदी गोह को पीड़ा झेलनी पड़ी। वह फाइनल से पहले तीन गेम तक चले चार मैच खेलने के बाद थकी हुई लग रही थीं और उन्हें कोर्ट को कवर करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पिछले दो वर्षों से फॉर्म और फिटनेस के लिए संघर्ष कर रही गोह ने शनिवार को भी थकान की शिकायत की थी और उन्हें कोर्ट में चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी। उनका बायां पैर हिल नहीं पा रहा था और वह परेशान दिख रही थीं। देविका ने फाइनल में शानदार शुरुआत की। उन्होंने अपने दमदार रिटर्न और बेहतरीन स्ट्रोक के दम पर 4-0 की बढ़त बना ली। एक नेट कॉर्ड की बदौलत गोह ने अपना पहला अंक हासिल किया। बाद में उन्होंने मुकाबला बीच में छोड़ दिया।

> देविका ने चैंपियन बनने के बाद कहा आज मैं बेहद खुश हूं क्योंकि यह मेरा पहला सुपर 300 खिताब है। मैं भविष्य में और टूर्नामेंट खेलने को लेकर काफी उत्साहित हूं। उन्होंने कहा मैंने यहां बहुत अच्छे मुकाबले खेले। मैंने काफी कुछ सीखा है। यहां मिली सीख को मैं अपने खेल में लागू कर गलतियों को सुधारूंगी। मैच में उतरते समय मैंने जीत या हार के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपना 100 प्रतिशत देने पर ध्यान रखा। इससे मुझे आत्मविश्वास मिला।
> -देविका सिहाग

थाईलैंड मास्टर्स

कार्लोस अल्कारेज ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलियाई ओपन : करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने वाले बने सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी

मेलबर्न, एजेंसी

कार्लोस अल्कारेज रविवार को यहां फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम करके करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम- ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

रिकॉर्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रहे जोकोविच की मेलबर्न पार्क में फाइनल में यह पहली हार है। इससे पहले उन्होंने यहां अपने सभी 10 फाइनल में जीत दर्ज की थी। शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी अल्कारेज ने रविवार को पहला सेट गंवाया लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत हासिल की। जीत दर्ज करने के बाद कोर्ट से जाते हुए अल्कारेज ने टीवी कैमरा के लैंस पर हस्ताक्षर करते हुए लिखा, 'काम पूरा हुआ। चार में से चार पूरे हुए।'

बाइस साल के स्पेन के खिलाड़ी ने 38 साल के जोकोविच पर दबाव बनाए रखा। जीत पक्की करने के बाद अल्कारेज ने हाथ से रैकेट छोड़ दिया और वह पीठ के बल जमीन पर गिर गए और अपने हाथ सिर पर रख लिए। जोकोविच से हाथ मिलाने के लिए नेट पर जाने से पहले वह कुछ सेकेंड वहीं रुके। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ बातें कीं और जोकोविच स्पेन के खिलाड़ी को बधाई देते हुए मुस्कुराए। इसके बाद नया चैंपियन कोर्ट के एकतरफ लगी कुर्सियों पर बैठे अपने कोच को गले लगाने के लिए दौड़ा और बाद में स्टैंड में अपने पिता और टीम के दूसरे सदस्यों को भी गले लगा। पिछले सत्र के आखिर में अल्कारेज अपने पुराने कोच जुआन कार्लोस फरेरो से अलग हो गए थे और सैमुअल लोपेज उनकी कोचिंग टीम के प्रमख बने।

जोकोविच ने मजाक में कहा कि यह मुकाबला अगले 10 वर्षों के लिए अल्कारेज के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत करेगा। उन्होंने हालांकि बाद में कहा कि नए चैंपियन को आगे आने देना ही सही था। दोनों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पांच सेट में कड़ी जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों की तलाश में तीन घंटे से अधिक समय तक दोनों ने जबरदस्त फिटनेस, खेल और स्टेमिना का नजारा दिखाया। कोई भी खिलाड़ी बड़े अंकों पर हार मानने को तैयार नहीं था। स्पेन के खिलाड़ी ने 16 ब्रेक प्वाइंट में से पांच का फायदा उठाया जबकि जोकोविच छह ब्रेक प्वाइंट में से सिर्फ दो को ही अंक में बदल सके।

> कोई नहीं जानता कि मैं यह ट्रॉफी पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। मैंने इस पल का बहुत पीछा किया। हमने बस सही काम किया, आप मुझे हर दिन सही काम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मैं उन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं जो अभी मेरे साथ हैं।
> -कालोस अल्कारेज

> सबसे पहले एक शानदार टूर्नामेंट और शानदार दो हफ्तों के लिए बधाई। आप जो कर रहे हैं उसे बताने के लिए सबसे अच्छा शब्द ऐतिहासिक, दिग्गज है इसलिए बधाई। मैं आपके बाकी करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
> -नोवाक जोकोविच

- नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराया

करियर ग्रैंडस्लैम

जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम- ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम एकल खिताब का इंतजार बढ़ा

नोवाक जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम एकल खिताब जीतने के अभियान पर एक बार फिर अल्कारेज और यानिक सिनर में से एक ने रोक लगाई। इन दोनों ने मिलकर पिछले नौ ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में सिनर को हराया था और ओपन युगल में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनने की राह पर थे लेकिन अल्कारेज ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जोकोविच और स्पेन के रफेल नडाल ने कुछ जबरदस्त मैच खेले जिसमें 2012 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का अब तक का सबसे लंबा मैच भी शामिल है जो पांच सेट का फाइनल था और लगभग छह घंटे तक चला था।

अंडर-19 में शॉट लगाते वेदांत त्रिवेदी। एजेंसी

पाकिस्तान को हराकर भारत सेमीफाइनल में

बुलावायो, एजेंसी

अंडर-19 विश्वकप

- भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 252 रन
- पाक को सेमीफाइनल के लिए 33.3 ओवर में हासिल करना था लक्ष्य

वेदांत त्रिवेदी (68) की अर्धशतकीय पारी और निचलेक्रम के बल्लेबाजों की जुझारू पारियों के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने अंडर-19 विश्वकप के 36वें मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है।

भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रनों का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान 33.3 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच सकता था। जिसमें वह विफल रहा। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 के स्कोर पर समेट कर उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने समीर मिन्हास (नौ) का विकेट गंवा दिया। खिलन पटेल ने मिन्हास को पगबाधा आउटकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उस्मान खान और हम्जा जहूर ने पारी को संभाला और 88 के स्कोर तक ले गए।

17वें ओवर में आयुष म्हात्र ने उस्मान खान (66) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कप्तान फरहान यूसफ ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को 151 तक ले गये। पाकिस्तान 35.3 ओवरों तक पांच विकेट पर 168 रन ही बना सका।

भारत के खिलाफ टी-20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान

कराची, एजेंसी

- लेकिन टूर्नामेंट में भाग लेगा बांग्लादेश का ले रहा पक्ष

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने बहुप्रतीक्षित ग्रुप लीग मुकाबले के बहिष्कार के फैसले की रविवार को औपचारिक घोषणा कर दी, लेकिन सरकार ने सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के बाकी मैचों में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा कदम, जिसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना है।

सरकार के एक आधिकारिक बयान के माध्यम से दिए गए इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। विश्व निकाय ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहले कहा था कि वह इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी की समीक्षा करेगा, क्योंकि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में ''मैदान पर नहीं उतरेगी''। इस फैसले के साथ टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर चल रही अटकलों का दौर समाप्त हो गया है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहे इस टूर्नामेंट के बीच यह फैसला क्षेत्र में बढ़े राजनीतिक तनाव के माहौल में सामने आया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, " पाकिस्तान की सरकार आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागीदारी को मंजूरी देती है, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी।'' भारत-पाकिस्तान मुकाबला किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का सबसे बहुप्रतीक्षित मैच माना जाता है, जिसे वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दर्शक, प्रायोजकों की रुचि और प्रसारण राजस्व मिलता है। इस मुकाबले के बहिष्कार से आईसीसी के सामने लॉजिस्टिक और नियामकीय चुनौतियां खड़ी होने की आशंका है, क्योंकि टूर्नामेंट के कार्यक्रम, विपणन और व्यावसायिक रणनीति का बड़ा हिस्सा इसी मुकाबले के इर्द-गिर्द तैयार किया गया है।

वॉकओवर की स्थिति में भारत को पूरे अंक मिल जाएंगे। पाकिस्तान सात फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, इसके बाद 10 फरवरी को अमेरिका और 18 फरवरी को नामीबिया से भिड़ेगा।

नॉकआउट चरण की स्थित स्पष्ट नहीं

पीसीबी या सरकार ने हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगर प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आते हैं तो क्या रुख अपनाया जाएगा।

यूपी की कप्तान मेग लानिंग का विकेट लेने के बाद जश्न मनातीं शिनेल हेनरी।

दिल्ली कैपिटल्स एलिमिनेटर में

वडोदरा। दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को यहां यूपी वारियर्स को पांच विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर में जगह बनाई जहां उसकी भिड़ंत गुजरात जाइंट्स से होगी।

इससे पहले मारिजेन कैप की अगुआई में गेंदबाजों के प्रभावी प्रदर्शन से दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग में रविवार को यहां यूपी वारियर्स को आठ विकेट पर 122 रन के स्कोर पर रोक दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने 18.4 ओवर में पांच विकेट से जीत जीत हासिल कर ली। कैप, श्री चरणी और हेनरी की धारदार गेंदबाजी के सामने यूपी वारियर्स ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए और टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई।

बढ़ा मनोबल | न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखला में सर्वाधिक रन बना बनाकर विश्व कप के लिए जता दिए इरादे

बल्लेबाजी में कुछ बदलाव से फॉर्म में लौटे सूर्यकुमार

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका शृंखला के बाद मिले ब्रेक और बल्लेबाजी में किए गए कुछ बदलाव से उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मदद मिली। सूर्यकुमार ने शनिवार से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड पर भारत की 4-1 से जीत में आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए कुछ उम्दा पारियां खेली।

सूर्यकुमार पिछले साल रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। वह इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए थे लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करके न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखला में सर्वाधिक रन बनाए और उन्हें शृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शृंखला के बाद सूर्यकुमार ने आत्मचिंतन किया और अपने खेल में कुछ बदलाव किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार पारियों में वह केवल 34 रन बनाए थे, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 12 रन था। सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत की 46 रन से जीत के बाद कहा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शृंखला के बाद मुझे ब्रेक मिला। मैंने घर लौटने पर अपना किट बैग एक तरफ रखा और नौ-दस दिन तक आराम किया। उन्होंने कहा नए साल की शुरुआत से ही मैंने फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया और पिछले साल की कमियों पर विचार किया। विशेष रूप से शुरुआती ओवरों में मेरे स्ट्राइक रेट पर मैंने चिंतन किया। सूर्यकुमार ने कहा मैं 2021-23 में शुरुआती पांच-दस गेंदों पर आक्रामक बल्लेबाजी करता था और मेरा स्ट्राइक रेट 200-250 रहता था। अब मैं शुरुआती पांच-सात गेंदों पर संभलकर खेलता हूं और उसके बाद अपना स्ट्राइक रेट दोगुना कर लेता हूं। नागपुर में खेले गए पहले ही मैच से यह रणनीति कारगर साबित हुई, जिससे मुझे लय मिली और मेरी फॉर्म में सुधार हुआ।

भारत के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाजों में से एक सूर्यकुमार को कप्तानी संभालने के बाद से लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने 2025 में 21 मैचों में केवल 218 रन बनाए। उनका औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पांच मैचों में 80.66 के औसत और 196.74 के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए। भारत की निगाहें अब लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने पर हैं।

टीम संयोजन को बनाया गया है बेहतर

सूर्यकुमार ने कहा कि गेंदबाजी से समझौता किए बिना बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए टीम संयोजन को भी बेहतर बनाया गया है। उन्होंने अपने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा हर खिलाड़ी अपनी अनूठी पहचान लेकर आता है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, सभी राज्य और फ्रेंचाइजी स्तर पर अपनी शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करते हैं। मैंने उन्हें अपनी शैली पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। सूर्यकुमार ने कहा कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर-बल्लेबाज को लेकर अंतिम फैसला शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ विश्व कप के पहले मैच से पहले लिया जाएगा।